



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02072026-273965
CG-DL-E-02072026-273965

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 173]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 24, 2026/आषाढ 3, 1948

No. 173]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 24, 2026/ASHADHA 3, 1948

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जून, 2026

मामला सं.-एडी (ओआई)-20/2025

विषय: चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "4-(ब्रोमोमेथाइल)-2'-साइनोबिफेनिल", जिसे "ब्रोमो ओटीबीएन" के रूप में भी जाना जाता है, के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच।

फा. सं. 6/23/2025-डीजीटीआर.— समय-समय पर यथासंशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे यहां आगे "अधिनियम" भी कहा गया है) और समय समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "पाटनरोधी नियमावली" या "नियमावली" भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए;

क. पृष्ठभूमि

1. मैसर्स नियोजेन केमिकल्स लिमिटेड (जिसे इसके बाद "याचिकाकर्ता" या "आवेदक" भी कहा गया है) ने चीन जन.गण. (जिसे आगे "संबद्ध देश" भी कहा गया है) से "4-(ब्रोमोमेथाइल)-2 '-साइनोबिफेनिल", जिसे "ब्रोमो ओटीबीएन" के रूप में भी जाना जाता है (जिसे यहां आगे "संबद्ध सामान" या "विचाराधीन उत्पाद" या "पीयूसी" भी कहा गया है) के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के लिए समय-समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे यहां आगे "अधिनियम" भी कहा गया है) और समय-समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं की पहचान, मूल्यांकन और उन पर पाटनरोधी शुल्क का संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 (जिसे यहां आगे "पाटनरोधी नियमावली, 1995" या "पाटनरोधी नियमावली" या "नियमावली" भी कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे यहां आगे "प्राधिकारी" भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन-पत्र दायर किया है।
2. जबकि, प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर, चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के तथाकथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव निर्धारित करने और पाटनरोधी शुल्क की राशि, जो यदि लगाई जाए और घरेलू उद्योग को तथाकथित क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, की सिफारिश करने के लिए पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के अनुसार संबद्ध जांच शुरू करते हुए, भारत के राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 30 जून 2025 की अधिसूचना सं. 6/23/2025-डीजीटीआर जारी की।

ख. प्रक्रिया

3. संबद्ध जांच के संबंध में प्राधिकारी द्वारा नीचे वर्णित प्रक्रिया अपनाई गई है:
 - i. निर्दिष्ट प्राधिकारी को पाटनरोधी नियमावली के तहत, घरेलू उद्योग की ओर से आवेदक से एक लिखित आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के पाटन का आरोप लगाया गया था।
 - ii. प्राधिकारी ने उपरोक्त नियम 5 के उप-नियम (5) के अनुसार जांच शुरू करने की कार्यवाही से पूर्व पाटनरोधी आवेदन की प्राप्ति के संबंध में भारत में चीन जन.गण. के दूतावास को अधिसूचित किया।
 - iii. प्राधिकारी ने 30 जून 2025 को भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित एक सार्वजनिक सूचना जारी की, जिसमें संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू की गई।
 - iv. प्राधिकारी ने भारत में चीन जन.गण. के दूतावास, चीन जन.गण.के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों और आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए पते के अनुसार घरेलू उद्योग को जांच की शुरुआत की अधिसूचना की प्रति भेजी और उनसे अनुरोध किया कि वे नियम 6 (4) के अनुसार प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर लिखित रूप में अपने ज्ञात विचार दें।
 - v. प्राधिकारी ने चीन जन.गण. में निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को संगत सूचना प्राप्त करने के लिए निर्यातक प्रश्नावली भेजी, (जिनका विवरण आवेदक द्वारा उपलब्ध कराया गया था) और उन्हें पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 (2) के अनुसार लिखित रूप में अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया।
 - क) यानचेंग सिटी डोंगगांग
 - ख) झेजियांग हुआहाई फार्मास्युटिकल कंपनी लिमिटेड
 - ग) सिडिक कंपनी लिमिटेड

- घ) झेजियांग तियान्यू फार्मास्युटिकल कंपनी लिमिटेड
- ड.) सिनोलाइट इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड
- च) जियांगसू जीटीआईजी हुताई कंपनी लिमिटेड
- छ) लूना केमिकल्स कंपनी लिमिटेड
- vi. प्राधिकारी ने प्रस्तावित शुल्कों के आर्थिक प्रभाव के संबंध में इनपुट मांगते हुए हितबद्ध पक्षकारों को एक आर्थिक हित प्रश्नावली (जिसे इसके बाद 'ईआईक्यू' कहा गया है) भी जारी की।
- vii. संबद्ध जांच की शुरुआत के उत्तर में, संबद्ध देश के निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने प्रश्नावली उत्तर दायर करके उत्तर दिया है:
- क) नांतोंग हुआयू केमिकल टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड
- ख) लिनहाई हुआनान केमिकल कंपनी, लिमिटेड
- ग) झेजियांग हुआहाई फार्मास्युटिकल कंपनी, लिमिटेड।
- घ) झेजियांग तियान्यू फार्मास्युटिकल कं, लिमिटेड
- ड.) यानचेंग सिटी डोंगगेंग फार्मास्युटिकल डेवलपमेंट कं, लिमिटेड
- viii. प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध सामानों के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं/प्रयोक्ता एसोसिएशनों (जिनके नाम और पते आवेदक द्वारा प्राधिकारी को उपलब्ध कराए गए थे) को जांच शुरुआत अधिसूचना की एक प्रति भेजी और उन्हें नियमावली के नियम 6 (4) के अनुसार प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर लिखित रूप में अपने ज्ञात विचार देने की सलाह दी।
- क) वसुधा फार्मा केम लिमिटेड
- ख) सीटीएक्स लाइफसाइंसेज प्राइवेट लिमिटेड
- ग) सन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड
- घ) केपी मनीष ग्लोबल इंग्रीडिएंट्स प्राइवेट लिमिटेड
- ड.) लौरस लैब्स लिमिटेड
- च) मैकलियोड्स फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड
- छ) जेनसिंथ लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड
- ज) वर्डेट लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड
- झ) ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज लिमिटेड
- त्र) कैडिला हेल्थकेयर लिमिटेड
- ट) बीएलडी फार्माटिक (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
- ठ) बी के डी हेल्थ केयर
- ड) ग्रेन्यूल्स इंडिया लिमिटेड
- ढ) कोनार ऑर्गेनिक्स लिमिटेड

- ण) सिनर्जी रेमेडीज प्राइवेट लिमिटेड
- त) जुबिलेंट जेनेरिक्स लिमिटेड
- थ) माइलन लेबोरेटरीज लिमिटेड
- ix. वर्तमान जांच में किसी भी आयातक/प्रयोक्ता ने अपनी प्रश्नावली/कानूनी अनुरोध दायर नहीं किए हैं।
- x. चाइना चैंबर ऑफ कॉमर्स फॉर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ मेडिसिन्स एंड हेल्थ प्रोडक्ट्स (सी सी सी एम एच पी आई ई) ने कानूनी अनुरोध किए।
- xi. प्राधिकारी ने 30 जून 2025 की जांच शुरुआत अधिसूचना के पैरा 7 द्वारा 30 दिनों के भीतर हितबद्ध पक्षकारों से विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र और उत्पाद नियंत्रण संख्या (पीसीएन) पद्धति पर टिप्पणियां आमंत्रित की। प्राधिकारी ने 25 अगस्त 2025 के अपने पत्र के माध्यम से विचाराधीन उत्पाद का अंतिम क्षेत्र और पीसीएन पद्धति अधिसूचित की।
- xii. वर्तमान जांच के उद्देश्य से जांच की अवधि ("पीओआई") जनवरी 2024-दिसंबर 2024 (12 माह) है। क्षति की अवधि में अप्रैल 2021 से मार्च 2022, अप्रैल 2022 से मार्च 2023, अप्रैल 2023 से मार्च 2024 और जांच की अवधि शामिल है।
- xiii. आवेदक और अन्य हितबद्ध पक्षकारों से आवश्यक मानी गई सीमा तक और भी सूचना मांगी गई थी। घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों का सत्यापन जांच के उद्देश्य के लिए आवश्यक समझी गई सीमा तक किया गया था।
- xiv. क्षतिरहित कीमत (जिसे आगे "एनआईपी" कहा गया है) का निर्धारण भारत में संबद्ध सामानों के लिए नियोजित पूंजी पर उत्पादन लागत और उचित आय के आधार पर, सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) और पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध- III के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा दी गई सूचना के आधार पर निर्धारित की गई है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।
- xv. गोपनीयता के दावों की पर्याप्तता के संबंध में गोपनीय आधार पर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदान की गई सूचना की जांच की गई थी। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने जहां भी आवश्यक था, गोपनीयता के दावों को स्वीकार कर लिया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना गया है और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को इसका प्रकटन नहीं किया गया है। जहां भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर दायर की गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर प्रदान करने का निर्देश दिया गया था।
- xvi. प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराया। सभी हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची डीजीटीआर वेबसाइट पर अपलोड की गई थी, साथ ही उन सभी से अनुरोध किया गया था कि वे अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को अपने अनुरोधों के अगोपनीय रूपांतर को ईमेल करें।
- xvii. डीजी सिस्टम से अनुरोध किया गया था कि वे पिछले तीन वर्षों और जांच की अवधि के लिए संबद्ध सामानों के आयात के लेन-देन-वार विवरण उपलब्ध कराएं जो प्राधिकारी को प्राप्त हो गए थे। प्राधिकारी ने आयात की मात्रा की गणना और लेन-देन की उचित जांच के बाद इसके विश्लेषण के लिए डीजी सिस्टम आंकड़ों पर भरोसा किया है।
- xviii. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 (6) के अनुसार हितबद्ध पक्षकारों को मौखिक रूप से संगत सूचना प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करने के लिए 3 फरवरी, 2026 को एक मौखिक सुनवाई

आयोजित की। मौखिक सुनवाई के समय मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने वाले हितबद्ध पक्षकारों को मौखिक रूप से व्यक्त किए गए विचारों की लिखित अनुरोध दायर करने के लिए कहा गया था। हितबद्ध पक्षकारों को अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों के प्रति प्रत्युत्तर अनुरोध देने का अवसर प्रदान किया गया था। हितबद्ध पक्षकारों से अनुरोध किया गया था कि वे 10 फरवरी 2026 तक अपने लिखित अनुरोध और 17 फरवरी 2026 तक प्रत्युत्तर अनुरोध प्रस्तुत करें। किए गए अनुरोधों पर विधिवत विचार किया गया था और उन्हें उचित रूप से हल किया गया था।

- xix. प्राधिकारी ने जांच प्रक्रिया के दौरान आवेदक और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना की सटीकता के संबंध में स्वयं को संतुष्ट किया, जो यथासंभव सीमा तक और संगत तथा आवश्यक मानी गई सीमा तक इन जांच परिणामों का आधार बनती है।
- xx. प्राधिकारी ने साक्ष्य से समर्थित सीमा तक और वर्तमान जांच के लिए मानी गई सीमा तक इस स्तर पर सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना और उठाए गए तर्कों पर विचार किया है।
- xxi. प्राधिकारी द्वारा वर्तमान पाटनरोधी जांच से संबंधित मामले में विचाराधीन अनिवार्य तथ्य प्रकट करते हुए नियमावली के नियम 16 के अनुसार दिनांक 9 जून 2026 को एक प्रकटन विवरण जारी किया। प्राधिकारी ने इन अंतिम जांच परिणामों में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा की गई सभी प्रकटन पश्चात टिप्पणियों की संगत सीमा तक जांच की है। कोई भी अनुरोध जो केवल पूर्व अनुरोध की पुनरावृत्ति था और जिसकी प्राधिकारी द्वारा पहले ही जांच की जा चुकी है, संक्षिप्तता के लिए दोहराया नहीं गया है।
- xxii. जहां कहीं भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच के दौरान आवश्यक सूचना देने से इनकार किया है या अन्यथा प्रदान नहीं किए हैं, या जांच में अत्यधिक रूप से बाधा डाली है, प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपनी टिप्पणियों को दर्ज किया है।
- xxiii. *** इन अंतिम जांच परिणामों में किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई सूचना और पाटनरोधी नियमावली के तहत, प्राधिकारी द्वारा मानी गई सूचना दर्शाते हैं।
- xxiv. संबद्ध जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई विनिमय दर 1 अमेरिकी डॉलर = 84.58 रुपये है।

ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

ग.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

4. किसी भी हितबद्ध पक्षकार विचाराधीन उत्पाद के संबंध में कोई टिप्पणी प्रस्तुत नहीं की है।

ग.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

5. विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र और समान वस्तु के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- i) वर्तमान आवेदन-पत्र में विचाराधीन उत्पाद "4-(ब्रोमोमेथाइल)-2'-साइनोबिफेनिल" है जिसे "ब्रोमो ओटीबीएन" के रूप में भी जाना जाता है। ब्रोमो ओटीबीएन एक क्रीम/ऑफ व्हाइट कलर पाउडर है जिसका उपयोग कुछ फार्मास्युटिकल एपीआई के निर्माण में किया जाता है, मुख्य रूप से वालसार्टन, इरबेसार्टन और टेलमिसार्टन में। यह लोसार्टन, अज़िलसार्टन एस्टर और टेलमिसार्टन जैसी सार्टन वर्ग की औषधीय दवाओं के संश्लेषण में मध्यवर्ती के रूप में कार्य करता है। इसका उपयोग अन्य पायराजोलिन और संबंधित व्युत्पन्न के संश्लेषण में भी किया जाता है।
- ii) संबद्ध सामानों की रासायनिक संरचना में प्रत्येक बेंजीन रिंग पर प्रतिस्थापन के साथ एक केंद्रीय बाइफिनाइल कोर होता है। साइनो समूह (-सीएन) एक बेंजीन रिंग की 2 स्थिति पर स्थित होता है, जबकि ब्रोमोमिथाइल समूह (-सीएच₂बीआर) दूसरे बेंजीन रिंग की 4 स्थितियों पर स्थित होता है। यह व्यवस्था अणु को इसके अद्वितीय गुण और प्रतिक्रियाशीलता देती है।

- iii) संबद्ध सामानों को उपयुक्त तापमान पर उत्प्रेरक की उपस्थिति में उपयुक्त विलायक में 2-साइनो-4'-मिथाइल बाइफिनाइल (ओटीबीएन) ब्रोमिनेटिंग द्वारा तैयार किया जाता है। प्रतिक्रिया द्रव्यमान में हाइड्रोजन पेरोक्साइड (एच₂O₂) को जोड़कर आगे ब्रोमिनेशन पूरा किया जाता है। कार्य में सोडियम मेटाबिसल्फाइड (एसएमबीएस) द्वारा ब्रोमिन के निशान को हटाना और उसके बाद सोडियम बाइकार्बोनेट घोल का उपयोग करके तटस्थीकरण प्रक्रिया शामिल है। परिणामस्वरूप ठोस पदार्थ कार्बनिक परत को शुद्ध करके प्राप्त किया जाता है; जो आगे मेथनॉल के साथ क्रिस्टलीकरण पर शुद्ध उत्पाद देता है।
- iv) संबद्ध सामानों को सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के अध्याय 29 के तहत वर्गीकृत किया गया है। संबद्ध सामानों को कंपनी से कंपनी और देश से देश में विभिन्न कोडों के तहत आयात किया जाता है, और अधिकांश आयात शीर्ष 29269000, 29339990, 29332990, 29420090 और 29152990 के तहत हो रहे हैं। यह अनुरोध किया जाता है कि सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और किसी भी तरह से यह उत्पाद क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।
- v) घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध सामानों और संबद्ध देश से आयातित सामानों में कोई अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध सामान और संबद्ध देश से आयातित संबद्ध सामान भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, प्रकार्यों और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशों, वितरण और विपणन तथा सामानों के प्रशुल्क वर्गीकरण जैसी विशेषताओं के संदर्भ में तुलनीय हैं।

ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

6. जांच शुरुआत अधिसूचना में विचाराधीन उत्पाद निम्नलिखित रूप में परिभाषित है:

"वर्तमान मामले में विचाराधीन उत्पाद "4-(ब्रोमोमेथाइल)-2'-साइनोबिफिनाइल" (इसके बाद इसे "विचाराधीन उत्पाद" या "पीयूसी" कहा गया) है। घरेलू उद्योग द्वारा दायर आवेदन-पत्र में निहित सूचना के अनुसार, विचाराधीन उत्पाद को "ब्रोमो ओटीबीएन" के रूप में भी जाना जाता है। ब्रोमो ओटीबीएन एक क्रीम/ऑफ व्हाइट क्लर पाउडर है जिसका उपयोग मुख्य रूप से वालसार्टन, इरबेसार्टन और टेलमिसार्टन फार्मास्युटिकल एपीआई के निर्माण में किया जाता है।"

7. लोसार्टन, अज़िलसार्टन एस्टर और टेलमिसार्टन जैसी सार्टन वर्ग की औषधीय दवाओं के संश्लेषण में संबद्ध सामान मध्यवर्ती के रूप में कार्य करते हैं। इसका उपयोग अन्य पायराजोलिन और संबंधित व्युत्पन्नों के संश्लेषण में भी किया जाता है। इसके अलावा, हाल ही में रिपोर्ट किए गए अध्ययनों ने थर्मोडायनामिक अध्ययनों का उपयोग करके ईएसआई-एमएस/एमएस तकनीक और अन्य सॉल्वेंट्स का उपयोग करके टेलमिसार्टन में संभावित जीनोटॉक्सिक अशुद्धियों के निर्धारण में संबद्ध सामानों की भूमिका दर्शाई है।
8. संबद्ध सामानों की रासायनिक संरचना में प्रत्येक बेंजीन रिंग पर प्रतिस्थापन के साथ एक केंद्रीय बाइफिनाइल कोर होता है। साइनो समूह (-सीएन) एक बेंजीन रिंग की 2' स्थिति पर स्थित होता है, जबकि ब्रोमोमिथाइल समूह (-सीएच₂बीआर) दूसरे बेंजीन रिंग की 4' स्थितियों पर स्थित होता है। यह व्यवस्था अणु को इसके अद्वितीय गुण और प्रतिक्रियाशीलता देती है।
9. संबद्ध सामानों को सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के अध्याय 29 के तहत वर्गीकृत किया गया है। याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया है कि संबद्ध सामानों को विभिन्न एचएस कोड के तहत आयात किया जा रहा है और अधिकांश आयात शीर्ष 29269000, 29339990, 29332990, 29420090, 29152990 के तहत हो रहे हैं। हालांकि, यह नोट किया जाता है कि पाटनरोधी जांच में सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और किसी भी तरह से, यह उत्पाद के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है। हितबद्ध पक्षकारों को, जांच की शुरुआत सूचना के पैरा 7 के माध्यम से, जांच शुरू होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर उत्पाद के क्षेत्र और पीसीएन पद्धति के संबंध में अपनी

टिप्पणियां/सुझाव प्रस्तुत करने की सलाह दी गई थी। किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार ने विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र या पीसीएन पद्धति के संबंध में कोई टिप्पणी प्रस्तुत नहीं की है।

10. तदनुसार विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र वही रहता है जैसा कि जांच शुरुआत अधिसूचना में परिभाषित किया गया है। इसके अतिरिक्त, किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने कोई पीसीएन पद्धति का प्रस्ताव नहीं दिया। पीसीएन पद्धति पर किसी भी टिप्पणी के अभाव में, वर्तमान जांच के लिए कोई पीसीएन पद्धति नहीं अपनाई जा रही है।
11. समान वस्तु के संबंध में पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(घ) में निम्नलिखित प्रावधान है:
- “समान वस्तु” का अर्थ उस वस्तु से है जो भारत में पाटन के कारण जांच के अंतर्गत वस्तु के सभी प्रकार से समरूप या समान है अथवा ऐसी वस्तु के न होने पर अन्य वस्तु जोकि यद्यपि सभी प्रकार से समनुरूप नहीं है परंतु जांचाधीन वस्तुओं के अत्यधिक सदृश विशेषताएं रखती हैं;*
12. रिकॉर्ड में दी गई सूचना पर विचार करने के बाद, प्राधिकारी का मानना है कि संबद्ध देश निर्यातित विचाराधीन उत्पाद और भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद में कोई वास्तविक अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित विचाराधीन उत्पाद भौतिक विशेषताओं, उत्पादन प्रौद्योगिकी और विनिर्माण प्रक्रिया, प्रकार्यों और प्रयोगों, उत्पाद विनिर्देशों, वितरण और विपणन के संदर्भ में आयातित संबद्ध उत्पाद से तुलनीय हैं। दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। तदनुसार, प्राधिकारी निष्कर्ष निकालते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद नियमावली के नियम 2 (घ) के अनुसार संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद की 'समान वस्तु' है।

घ. घरेलू उद्योग का क्षेत्र और आधार

घ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

13. किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने घरेलू उद्योग के आधार के संबंध में कोई टिप्पणी प्रस्तुत नहीं की है।

घ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

14. घरेलू उद्योग और आधार के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध निम्नानुसार हैं:

- i. पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए आवेदन-पत्र मैसर्स नियोजन केमिकल्स लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदक के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, देश में संबद्ध सामानों के दो और उत्पादक हैं, अर्थात् एसवी लैम्स और सौरव केमिकल्स। तथापि, आवेदक का संबद्ध सामानों के भारतीय उत्पादन (50% से अधिक) का बड़ा हिस्सा है।
- ii. आवेदक ने न तो विचाराधीन उत्पाद का आयात किया है और न ही चीन जन.गण. में विचाराधीन उत्पाद के किसी भी उत्पादक/निर्यातक और न ही भारत में संबद्ध सामानों के किसी भी आयातक से संबद्ध है।
- iii. नियमावली के अनुसार आवेदक का उत्पादन कुल भारतीय उत्पादन का "एक बड़ा अनुपात" है। इस प्रकार, आवेदक नियम 2 (ख) के परीक्षण और नियम 5 की आधार अपेक्षाओं को पूरा करता है।

घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

15. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग निम्नलिखित रूप में परिभाषित है:

“(ख) “घरेलू उद्योग” का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके

आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में "घरेलू उद्योग" का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।"

16. वर्तमान मामले में आवेदन-पत्र मैसर्स नियोजन केमिकल्स लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदक के अनुसार, देश में संबद्ध सामानों के दो और उत्पादक हैं, अर्थात् एसवी लैब्स और सौरव केमिकल्स।
17. सौरव केमिकल्स (अब एससीएल लाइफसाइंसेज) ने दिनांक 30.01.2026 को एक ईमेल भेजा जिसमें कहा गया है कि वे घरेलू उद्योग द्वारा दायर आवेदन-पत्र का समर्थन करते हैं। तथापि, यह नोट किया जाता है कि न तो निर्धारित प्रारूप में सूचना दायर की गई थी और न ही पक्षकार ने पंजीकरण किया और जांच में भाग नहीं लिया।
18. रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना के अनुसार, अन्य घरेलू उत्पादक द्वारा दिए गए समर्थन की परवाह किए बिना कुल घरेलू उत्पादन में आवेदक की बड़ी हिस्सेदारी है और पाटनरोधी नियमावली के संदर्भ में कुल भारतीय उत्पादन का "एक प्रमुख अनुपात" है। निम्नलिखित तालिका आवेदक और अन्य उत्पादकों के हिस्से के बारे में विस्तार से बताती है:

उत्पादन	एमटी	% हिस्सा
आवेदक	***	***
अन्य उत्पादक :	***	***
एस वी लैब्स	***	***
सौरव केमिकल्स	***	***
कुल भारतीय उत्पादन	***	100

19. आवेदक ने यह भी अनुरोध किया है कि उसने न तो विचाराधीन उत्पाद का आयात किया है और न ही वह चीन जन.गण. में विचाराधीन उत्पादक के किसी उत्पादक/निर्यातक से संबद्ध है या भारत संबद्ध सामानों के किसी आयातक से संबद्ध है। उपरोक्त को देखते हुए, और उचित जांच के बाद, प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक नियम 2(ख) के अनुसार पात्र घरेलू उद्योग है और आवेदन-पत्र उपर्युक्त नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार आधार के मानदंडों को पूरा करता है।

ड. गोपनीयता संबंधी मुद्दे

ड.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

20. वर्तमान जांच के दौरान गोपनीयता के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोध और प्राधिकारी द्वारा संगत माने गए अनुरोध इस प्रकार हैं:
- याचिका में अत्यधिक गोपनीयता है। इसके अलावा, याचिका में मात्रा के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है।
 - घरेलू उद्योग ने भी उनकी लागत का पर्याप्त विवरण उपलब्ध नहीं कराया है।

ड.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

21. घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- i. उत्तरदाता निर्यातक निर्यातकों की प्रश्नावली के उत्तर का सार्थक सारांश प्रदान नहीं करके भारतीय कानून के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल रहे हैं। उन्होंने बिना किसी उचित औचित्य के अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है। इसके अतिरिक्त, उचित कारण बताए बिना गोपनीय रूपांतर में निहित सभी सूचना के लिए प्रश्नावली के उत्तर का अगोपनीय रूपांतर नहीं दिया गया है।
- ii. निर्यातकों के लिए यह अनिवार्य था कि वे कारणों का उचित विवरण दें कि गोपनीयता का दावा क्यों किया गया था और कुछ सूचना का सार संभव क्यों नहीं था।
- iii. निर्यातक न केवल सार्थक प्रतिक्रिया देने में विफल रहे हैं, बल्कि वे इस तरह की अत्यधिक गोपनीयता का दावा करने का कोई कारण देने में भी विफल रहे हैं। प्रतिक्रियाओं के साथ संलग्न परिशिष्टों में कोई सार्थक अगोपनीय प्रतिक्रिया नहीं होती है और कुछ मामलों में, वे या तो पूरी तरह से खाली होते हैं या प्रतिक्रिया के साथ संलग्न नहीं होते हैं।
- iv. कानून में आगे कहा गया है कि यदि प्राधिकारी को पता चलता है कि गोपनीयता के लिए अनुरोध आवश्यक नहीं है और यदि सूचना का आपूर्तिकर्ता या तो सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्यीकृत या संक्षिप्त रूप में इसके प्रकटीकरण को अधिकृत करने के लिए तैयार नहीं है, तो प्राधिकारी ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं। इसके अलावा, उत्तरदाता निर्यातकों द्वारा प्रश्नावली प्रतिक्रियाओं में बहुत कमी है और उनमें उठाए गए कई प्रश्नों का उत्तर नहीं देते हैं।

ड.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

22. प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना का अगोपनीय रूपांतर सभी हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराया।
22. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(7) के अनुसार विभिन्न पक्षकारों द्वारा प्रदान की गई सूचना का अगोपनीय रूपांतर सभी हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराया। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत सूचना की गोपनीयता के संबंध में, पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 में निम्नलिखित प्रावधान हैं:

“गोपनीय सूचना:

“(1) नियम 6 के उप नियमावली (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को अनुरोध किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना अनुरोध करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश अनुरोध करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण अनुरोध करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।”

24. सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई सूचना की गोपनीयता के दावों की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई। संतुष्ट होने पर, जहां भी आवश्यक था, प्राधिकारी ने गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना गया है और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया गया है। जहां भी संभव

हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर दायर सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर प्रदान करने का निर्देश दिया गया था। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि सभी हितबद्ध पक्षकारों ने अपने व्यवसाय से संबंधित संवेदनशील सूचना को गोपनीय होने का दावा किया है।

च. विविध मुद्दे

च.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

25. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध निम्नानुसार हैं:

- i. यह देखा गया है कि याचिकाकर्ता ने गौण स्रोतों से आयात आंकड़े प्राप्त किए हैं। यह अनुरोध किया जाता है कि गौण स्रोतों से प्राप्त आंकड़े प्रामाणिक और विश्वसनीय नहीं हैं। प्राधिकारी को जांच की शुरुआत के समय वर्तमान जांच में आयात की जांच के लिए डीजीसीआईएंडएस आंकड़ों को मंगाना चाहिए था। पूर्व में, प्राधिकारी ने हमेशा डीजीसीआईएंडएस से प्राप्त आंकड़ों पर भरोसा किया है न कि गौण स्रोतों पर।
- ii. घरेलू उद्योग द्वारा दायर याचिका में वित्तीय वर्ष 2021-22, जो क्षति की अवधि का आधार वर्ष है, के लिए, आयात की मात्रा और सीआईएफ कीमत जैसे महत्वपूर्ण आंकड़ा बिंदुओं के बारे में वास्तविक विसंगतियां और विरोधाभासी सूचना है,
- iii. डीजीटीआर ने क्षतिरहित कीमत (एनआईपी) निर्धारित करने के लिए नियोजित पूंजी पर आय (आरओसीई) 22% को लगातार अपनाया है, जो हम कहते हैं कि अत्यधिक, पुराना और पाटनरोधी नियमावली के तहत निर्धारित सिद्धांतों के साथ असंगत है। नियमावली के अनुबंध-III के पैरा 4 के अनुसार, नियोजित पूंजी पर "उचित आय" की अनुमति दी जानी चाहिए, न कि एक निश्चित या बढ़ी हुई पूंजी पर। वर्तमान पद्धति प्रचलित ब्याज और कर दरों के लिए उत्तरदायी नहीं है और क्षतिरहित कीमत को अनुचित रूप से बढ़ाती है, जिससे क्षति दर्शाई जाती है और घरेलू उद्योग को अनुचित संरक्षण मिलता है।

च.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

26. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध निम्नानुसार हैं:

- i. दवाओं और स्वास्थ्य उत्पादों के आयात और निर्यात के लिए चाइना चेंबर ऑफ कॉमर्स (सीसीसीएमएचपीआईई) को पाटनरोधी नियमावली के नियम 2 (ग) के अनुसार एक हितबद्ध पक्षकार के रूप में नहीं माना जा सकता है।
- ii. इस बात में कोई विवाद नहीं है कि सीसीसीएमएचपीआईई निश्चित रूप से उत्पादक, निर्यातक या आयातक की श्रेणी में नहीं आता है। अतः एसोसिएशन नियम 2 (ग) (i) के तहत बिजनेस एसोसिएशन के दर्जे का दावा कर सकता है। उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि केवल उस एसोसिएशन को "हितबद्ध पक्षकार" माना जा सकता है, जिसके अधिकांश सदस्य "ऐसी वस्तु" के उत्पादक, निर्यातक या आयातक हैं। अतः, एक एसोसिएशन को जांच में एक हितबद्ध पक्षकार के रूप में भाग लेने की अनुमति केवल तभी दी जा सकती है जब प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए यह साबित हो जाए कि ऐसी एसोसिएशन के अधिकांश सदस्य या तो आयातक हैं या संबद्ध सामानों के उत्पादक हैं। यह नोट करना व्यावहारिक है कि अधिसंख्य परीक्षण संबंधित एसोसिएशन की कुल सदस्यता के संदर्भ में लागू किया जाना है।
- iii. उक्त एसोसिएशन ने यह साबित करने के लिए कोई साक्ष्य भी नहीं दिया है कि वे ऊपर बताए गए नियम के संदर्भ में एक हितबद्ध पक्षकार के रूप में पात्र हैं। उन्होंने अपने सभी सदस्यों की पूरी सूची प्रस्तुत करने की भी जहमत नहीं उठाई ताकि माननीय प्राधिकारी को एक हितबद्ध पक्षकार के रूप में उनकी स्थिति का पता लगाने में सक्षम बनाया जा सके, इस तथ्य के बावजूद कि उत्तर देने वाली एसोसिएशन और साथ ही उनके कानूनी प्रतिनिधि पाटनरोधी नियमावली में निहित आवश्यकता से अच्छी तरह वाकिफ हैं।

- iv. आवेदक द्वारा भरोसा किए गए आयात आंकड़ों की विश्वसनीयता को चुनौती देने वाले हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध गलत हैं और अनावश्यक बातें कही गई हैं। यह स्पष्ट करना महत्वपूर्ण है कि प्राधिकारी द्वारा स्थापित परिपाटी और बार-बार स्पष्टीकरण के अनुसार, पाटनरोधी जांच में आवेदकों को अपने आवेदन-पत्र दायर करने के उद्देश्य से किसी भी स्रोत से आयात आंकड़े प्रदान करने की अनुमति है। तथापि, प्राधिकारी जो आंकड़े जांच शुरुआत करने और आगे की कार्यवाही के लिए प्रयोग करते हैं, उसे विधिवत रूप से वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) जैसे सरकारी आंकड़ों से प्राप्त किया जाता है, जो आयात आंकड़ों का आधिकारिक और विश्वसनीय भंडार है। यह आयात आंकड़ों की अखंडता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करता है जिस पर जांच आधारित होती है। इस प्रकार, केवल आवेदक द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों के स्रोत पर ध्यान केंद्रित करने वाली आपत्तियां इस प्रक्रियात्मक सुरक्षा की अनदेखी करती हैं और इन्हें खारिज कर दिया जाना चाहिए।
- v. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि क्षतिरहित कीमत की गणना के उद्देश्य से प्रयोग की जाने वाली पूंजी पर आय बढ़ा-चढ़ाकर पेश की गई है, यह अनुरोध किया जाता है कि ऐसे अनुरोध किसी ठोस तर्क या प्रस्तुति पर आधारित नहीं हैं। क्षतिरहित कीमत की गणना करते समय अनुमत 22% आय ऐतिहासिक रूप से सुसंगत आय है जिसे प्राधिकारी के साथ-साथ माननीय सेस्टैट द्वारा बार-बार पर्याप्त/उचित पाया गया है।

च.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

27. प्राधिकारी ने 17 फरवरी, 2026 के अपने प्रत्युत्तर में घरेलू उद्योग के इस अनुरोध की जांच की है कि सीसीसीएमएचपीआईईई एक हितबद्ध पक्षकार के रूप में माने जाने के लिए नियमावली के नियम 2 (ग) (i) में निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं करता है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि सीसीसीएमएचपीआईईई ने 2 सितंबर, 2025 को अपने शुरुआती अनुरोध में और बाद में लिखित अनुरोधों में, मई 1989 में स्थापित चीन में एक राष्ट्रीय व्यापार संघ के रूप में खुद को वर्णित किया है, जो चीन जनवादी गणराज्य के वाणिज्य मंत्रालय के तहत कार्य कर रहा है, जिसमें निर्माताओं, व्यापारिक कंपनियों और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में अनुसंधान और विकास सुविधाओं सहित 2,400 से अधिक कंपनियों की सदस्यता है।
28. प्राधिकारी ने 6 अगस्त, 2025 को हितबद्ध पक्षकारों की सूची प्रकाशित की, जिसमें सीसीसीएमएचपीआईईई को विशेष रूप से शामिल किया गया था और घरेलू उद्योग ने उस स्तर पर इस तरह के समावेश पर कोई आपत्ति नहीं जताई थी। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने 10 सितंबर, 2025 और 17 नवंबर, 2025 को अपने पत्र द्वारा सीसीसीएमएचपीआईईई के अनुरोधों की प्राप्ति को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया, और 3 फरवरी, 2026 को आयोजित मौखिक सुनवाई और 10 फरवरी, 2026 को अपने लिखित अनुरोधों सहित पूरी जांच के दौरान गुण-दोष के आधार पर ऐसे अनुरोधों में शामिल रहा, जिसमें भाग लेने के लिए सीसीसीएमएचपीआईईई की पात्रता को किसी भी समय कोई चुनौती नहीं दी गई। प्रत्युत्तर अनुरोधों में पहली बार आपत्ति उठाई गई है, जो सामान्य रूप से आगे के उत्तर के लिए परिचालित नहीं की गई हैं, जिसके परिणामस्वरूप सीसीसीएमएचपीआईईई को उत्तर देने का कोई प्रक्रियात्मक अवसर नहीं मिला है। घरेलू उद्योग बिना किसी आपत्ति के पहले से ही गुण-दोष पर सीसीसीएमएचपीआईईई के अनुरोधों के साथ जुड़ा हुआ था और इस मुद्दे पर घरेलू उद्योग की लंबी चुप्पी को उस अवधि के दौरान सीसीसीएमएचपीआईईई की भागीदारी की स्वीकृति के रूप में समझा जा सकता है।
29. प्राधिकारी का यह भी मानना है कि वर्तमान जांच में सीसीसीएमएचपीआईईई द्वारा दिए गए तर्क काफी हद तक चीन जन.गण. के सहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों द्वारा दिए गए तर्कों के समान हैं, जिन्होंने प्रश्नावली प्रतिक्रियाएं दायर की हैं, और किसी भी घटना में औचित्य के आधार पर विचार किया जाना चाहिए। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी सीसीसीएमएचपीआईईई की पात्रता के लिए विलंबित चुनौती को स्वीकार नहीं करते हैं, और औचित्य के आधार पर सीसीसीएमएचपीआईईई के अनुरोधों पर विचार किया है।

30. जहां तक आवेदक द्वारा भरोसा किए गए आयात आंकड़ों के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच शुरुआत के समय, आवेदक को पाटन, क्षति और कारणात्मक संपर्क के संबंध में प्राधिकारी को प्रथम दृष्टया संतुष्ट करना आवश्यक है। इस उद्देश्य के लिए, आवेदक गौण स्रोतों/बाजार सूचना से आंकड़े प्राप्त करता है। तथापि, जांच की शुरुआत के उद्देश्य और वर्तमान अंतिम जांच परिणामों के लिए, प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम से आधिकारिक आयात आंकड़ों पर भरोसा किया है।
31. घरेलू उद्योग के लिए क्षतिरहित कीमत की गणना के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए मुद्दों के संबंध में, प्राधिकारी ने अनुबंध-III के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर और प्राधिकारी सतत परिपाटी के अनुसार घरेलू उद्योग के लिए क्षतिरहित कीमत का निर्धारण किया है।

छ. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन

छ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

32. वर्तमान जांच के दौरान अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं और प्राधिकारी द्वारा संगत माने गए हैं:
- पाटनरोधी जांच के तहत एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था (एनएमई) के रूप में चीन जन.गण.का निरंतर व्यवहार 11 दिसंबर 2016 के बाद कानूनी आधार के बिना है, जिस तारीख को चीन के डब्ल्यूटीओ अधिगम नयाचार के अनुच्छेद 15 (क) (ii) की अवधि समाप्त हो गई थी। इस नयाचार के अनुसार, डब्ल्यूटीओ के सदस्यों को अधिकतम 15 वर्षों के लिए प्रतिनिधि देश पद्धति का उपयोग करने की अनुमति दी गई थी। वह अवधि समाप्त हो गई है, और ऐसी पद्धति अब डब्ल्यूटीओ कानून के असंगत है।
 - प्राधिकारी को चीनी उत्पादक/निर्यातक के सहयोग के लिए निर्मित सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए सहयोगी चीनी उत्पादक/निर्यातक के वास्तविक उपभोग मानदंडों को ध्यान में रखना चाहिए। चीनी उत्पादक/निर्यातक के वास्तविक उपभोग मानक को घरेलू उद्योग के उपभोग मानक के साथ प्रतिस्थापित करने के लिए कोई कानूनी औचित्य या आर्थिक तर्क नहीं है, जो अक्षम हो सकता है।
 - सहयोग करने वाले चीनी उत्पादकों/निर्यातकों ने इस जांच में प्राधिकारी के साथ पूरा सहयोग किया है और निर्धारित प्रारूप में और प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर एक पूर्ण प्रश्नावली प्रतिक्रिया प्रस्तुत की है। सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 9क (6क) के अनुसार, बनाए रखे गए रिकॉर्ड और सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा प्रदान की गई सूचना के आधार पर शुल्क की एक व्यक्तिगत दर निर्धारित की जानी चाहिए।

छ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

33. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध निम्नानुसार हैं:
- किसी भी निर्यातक ने बाजार अर्थव्यवस्था का स्तर का दावा करने के लिए अतिरिक्त प्रश्नावली दायर नहीं की है। तीसरे देश के निर्यात से संबंधित कोई विश्वसनीय और सत्यापित सूचना भी रिकॉर्ड में नहीं है। इस प्रकार, निर्यातकों के सामान्य मूल्य की गणना लागत-प्लस पद्धति के आधार पर की जानी चाहिए।
 - रिकॉर्ड पर आंकड़े काफी सकारात्मक पाटन मार्जिन दर्शाते हैं। इस प्रकार, प्राधिकारी से अनुरोध है कि कृपया घरेलू उद्योग के संरक्षण के लिए पाटनरोधी शुल्क लगाएं।
 - जहां तक इस अनुरोध का संबंध है कि चीन जन.गण.को बाजार अर्थव्यवस्था स्तर दिया जाना चाहिए, यह अनुरोध किया जाता है कि चीन जन.गण.को डीजीटीआर सहित दुनिया भर के विभिन्न प्राधिकारियों

द्वारा एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था देश के रूप में माना गया है। अनुबंध-1 के पैरा 8 में ऐसे देश के विरुद्ध एक धारणा है कि वह गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के आधार पर काम कर रहा है, बशर्ते कि उक्त देश के उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा इसका खंडन किया जाए। चूंकि किसी भी चीनी उत्पादक ने बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति के मूल्यांकन के लिए आवश्यक निर्धारित प्रारूप में अनुरोधित सूचना दायर नहीं की है, इसलिए अनुबंध-1 के पैरा 8 के तहत अनुमान के संदर्भ में, चीन जन.गण.को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में माना जाना चाहिए और तदनुसार सामान्य मूल्य नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार निर्धारित किए जाने की आवश्यकता है।

- iv. जहां तक चीनी उत्पादकों के सामान्य मूल्य के निर्माण के उद्देश्य से उनके वास्तविक उपभोग मानदंडों को ध्यान में रखने के अनुरोध का संबंध है, यह अनुरोध किया जाता है कि ऐसा अनुरोध प्राधिकारी द्वारा अपनाई जाने वाली परिपाटी के अनुरूप नहीं है।

छ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

छ.3.1 सामान्य मूल्य

34. धारा 9क(1)(ग) के तहत, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है:

(i) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमावली के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा

(ii) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा:-

(क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमावली के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो; अथवा

(ख) उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमावली के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उद्गम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत;

बशर्ते यदि उक्त वस्तु का आयात उद्गम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल यानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उद्गम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

35. डब्ल्यूटीओ में चीन के अभिगम नयाचार के अनुच्छेद 15 में निम्नलिखित प्रावधान है:

“जीएटीटी 1994 का अनुच्छेद VI, प्रशुल्क और व्यापार संबंधी सामान्य करार, 1994 (“पाटनरोधी करार”) के अनुच्छेद VI के कार्यान्वयन संबंधी करार और एससीएम करार एक डब्ल्यूटीओ सदस्य में चीन के मूल के आयातों की संलिप्तता की कार्यवाहियों में लागू होंगे जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

(क) जीएटीटी 1994 के अनुच्छेद -VI और पाटनरोधी करार के तहत कीमत तुलनात्मकता का निर्धारण करने में, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीन की कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे अथवा उस पद्धति का उपयोग करेंगे, जो निम्नलिखित नियमावली के आधार पर घरेलू कीमतों या चीन में लागतों के साथ सख्ती से तुलना करने पर आधारित नहीं है:

- (i) यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां रहती हैं तो निर्यात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य मूल्य की तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेगा।
- (ii) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उस पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त अनुपालन पर आधारित नहीं है, यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह नहीं दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग हैं।
- (iii) एससीएम समझौते के पैरा II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14(घ) में निर्धारित राजसहायता को बताते समय एससीएम समझौते के संगत प्रावधान लागू होंगे, तथापि, उसके प्रयोग करने में यदि विशेष कठिनाईयां हों, तो आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य राजसहायता लाभ की पहचान करने और उसको मापने के लिए तब पद्धति का उपयोग कर सकते हैं जिसमें उस संभावना को ध्यान में रखती है और चीन में प्रचलित निबंधन और शर्तें उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में सदैव उपलब्ध नहीं हो सकती है। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में, जहां व्यवहार्य हो, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य के द्वारा चीन से बाहर प्रचलित निबंधन और शर्तों का उपयोग के बारे में विचार करने से पूर्व ऐसी विद्यमान निबंधन और शर्तों को ठीक करना चाहिए।
- (iv) आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य उप-पैरा (क) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को पाटनरोधी कार्य समिति के लिए अधिसूचित करेगा तथा उप पैराग्राफ (ख) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को कमिटी ऑन सब्सिडीज और काउंटर वेलिंग मैसर्स के लिए अधिसूचित करेगा।
- (v) आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य को राष्ट्रीय कानून के तहत चीन ने एक बार यह सुनिश्चित कर लिया है कि यह एक बाजार अर्थव्यवस्था है, तो उप पैराग्राफ के प्रावधान (क) समाप्त कर दिए जाएंगे, बशर्ते आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में प्राप्ति की तारीख के अनुरूप बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड हो। किसी भी स्थिति में उप पैराग्राफ क (II) के प्रावधान प्राप्ति की तारीख के बाद 15 वर्षों में समाप्त होंगे। इसके अलावा, आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में चीन के द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां एक विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में प्रचलित हैं, उप पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए आगे लागू नहीं होंगे।"

36. प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन जन.गण. के अभिगम नयाचार अनुच्छेद 15 (क) (ii) के प्रावधान 11 दिसंबर, 2016 को समाप्त हो गए हैं, तथापि अभिगम नयाचार अनुच्छेद 15 (क) (i) के तहत दायित्व के साथ पठित पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 2.2.1.1 के तहत प्रावधान में बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार का दावा करने संबंधी पूरक प्रश्नावली में दिए जाने के लिए सूचना/आंकड़ों के माध्यम से संतुष्ट होने हेतु, पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध I के पैराग्राफ 8 में निर्धारित मानदंड अपेक्षित हैं।
37. जांच की शुरुआत के स्तर पर, प्राधिकारी ने बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक खर्चों और लाभों को विधिवत समायोजित करने के बाद घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत के सर्वोत्तम अनुमानों के आधार पर चीन जन.गण.के लिए सामान्य मूल्य का निर्माण किया है। जांच शुरू करने पर, प्राधिकारी ने चीन जन.गण. में उत्पादकों/निर्यातकों को जांच शुरुआत की सूचना का उत्तर देने और अपनी बाजार अर्थव्यवस्था के स्तर के निर्धारण के लिए संगत सूचना प्रदान करने की सलाह दी। प्राधिकारी ने नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8 (3) में निर्धारित मानदंडों के अनुसार गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की धारणा का खंडन करने और संगत विस्तृत सूचना देने के लिए सभी ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को पूरक प्रश्नावली की प्रतियां भेजीं।

38. प्राधिकारी चीन जन.गण. में उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य के निर्धारण के संबंध में नियमावली अनुबंध-1 के पैरा 7 और 8 के तहत निम्नलिखित प्रावधान नोट करते हैं:

"7. गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयात के मामले में, उचित लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए भारत में समान उत्पाद के लिए वास्तविक रूप से भुगतान किया गया अथवा भुगतान योग्य, आवश्यकतानुसार पूर्णतया समायोजित कीमत रहित, सामान्य, मूल्य का निर्धारण तीसरे देश के बाजार अर्थव्यवस्था में कीमत अथवा परिकल्पित मूल्य के आधार पर अथवा भारत सहित ऐसे किसी तीसरे देश से अन्य देशों के लिए कीमत अथवा जहां यह संभव नहीं है, या किसी अन्य उचित आधार पर किया जाएगा। संबद्ध देश के विकास के स्तर तथा संबद्ध उत्पाद को देखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा यथोचित पद्धति द्वारा एक समुचित बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश का चयन किया जाएगा और चयन के समय पर उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना पर यथोचित रूप से विचार किया जाएगा। बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी अन्य तीसरे देश के संबंध में किसी समयानुरूपी मामले में की जाने वाली जांच के मामले में जहां उचित हों, समय-सीमा के भीतर कार्रवाई की जाएगी। जांच से संबंधित पक्षकारों को किसी अनुचित विलंब के बिना बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के चयन के विशेष में सूचित किया जाएगा और अपनी टिप्पणियां देने के लिए एक समुचित समयावधि प्रदान की जाएगी।"

"8 (1) "गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश" वाक्यांश का अर्थ है कि ऐसा देश जिसे निर्दिष्ट प्राधिकारी लागत अथवा कीमत ढांचे के बाजार सिद्धान्तों को लागू नहीं करने वाले देश के रूप में मानते हैं, जिसके कारण ऐसे देश में पण्य वस्तुओं कि विक्रियों उप पैराग्राफ (3) में निर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार वस्तुओं के सही मूल्य को नहीं दर्शाती है।"

(2) यह कहना पूर्वनुमान लगाना होगा कि कोई देश जिसे जांच के पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान निर्दिष्ट प्राधिकारी अथवा डब्ल्यू .टी.ओ.के किसी सदस्य के समक्ष प्राधिकारी द्वारा पाटनरोधी जांच के प्रयोजनार्थ एक गैर- बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश निर्धारित अथवा माना गया है, एक गैर- बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश है। तथापि, गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश या ऐसे देश से संबंधित फर्म निर्दिष्ट-प्राधिकारी को सूचना तथा साक्ष्य उपलब्ध कराकर इस परिकल्पना को समाप्त कर सकते हैं जो यह साबित करता हो कि ऐसा देश उप पैरा (3) में निर्दिष्ट मानदंड के आधार पर एक गैर बाजार अर्थ-व्यवस्था वाला देश नहीं है।

(3) निर्दिष्ट प्राधिकारी प्रत्येक मामले में निम्नलिखित मानदंड पर विचार करेंगे कि क्या: (क) ऐसे देश में कच्ची समग्रियों प्रौद्योगिकी लागत और श्रम, उत्पादन, विक्रियों तथा निवेश सहित कीमतों, लागतों तथा निवेशों के संबंध में संबंधित फर्म का निर्णय आपूर्ति तथा मांग को दर्शाने वाले बाजार संकेतों तथा इस संबंध में किसी विशिष्ट राज्य हस्तक्षेप के बिना होता है और यह कि क्या मुख्य निवेशों की लागतें वास्तविक रूप से बाजार मूल्यों को दर्शाती है; (ख) ऐसी फर्मों की उत्पादन लागतों तथा वित्तीय स्थिति पूर्ववर्ती गैर- बाजार अर्थव्यवस्था प्रणाली से उठाये गये विशिष्ट विरूपणों के अधीन होती है, खासकर ऋणों की प्रतिपूर्ति द्वारा परिसम्पत्तियों के मूल्यहास, अन्य बट्टे खाते वस्तु विनियम व्यापार तथा ऋणों की क्षतिपूर्ति के जरिए तथा भुगतान के संबंध में; (ग) ऐसी फर्म दिवालियापन तथा सम्पत्ति कानून के अधीन होती है जो कि फर्मों के प्रचालन की कानूनी निश्चितता तथा स्थायित्व की गारंटी देता है; (घ) विनियम दर के परिवर्तन बाजार दर पर किये जाते हैं; बशर्ते, तथापि, जहां इस पैराग्राफ में निर्दिष्ट मानदंड के आधार पर लिखित रूप में पर्याप्त साक्ष्य दर्शाया जाता है कि पाटनरोधी जांच के अधीन एक अथवा ऐसी अधिक फर्मों के लिए बाजार स्थितियां लागू होती हैं, निर्दिष्ट प्राधिकारी पैरा 7 तथा इस पैरा में निर्दिष्ट सिद्धान्तों के पैरा 1 से 6 में निर्दिष्ट सिद्धान्तों को लागू कर सकते हैं।

(4) उप पैराग्राफ (2) में किसी बात के होते हुए भी, निर्दिष्ट प्राधिकारी जो संगत मापदंड के अद्यतन विस्तृत मूल्यांकन के आधार पर ऐसे देश को बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश मान सकते हैं जिसमें उप पैराग्राफ (3) में विनिर्दिष्ट मापदंड में किसी सार्वजनिक दस्तावेज में ऐसे मूल्यांकन का प्रकाशन शामिल हो, जिसे विश्व व्यापार संगठन के किसी सदस्य देश द्वारा पाटनरोधी जाँच के प्रयोजनार्थ बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माने जाने के लिए माना या निर्धारित किया हो”

39. जांच की शुरुआत के स्तर पर, प्राधिकारी ने चीन जन.गण. को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था देश के रूप में मानने की धारणा से कार्यवाही की। जांच शुरु करने पर, प्राधिकारी ने चीन जन.गण. में उत्पादकों/निर्यातकों को जांच शुरुआत की सूचना का उत्तर देने और इस बारे में सूचना देने की सलाह दी कि क्या उनके आंकड़े/सूचना को सामान्य मूल्य निर्धारण के लिए अपनाया जा सकता है। प्राधिकारी ने इस संबंध में संगत सूचना प्रदान करने के लिए चीन जन.गण. में सभी ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार/पूरक प्रश्नावली की प्रतियां भेजीं।
40. पैराग्राफ 7 गैर-बाजार अर्थव्यवस्था में उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य की गणना करने के लिए कई प्रशंसनीय तरीकों को निर्धारित करता है, जिसमें (क) बाजार अर्थव्यवस्था में मूल्य या निर्मित मूल्य के आधार पर तीसरे देश; (ख) ऐसे तीसरे देश से भारत सहित अन्य देश में कीमत; और (ग) किसी अन्य उचित आधार पर, जिसमें उचित लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए, यदि आवश्यक हो, विधिवत समायोजित किए गए समान उत्पाद के लिए भारत में वास्तव में प्रदत्त या देय कीमत शामिल है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पैराग्राफ 7 के तहत प्रदान किए गए विभिन्न क्रमिक विकल्पों को ध्यान में रखते हुए सामान्य मूल्य निर्धारित करने की आवश्यकता है।
41. आवेदन-पत्र दायर करने के स्तर पर, घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया था कि चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य का निर्माण भारत में वास्तव में देय कीमत के आधार पर किया जाना चाहिए, जिसमें भारत में उत्पादित होने वाली समान वस्तु के लिए उचित लाभ भी शामिल है।
42. पहले और दूसरे तरीकों के आधार पर सामान्य मूल्य पर विचार करने के लिए हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई सूचना/साक्ष्य प्रदान नहीं किया गया है। इसलिए, प्राधिकारी ने किसी अन्य उचित आधार पर तीसरे तरीके के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्माण करने का निर्णय लिया है। इसके तहत, भारत में वास्तव में प्रदत्त या देय कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया जा सकता है। इस उद्देश्य के लिए, प्राधिकारी ने बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय और लाभ को उचित रूप से जोड़कर घरेलू उद्योग की उत्पादन की इष्टतम लागत पर विचार किया है। इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में दिया गया है।

छ.3.2 निर्यात कीमत

43. चीन जन.गण. के निम्नलिखित उत्पादकों और निर्यातकों ने भाग लिया है और प्रश्नावली के उत्तर दायर किए हैं।
 - क) लिन्हाई हुआनान केमिकल कंपनी लिमिटेड, उत्पादक और निर्यातक
 - ख) नानटोंग हुआयु केमिकल टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड, निर्यातक
 - ग) झेजियांग हुआहाई फार्मास्युटिकल कंपनी लिमिटेड, निर्यातक
 - घ) झेजियांग तियानयु फार्मास्युटिकल कंपनी लिमिटेड, उत्पादक और निर्यातक
 - ड.) यानचेंग सिटी डोंगगांग फार्मास्युटिकल डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, उत्पादक और निर्यातक

यानचेंग सिटी डोंगगैंग फार्मास्युटिकल डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड ("डोंगगैंग")

44. यानचेंग सिटी डोंगगैंग फार्मास्युटिकल डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड ("डोंगगैंग") चीन जन.गण. में संबद्ध सामान की उत्पादक/निर्यातक है। डोंगगैंग ने निर्यातक के लिए निर्धारित प्रश्नावली के प्रारूप में आवश्यक सूचना दी है।
45. यह नोट किया जाता है कि जांच की अवधि के दौरान, डोंगगैंग ने भारत में सीधे ही असंबद्ध ग्राहकों को *** एमटी संबद्ध सामानों का निर्यात किया है। डोंगगैंग ने समुद्री माल-भाड़े, समुद्री बीमा, अंतर्देशीय मालभाड़ा, बंदरगाह और सार-संभाल खर्चों, क्रेडिट लागत और बैंक शुल्क के निमित्त समायोजन का दावा किया है, जिसे प्राधिकारी ने अनुमति दे दी है। डोंगगैंग के लिए निर्धारित की गई कारखानागत निर्यात कीमत नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में दी गई है।

झेजियांग तियान्यू फार्मास्युटिकल कं, लिमिटेड ("तियान्यू")

46. झेजियांग तियान्यू फार्मास्युटिकल कं. लिमिटेड चीन जन.गण., चीन जन.गण. में संबद्ध सामानों का निर्माता/निर्यातक है और उसने निर्धारित निर्यातक प्रश्नावली में संगत सूचना प्रदान की है।
47. जांच की अवधि के दौरान, झेजियांग तियान्यू फार्मास्युटिकल कंपनी, लिमिटेड, चीन जन.गण ने भारत में असंबद्ध खरीदारों को सीधे भारत को *** एमटी संबद्ध सामान बेचे हैं। उत्पादक/निर्यातक ने समुद्री मालभाड़ा, बीमा, अंतर्देशीय परिवहन, बंदरगाह और अन्य संबंधित खर्चों, ऋण लागत और बैंक शुल्कों के निमित्त समायोजन का दावा किया है, जिनकी प्राधिकारी द्वारा अनुमति दी गई है।

मैसर्स लिन्हाई हुआनान केमिकल कंपनी लिमिटेड, चीन जन.गण.

48. जांच की अवधि के दौरान, लिनहाई हुआनान केमिकल कंपनी, लिमिटेड, चीन जन.गण.ने दो संबद्ध निर्यातों/व्यापारियों नामतः नानटोंग हुआयू केमिकल टेक्नोलॉजी कंपनी, लिमिटेड और झेजियांग हुआहाई फार्मास्युटिकल कंपनी, लिमिटेड के माध्यम से कार्यगत आधार पर अप्रत्यक्ष रूप से भारत को ***एमटी संबद्ध सामानों की बिक्री की है।
49. लिनहाई हुआनान केमिकल कं, लिमिटेड, चीन जन.गण. ने नानटोंग हुआयू केमिकल टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड को *** एमटी बेचा है, और बाकी मात्रा *** एमटी को झेजियांग हुआहाई फार्मास्युटिकल कं, लिमिटेड को बेच दिया गया है।
50. लिनहाई हुआनान केमिकल कंपनी लिमिटेड, चीन जन.गण. द्वारा नानटोंग हुआयू केमिकल टेक्नोलॉजी कंपनी, लिमिटेड को बेचे गए संबद्ध सामानों के *** एमटी को नानटोंग हुआयू केमिकल टेक्नोलॉजी कंपनी, लिमिटेड द्वारा झेजियांग हुआहाई फार्मास्युटिकल कंपनी, लिमिटेड को फिर से बेचा गया है।
51. यह भी नोट किया जाता है कि भारत को निर्यात किए गए संबद्ध सामानों में से *** एमटी में से झेजियांग हुआहाई फार्मास्युटिकल कंपनी लिमिटेड, जो संबद्ध सामानों का अंतिम निर्यातक/व्यापारी है, ने भारत में सीधे असंबद्ध खरीदारों को संबद्ध सामानों का *** एमटी बेचा है और शेष *** एमटी को अप्रत्यक्ष रूप से भारत को चार असंबद्ध गैर-प्रतिभागी निर्यातकों/व्यापारियों के माध्यम से बेचा गया है, अर्थात् हांगजो डॉन रे फार्मास्युटिकल कंपनी लिमिटेड, हांगजो स्टारशाइन फार्मास्युटिकल कंपनी लिमिटेड, झेजियांग टॉप हैकूक बायोफार्म कंपनी लिमिटेड, और झेजियांग यूजी बिजनेस सर्विस कंपनी लिमिटेड। उत्पादक/निर्यातक ने कार्यगत कीमतों में किसी भी समायोजन का दावा नहीं किया है।

52. जांच की अवधि के लिए मैसर्स लिनहाई हुआनान केमिकल कंपनी लिमिटेड के लिए भारित औसत कारखानागत निर्यात कीमत का निर्धारण *** एमटी के सहयोगी हिस्से के लिए सत्यापित निर्यात कीमत को *** एमटी के गैर-सहयोगी हिस्से के लिए तथ्य-उपलब्ध निर्यात कीमत के साथ मिलाकर किया गया है, जैसा कि नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में निर्धारित किया गया है।

छ. 3.3. असहयोगी निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत

53. चीन जन.गण. के अन्य सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत, सहयोगी उत्पादक/निर्यातकों के लिए जांचे गए आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित की गई है और इसका उल्लेख नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

छ. 3.4. पाटन मार्जिन का निर्धारण

54. पाटन मार्जिन निम्नानुसार दिया गया है:

उत्पादक/निर्यातक का नाम	सीएनवी (यूएसडॉ./ एमटी)	एनईपी (यूएसडॉ./ एमटी)	पाटन मार्जिन (यूएसडॉ./ एमटी)	पाटन मार्जिन %	पाटन मार्जिन रेंज %
यानचेंग सिटी डोंगगांग फार्मास्युटिकल डेवलपमेंट कं, लिमिटेड	***	***	***	***	55-65
लिनहाई हुआनान केमिकल कं, लिमिटेड	***	***	***	***	60-70
झेजियांग तियान्यू फार्मास्युटिकल कं, लिमिटेड	***	***	***	***	60-70
अन्य सभी	***	***	***	***	80-90

ज. क्षति आंकलन की पद्धति क्षति तथा कारणात्मक संपर्क की जांच

ज.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

55. वर्तमान जांच के दौरान अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए क्षति संबंधी अनुरोध और प्राधिकारी द्वारा संगत माने गए अनुरोध निम्नलिखित हैं।

- आवेदक द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के गहन विश्लेषण से क्षति की जांच की अवधि के दौरान सभी प्रमुख मात्रा संबंधी मापदंडों में साल-दर-साल लगातार और पर्याप्त सुधार का पता चलता है।
- उत्पादन, क्षमता उपयोग, घरेलू बिक्री, बाजार हिस्सेदारी, रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता जैसे सभी मात्रा आधारित मापदंडों में निरंतर और पर्याप्त सुधार एक संपन्न घरेलू उद्योग की स्पष्ट तस्वीर दर्शाते हैं। ये संकेतक सामूहिक रूप से दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति नहीं हो रही है।

- iii. आयात की पहुंच कीमत में गिरावट घरेलू उद्योग की बिक्री लागत में गिरावट के अनुरूप है। वास्तव में, पहुंच कीमत में गिरावट की दर घरेलू उद्योग की बिक्री लागत में गिरावट की दर से कम है। इसका मतलब है कि आयात घरेलू उद्योग पर कीमत दबाव नहीं डाल रहा है और कीमत न्यूनीकरण एवं हास नहीं कर रहा है।
- iv. घरेलू उद्योग ने मुख्य रूप से हानि के कारण क्षति का दावा किया है। हालांकि, आंकड़ों का विश्लेषण आयात की प्रवृत्ति और घरेलू उद्योग की लाभप्रदता के बीच एक स्पष्ट असंबंध को दर्शाता है।
- v. यदि आयात क्षति का कारण था, तो जांच की अवधि हानियां बढ़नी चाहिए थी, कम नहीं होनी चाहिए था। यह असंबंध दर्शाता है कि आवेदक का वित्तीय निष्पादन मुख्य रूप से आयात की मात्रा या कीमत से नियंत्रित नहीं होता है, यह सुझाव देते हुए कि हानियों का मूल कारण अन्य कारकों में निहित है।
- vi. अपनी वार्षिक रिपोर्ट में आवेदकों के अपने विवरण आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान, भू-राजनीतिक तनाव और कच्चे माल की कीमत में सुधार को प्राथमिक चुनौतियों के रूप में पहचानते हैं। इन चुनौतियों ने न केवल जांच की अवधि बल्कि पूरी कंपनी को प्रभावित किया। हालांकि, इसका मतलब यह भी है कि इन चुनौतियों ने विचाराधीन उत्पाद के लिए घरेलू उद्योग के निष्पादन को भी प्रभावित किया और ये कारक कथित पाटन से पूरी तरह से असंबंधित हैं और इन्हें किसी भी क्षति के प्रमुख कारणों के रूप में माना जाना चाहिए।
- vii. याचिकाकर्ता ने वित्तीय हानियों की सूचना दी है; तथापि, जांच की अवधि के दौरान प्रमुख वित्तीय संकेतकों की बारीकी से जांच से स्थिरीकरण और वसूली की महत्वपूर्ण प्रवृत्ति का पता चलता है। याचिकाकर्ता द्वारा प्रदान किए गए सूचीबद्ध आंकड़े स्पष्ट रूप से इसके वित्तीय निष्पादन में लगातार सुधार को दर्शाते हैं, जो सीधे तौर पर पाटित आयातों के कारण होने वाली वास्तविक क्षति के दावे के विरोधाभासी हैं।
- viii. चीन जन.गण. से आयात में कथित वृद्धि पाटन का परिणाम नहीं है, बल्कि घरेलू मांग में वृद्धि का प्रत्यक्ष परिणाम है। भारत में संबद्ध सामानों की कुल मांग में लगातार वृद्धि देखी गई है, सूचकांक 2022-23 में 100 से बढ़कर जांच की अवधि (जनवरी 2024-दिसंबर 2024) में 163 हो गया है, जो 63% की वृद्धि दर्शाता है।
- ix. जांच की अवधि के दौरान, कीमत कटौती नकारात्मक है, जो दर्शाता है कि चीन जन.गण. से आयात की कीमत घरेलू बिक्री कीमत से अधिक थी। पिछले वर्षों में भी कीमत कटौती न्यूनतम और असंगत रही है। इससे पता चलता है कि घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने वाला कोई कीमत प्रभाव नहीं है।
- x. जांच की अवधि के दौरान मालसूची के स्तर में वृद्धि चीन जन.गण. से आयात के कारण होने वाली क्षति के साक्ष्य के बजाय एक रणनीतिक व्यावसायिक निर्णय प्रतीत होता है। इसकी पुष्टि उत्पादन में तेज वृद्धि (210 पर सूचीबद्ध) से होती है जो स्वाभाविक रूप से आपूर्ति निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए उच्च मालसूची भंडारण की आवश्यकता होती है। इस के अतिरिक्त, घरेलू बिक्री में भी काफी वृद्धि हुई है (168 पर सूचीबद्ध) जो वस्तुओं की निरंतर आवाजाही और बाजार की निरंतर मांग का संकेत देती है।
- xi. याचिकाकर्ता द्वारा दावा की गई वित्तीय हानियां चीन जन.गण. से आयात के कारण नहीं हैं, बल्कि इसके अपने वाणिज्यिक निर्णयों और आंतरिक अदक्षताओं का परिणाम है। सूचीबद्ध वित्तीय आंकड़े, जैसा कि अद्यतन याचिका के अगोपनीय रूपांतर में किया गया है, से पता चलता है कि मूल्यहास और ब्याज व्यय जैसे प्रमुख लागत घटकों में जांच की अवधि के दौरान काफी वृद्धि हुई है।

- xii. उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्री में निरंतर वृद्धि दर्शाती है कि घरेलू उद्योग कुशलता से काम कर रहा है और संबद्ध आयात से प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं है।
- xiii. चीन जन.गण. से पाटित आयातों और याचिकाकर्ता द्वारा सामना किए जाने वाले वित्तीय तनाव के बीच कोई स्पष्ट कारणात्मक संपर्क नहीं है। हानियां काफी हद तक आंतरिक कारकों जैसे उच्च लागत, निवेश अदक्षताओं और बाहरी पाटन के बजाय रणनीतिक व्यावसायिक विकल्पों के कारण हैं।
- xiv. स्थापित क्षमता में कोई वृद्धि नहीं होने के बावजूद, याचिकाकर्ता की नियोजित पूंजी में तेजी से वृद्धि हुई है, जो खराब परिसंपत्ति उपयोग और संभावित रूप से अदक्ष निवेश निर्णयों का संकेत देती है। सूचीबद्ध मूल्यहास और ब्याज लागत भी असमान रूप से बढ़ी है, जो वित्तीय बोझ को और बढ़ा रही है और बाहरी प्रतिस्पर्धी दबाव के बजाय आंतरिक वित्तीय कुप्रबंधन को दर्शाती है।

ज.2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

56. वर्तमान जांच के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा किए गए क्षति संबंधी अनुरोध और प्राधिकारी द्वारा संगत माने गए अनुरोध निम्नलिखित हैं:

- i. क्षति की कमी के बारे में हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध मौलिक रूप से त्रुटिपूर्ण हैं और घरेलू उद्योग को हानि दर्शाने वाले साक्ष्य की समग्रता पर विचार करने में विफल रहते हैं। हालांकि यह सच है कि क्षति के कुछ पहलुओं में सुधार हुआ है, भारतीय पाटनरोधी कानूनों और डब्ल्यूटीओ करार के तहत क्षति विश्लेषण केवल कुछ मापदंडों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पाटित आयातों के प्रभाव, कीमत प्रभाव, बाजार हिस्सेदारी के क्षरण और घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंडों पर प्रतिकूल प्रभावों को ध्यान में रखते हुए एक समग्र मूल्यांकन किया जाना है। कुछ मापदंडों में केवल सुधार पाटित आयातों के कारण होने वाली सामग्री की क्षति को नकारता नहीं है, और न ही यह आगे की क्षति के जोखिम को दूर करता है।
- ii. पहले से दर्ज आंकड़ों से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि घरेलू उद्योग मात्रा और कीमत मापदंडों के संबंध में गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है। संबद्ध आयात द्वारा काफी कीमत न्यूनीकरण/कीमत हास है और कम कीमत पर बिक्री भी सकारात्मक और काफी है।
- iii. क्षमता उपयोग, लाभप्रदता, आरओसीई, नकदी प्रवाह, बाजार हिस्सेदारी आदि की तुलना में घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंड भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए हैं।
- iv. आयात द्वारा लगाए गए निरंतर कीमत दबाव के कारण, घरेलू उद्योग संबद्ध सामानों को लागत से कम पर बेचने के लिए मजबूर है।
- v. घरेलू उद्योग पर अपने ग्राहकों द्वारा आयात कीमतों का मिलान करके अपनी कीमतों को कम करने के लिए लगातार दबाव डाला जाता है और ऐसे कई उदाहरण हैं जहां इसके ग्राहकों ने घरेलू उद्योग से आयात कीमतों का मिलान करने की मांग करते हुए पहले से ही ऑर्डर को रोक दिया है। इस संबंध में, घरेलू उद्योग ने अपने ग्राहकों के साथ इस तरह की कुछ ईमेल बातचीत प्रस्तुत की है, जिसमें ग्राहकों ने उन्हें आयात कीमतों का मिलान करने के लिए कहा है और कुछ मामलों में कीमत में कमी होने तक ऑर्डर को रोक दिया है।
- vi. जहां जांच की अवधि में घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्री में वृद्धि हुई है, वहीं घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी में गिरावट आई है। इसके विपरीत, चीन जन.गण. की बाजार हिस्सेदारी में काफी वृद्धि हुई है, जो भारत में कुल मांग का दो तिहाई से अधिक है।
- vii. चीन जन.गण. से आयात में बहुत तेज वृद्धि हुई है, जो मांग में वृद्धि से अतिरिक्त और अधिक है। दूसरी ओर, घरेलू उद्योग की बिक्री में वृद्धि विशुद्ध रूप से मांग में वृद्धि के कारण है। यह भी अनुरोध है कि घरेलू उद्योग की बिक्री में वृद्धि मांग में वृद्धि और आयात में वृद्धि की तुलना में कम है।

- viii. जबकि कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने सुनवाई के दौरान तर्क दिया कि आयात में वृद्धि और घरेलू उद्योग को होने वाली हानियों के बीच कोई संबंध नहीं है, यह अनुरोध किया जाता है कि आयात की ऐसी अवधि के दौरान उल्लिखित लागत को ध्यान में रखे बिना इस तरह के अनुरोध अर्थहीन हैं।
- ix. घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग और लाभप्रदता और आरओसीई पर परिणामी प्रभाव के बीच एक सीधा संबंध मौजूद है। आधार वर्ष की तुलना में 2022-23 के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता उपयोग में सुधार हुआ है जिससे घरेलू उद्योग की लाभप्रदता और आरओसीई में सुधार हुआ है। हालांकि, 2023-24 में क्षमता उपयोग में उल्लेखनीय गिरावट आई, जिससे लाभप्रदता और आरओसीई में उल्लेखनीय गिरावट आई। घरेलू उद्योग फिर से जांच की अवधि में अपनी क्षमता उपयोग में काफी सुधार करने में सक्षम था जिससे जांच की अवधि में लाभप्रदता और आरओसीई में सुधार हुआ। स्पष्ट रूप से, लाभप्रदता के साथ घरेलू क्षमता उपयोग और घरेलू उद्योग के आरओसीई के बीच एक सीधा संबंध मौजूद है। इसी तरह की प्रवृत्ति तब दिखाई देती है जब आयात की सीआईएफ कीमतों और घरेलू उद्योग की लागत के बीच डेल्टा का प्रभाव घरेलू उद्योग के पीवीटी और आरओसीई पर देखा जाता है। घरेलू उद्योग का पीवीटी और आरओसीई एक साथ बढ़ता है जब इसकी लागत और आयात कीमतों के बीच का अंतर बढ़ता है। इसके विपरीत, दोनों मेट्रिक्स में गिरावट आती है क्योंकि यह अंतर कम हो जाता है। यह स्पष्ट रूप से आयात कीमतों और घरेलू उद्योग की लाभप्रदता के बीच सीधा संबंध स्थापित करता है।
- x. किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने रिकॉर्ड में कोई साक्ष्य नहीं दिया है कि संबद्ध देश से पाटन को छोड़कर अन्य कारकों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई है। केवल असिद्ध विवरण दिए गए हैं। अतः, हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों को नजरअंदाज करने की आवश्यकता है।

ज.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

57. अनुबंध-II के साथ पठित नियमावली के नियम 11 में यह प्रावधान है कि क्षति के निर्धारण में "... पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर इस प्रकार के आयातों का परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत तथ्यों पर विचार करते हुए ..." घरेलू उद्योग को क्षति दर्शाने वाले कारकों की जांच शामिल होगी। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, इस बात की जांच करना आवश्यक माना गया है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा कीमत में बहुत अधिक कटौती हुई है अथवा यह कि क्या इस प्रकार के आयातों के प्रभाव से अन्यथा कीमतों का बहुत अधिक मात्रा में हास हुआ है अथवा कीमत में वृद्धि रूक जाती जो अन्यथा बहुत अधिक मात्रा में हुई होती। भारत में घरेलू उद्योगों पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए, इन सूचकांकों जिनका उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता हो जैसे उत्पादन, क्षमता का उपयोग, बिक्री की मात्रा, मालसूची, लाभप्रदता, निवल बिक्री प्राप्ति, पाटन की मात्रा और मार्जिन आदि पर विचार नियमावली के अनुबंध-II के अनुसार किया गया है।

58. प्राधिकारी द्वारा किया गया क्षति विश्लेषण वर्तमान जांच के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों और प्राधिकारी द्वारा संगत माने गए अनुरोधों को निम्नलिखित रूप में हल करता है।

ज.3.1 पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव

क. मांग/खपत का मूल्यांकन

59. प्राधिकारी ने भारत में उत्पाद की मांग या प्रत्यक्ष खपत को घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री, अन्य उत्पादकों की अनुमानित बिक्री और सभी स्रोतों से संबद्ध सामानों के आयात के योग के रूप में निर्धारित किया है।

विवरण	यूओएम	2021-22	2022-23	2023-24	जांच की अवधि
घरेलू उद्योग की बिक्री	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	132	75	168
अन्य उत्पादकों की बिक्री	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	135	60	116
संबद्ध देश से आयात	एमटी	***	***	***	***
अन्य देशों से आयात	एमटी	0	0	0	0
कुल मांग	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	106	96	125

60. यह देखा जाता है कि क्षति जांच अवधि के दौरान संबद्ध सामानों की मांग में वृद्धि हुई और यह जांच की अवधि में सबसे अधिक थी। घरेलू उद्योग और अन्य उत्पादकों की बिक्री 2022-23 में बढ़ी, उसके बाद 2023-24 में गिर गई तथा जांच की अवधि में बढ़ गई।

61. क्षति जांच अवधि के दौरान आयात में भी वृद्धि हुई है और यह जांच की अवधि में सबसे अधिक थी। हितबद्ध पक्षकारों के इस अनुरोध के संबंध में कि आयात में वृद्धि मांग में वृद्धि के कारण हुई है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि हालांकि आधार वर्ष से जांच की अवधि में आयात में वृद्धि मांग में वृद्धि से कम है, घरेलू उद्योग की महत्वपूर्ण उत्पादन क्षमता का उपयोग नहीं किया गया है।

ख. पूर्ण और सापेक्ष रूप में आयात

62. क्षति की अवधि और जांच की अवधि में पूर्ण रूप से और सापेक्ष रूप से आयात की मात्रा के बारे में सूचना नीचे दी गई है।

विवरण	यूओएम	2021-22	2022-23	2023-24	जांच की अवधि
संबद्ध देश के आयात	एमटी	456	426	501	538
अन्य आयात	एमटी	0	0	0	0
कुल आयात	एमटी	456	426	501	538
निम्नलिखित के संबंध में संबद्ध देशों के आयात					
भारतीय उत्पादन	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	65	168	73
मांग	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	88	115	94
कुल आयात	%	100	100	100	100

प्रवृत्ति		100	100	100	100
-----------	--	-----	-----	-----	-----

63. प्राधिकारी नोट करते हैं कि:

- क. भारतीय उत्पादन के संबंध में संबद्ध आयात पहले 2022-23 में कम हुए, उसके बाद 2023-24 में बढ़े और अंत में जांच की अवधि में उनमें गिरावट आई।
- ख. मांग/खपत के संबंध में संबद्ध आयातों ने भी समान पैटर्न दर्शाया है।

ज.3.2 पाटित आयातों का कीमत प्रभाग

64. नियमावली के अनुबंध II (ii) के अनुसार, कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में, प्राधिकारी को इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों से काफी कीमत कटौती हुई है, या क्या इस तरह के आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों को काफी मात्रा तक कम करना या कीमत वृद्धि को रोकने के लिए है, जो अन्यथा काफी मात्रा तक हुई होती।
65. तदनुसार, संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रभाव की कीमत कटौती और न्यूनीकरण/ह्रास के संदर्भ में जांच की गई है। इस विश्लेषण के उद्देश्य से, घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और निवल बिक्री वसूली (एनएसआर) की तुलना संबद्ध देश से संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत के साथ की गई है।
- क. कीमत कटौती
66. घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति की तुलना जांच की अवधि के लिए आयात की पहुंच कीमत से करके कीमत कटौती का निर्धारण किया गया है। नीचे दी गई तालिका संबद्ध देश से कीमत कटौती को दर्शाती है।

विवरण	यूओएम	मूल्य
पहुंच कीमत	र./एमटी	***
निवल बिक्री प्राप्ति	र./एमटी	***
कीमत कटौती	र./एमटी	***
कीमत कटौती	%	***
कीमत कटौती	% रेंज	नगण्य

67. यह देखा जाता है कि जांच की अवधि में संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से मामूली रूप से अधिक है जिसके परिणामस्वरूप नकारात्मक कीमत कटौती हुई।
68. घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि वे अपने ग्राहकों द्वारा आयात कीमतों का मिलान करके कीमतों को कम करने के लिए लगातार दबाव डाल रहे हैं और ऐसे कई उदाहरण हैं जहां उनके ग्राहकों ने घरेलू उद्योग से आयात कीमतों का मिलान करने की मांग करते हुए पहले से ही ऑर्डर को रोक दिया है। इस संबंध में, घरेलू उद्योग ने अपने ग्राहकों के साथ ईमेल वार्तालाप की नमूना प्रतियां सबूत के रूप में प्रस्तुत की हैं, जहां ग्राहकों ने उन्हें आयात कीमतों का मिलान करने के लिए कहा है और कुछ मामलों में, कीमत में कमी आने तक ऑर्डर को रोक दिया है।

ख. कीमत ह्रास/न्यूनीकरण

69. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटित आयात घरेलू कीमतों का ह्रास रहे हैं या क्या इस तरह के आयातों का प्रभाव कीमतों को काफी हद तक कम करना है या कीमत वृद्धि को रोकना है जो अन्यथा सामान्य प्रक्रिया में हुई होती, क्षति की अवधि में लागतों और कीमतों में परिवर्तनों की तुलना निम्नलिखित रूप में की गई है।

विवरण	यूओएम	2021-22	2022-23	2023-24	जांच की अवधि
पहुंच मूल्य	रु./एमटी	14,69,288	17,59,638	10,15,382	8,01,233
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	120	69	55
बिक्री लागत	रु./एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	85	83	49
बिक्री कीमत	रु./एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	64	47

70. यह देखा जाता है कि संबद्ध देश से आयात घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत से कम बने हुए हैं। कम कीमत वाले आयात ने घरेलू उद्योग को अपनी बिक्री लागत से कम कीमत पर संबद्ध सामान बेचने के लिए मजबूर किया है। पाटित आयात घरेलू उद्योग की कीमतों का न्यूनीकरण और ह्रास कर रहे हैं।

71. जहां तक हितबद्ध पक्षकारों के इस अनुरोध का संबंध है कि आयातों की पहुंच कीमत में गिरावट बिक्री की लागत में गिरावट के अनुरूप है और आयात कीमत में कमी उत्पाद की बिक्री की लागत में गिरावट को दर्शाती है न कि पाटन के कारण, प्राधिकारी नोट करते हैं कि हालांकि उत्पादन की लागत में गिरावट आई है, आयात का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत से लगातार काफी कम है।

ज.3.3 घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंडों पर प्रभाव

72. घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति मापदंडों पर नीचे चर्चा की गई है।

क क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्री

73. क्षति की अवधि में क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्री के संबंध में सूचना इस प्रकार है:

विवरण	यूओएम	2021-22	2022-23	2023-24	जांच की अवधि
संस्थापित क्षमता	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	100	100
उत्पादन	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	143	72	210
क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	139	71	207
घरेलू बिक्री	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	132	75	168

74. प्राधिकारी नोट करते हैं कि:-

क. घरेलू उद्योग की क्षमता क्षति की जांच अवधि के दौरान समान रही है। हालाँकि, घरेलू उद्योग में महत्वपूर्ण अप्रयुक्त क्षमताएँ हैं।

ख. घरेलू उद्योग के उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्री में 2022-23 में वृद्धि हुई, उसके बाद वर्ष 2023-24 में गिरावट आई और जांच की अवधि में वृद्धि हुई।

ख. बाजार हिस्सा

75. इस अवधि में आयात और भारतीय उद्योग की बाजार हिस्सेदारी के बारे में सूचना इस प्रकार थी:

बाजार हिस्सा	यूओएम	2021-22	2022-23	2023-24	जांच की अवधि
घरेलू उद्योग	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	124	78	134
अन्य उत्पादक	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	127	62	92
संबद्ध देश से आयात	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	88	114	94
अन्य देशों से आयात	%	0	0	0	0
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	0	0	0	0

76. प्राधिकारी नोट करते हैं कि: -

क. घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी 2022-23 में बढ़ी, लेकिन उसके बाद 2023-24 में गिरावट आई, और फिर से जांच की अवधि में बढ़ गई। कुल मिलाकर, क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि हुई।

ख. चीन जन.गण. से आयात की बाजार हिस्सेदारी पहले 2022-23 में घटी, उसके बाद 2023-24 में बढ़ी और अंत में जांच की अवधि के दौरान गिरावट आई। कुल मिलाकर, क्षति की अवधि के दौरान चीन जन.गण.से आयात की बाजार हिस्सेदारी में मामूली गिरावट आई।

ग. संबद्ध देश से आयातों का भारतीय बाजार में अधिकतर बाजार हिस्सेदारी पर नियंत्रण है।

घ. जांच की अवधि के दौरान बेहतर मात्रा मापदंडों के बारे में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देश से आयातों का घरेलू उद्योग में काफी अनुपयुक्त क्षमताओं के बावजूद अधिकतर बाजार हिस्सेदारी पर नियंत्रण है। इसके अलावा, अन्य भारतीय उत्पादकों की बाजार हिस्सेदारी में भी गिरावट आई है।

ग. लाभप्रदता, नकद लाभ, और निवेश पर आय

77. लाभप्रदता, निवेश पर आय और नकद लाभ के बारे में सूचना इस प्रकार है:

विवरण	यूओएम	2021-22	2022-23	2023-24	जांच की अवधि
लाभ/(हानि)	रु./एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-100	-43	-140	-57
लाभ/(हानि)	लाख रु.	***	***	***	***

प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-100	-56	-106	-97
नकद लाभ	रु./एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-100	-36	-142	-52
नकद लाभ	लाख रु.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-100	-47	-108	-83
आरओसीई	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-100	-31	-95	-32

78. यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग की प्रति यूनिट हानि में 2023-24 में वृद्धि हुई और उसके बाद जांच की अवधि के दौरान उसमें गिरावट आई। पीबीआईटी, नकद लाभ और आरओसीई में भी इसी तरह की प्रवृत्ति देखी गई है। घरेलू उद्योग पूरी क्षति जांच अवधि में लगातार हानियों में है।

79. घरेलू उद्योग के बेहतर वित्तीय निष्पादन के संबंध में, यह भी नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में वृद्धि हुई है जब भी उनकी क्षमता उपयोग में वृद्धि हुई है और क्षमता उपयोग में गिरावट के साथ गिरावट आई है। इस प्रकार, आयात की उच्च मात्रा से घरेलू उद्योग की क्षमताओं का कम उपयोग होता है, जिससे घरेलू उद्योग को हानियां होती हैं।

80. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध करने के संबंध में कि स्थापित क्षमता में कोई वृद्धि नहीं होने के बावजूद, याचिकाकर्ता की नियोजित पूंजी में तेजी से वृद्धि हुई है, जो खराब परिसंपत्ति उपयोग और संभावित रूप से अदक्ष निवेश निर्णयों का संकेत देता है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उद्योग संबद्ध सामानों और अन्य उत्पादों के निर्माण के लिए सामान्य संयंत्र का उपयोग करते हैं जो वर्तमान जांच में शामिल नहीं हैं। संबद्ध सामानों के उत्पादन और क्षमता उपयोग में वृद्धि के कारण नियोजित उच्च पूंजी के विभाजन, कीमत ह्रास और संबद्ध सामानों के प्रति ब्याज लागत में वृद्धि हुई।

घ. मालसूची

81. मालसूची के संबंध में सूचना निम्नानुसार है:

विवरण	यूओएम	2021-22	2022-23	2023-24	जांच की अवधि
आरंभिक मालसूची	एमटी	***	***	***	***
अंतिम मालसूची	एमटी	***	***	***	***
औसत मालसूची	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	2350	3809	7864

82. यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग की औसत मालसूची में क्षति की अवधि के दौरान काफी वृद्धि हुई है।

ड. रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता

83. क्षति की अवधि में रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता के बारे में सूचना इस प्रकार है:

विवरण	यूओएम	2021-22	2022-23	2023-24	जांच की अवधि
कर्मचारियों की संख्या	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	125	142	140
वेतन एवं मजदूरी	लाख रु.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	170	107	337
प्रतिदिन उत्पादकता	एमटी/दिन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	144	74	211
प्रति कर्मचारी उत्पादकता	एमटी/कर्मचारी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	114	51	150

84. क्षति की अवधि के दौरान कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि हुई। उन्हें प्रदत्त में भी वृद्धि हुई है। प्रतिदिन और प्रति कर्मचारी उत्पादकता में वृद्धि हुई है।

च. वृद्धि

85. वृद्धि संबंधी सूचना नीचे दी गई है: -

वृद्धि	यूओएम	2022-23	2023-24	जांच की अवधि
क्षमता	%	0%	0%	0%
उत्पादन	%	43%	-50%	193%
घरेलू बिक्री	%	32%	-43%	124%
लाभ/(हानि) (रु./एमटी)	%	57%	-229%	59%
नकद लाभ (रु./एमटी)	%	64%	-291%	63%
आरओसीई	%	69%	-207%	74%

86. प्राधिकारी नोट करते हैं कि हालांकि घरेलू उद्योग ने लाभप्रदता, नकद लाभ और आरओसीई आदि जैसे सभी कीमत मापदंडों के संदर्भ में जांच की अवधि में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की है, फिर भी उन्हें हानियां हो रही हैं। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने उत्पादन, बिक्री और क्षमता उपयोग आदि जैसे मात्रात्मक मापदंडों में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की है।

छ. पाटन की मात्रा

87. पाटन की मात्रा इस बात का संकेतक है कि भारत में आयात किस तक पाटित किया जा रहा है। जाँच से पता चला है कि जाँच की अवधि में पाटन मार्जिन सकारात्मक और काफी है।

ज. पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता

88. यह नोट किया जाता है कि जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा लाभप्रदता और नियोजित पूंजी पर आय नकारात्मक रही है। जाँच और क्षति जाँच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग घाटे में था। इसने पूंजी निवेश बढ़ाने की क्षमता को प्रभावित किया है।

झ. घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

89. आयात कीमत की जांच से पता चलता है कि संबद्ध देश से आयात कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत से वास्तविक रूप से कम है। चूंकि संबद्ध देश से आयात इस तरह की कीमतों पर घरेलू बाजार में आते हैं, अतः घरेलू उद्योग अपनी कीमतें बिक्री की लागत में वृद्धि के अनुरूप रखने में अक्षम रहा है।

त्र. क्षति संबंधी अवलोकन

90. घरेलू उद्योग के विचाराधीन उत्पाद के आयात और निष्पादन की जांच से पता चलता है कि:

- क. संबद्ध देश के निर्यातक पाटित कीमतों पर भारत को संबद्ध सामानों का निर्यात कर रहे हैं। निर्धारित पाटन मार्जिन सकारात्मक और काफी अधिक है।
- ख. संबद्ध देश से आयात पूर्ण रूप से काफी बढ़ गया है।
- ग. कीमत कटौती नकारात्मक है। प्राधिकारी घरेलू उद्योग के इस अनुरोध को नोट करते हैं कि देश में बढ़ते आयात और आयात कीमतों से मेल खाने के लिए अपने ग्राहकों के दबाव के कारण उसे अपनी कीमतें कम करने के लिए मजबूर होना पड़ा।
- घ. संबद्ध देश से आयात ने घरेलू उद्योग की कीमतों न्यूनीकरण और ह्रास किया है।
- ड. घरेलू उद्योग को काफी हानियां हो रही हैं।
- च. घरेलू उद्योग पर्याप्त आय प्राप्त करने में अक्षम रहा है। वास्तव में, आरओसीई नकारात्मक रहा है।
- छ. संबद्ध देश से आयात ने घरेलू उद्योग को अच्छा निष्पादन नहीं करने दिया है और इस प्रकार, घरेलू उद्योग को निरंतर हानियां हुई हैं।

ज.4 गैर-आरोपण विश्लेषण (अन्य कारक)

91. प्राधिकारी ने यह जांच की कि क्या पाटनरोधी नियमावली के तहत सूचीबद्ध अन्य कारकों से घरेलू उद्योग को क्षति हुई है। प्राधिकारी पाटित को छोड़कर अन्य ज्ञात कारकों की जांच की और यह पता लगाया कि क्या ये एक ही समय में घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहे हैं, ताकि अन्य, यदि कोई हो, के कारण होने वाली क्षति पाटित आयातों के कारण न हो। इस संबंध में संगत कारकों में, अन्य बातों के साथ-साथ, पाटित कीमतों पर नहीं बेचे संबद्ध सामानों की मात्रा, मांग में संकुचन या खपत के पैटर्न में परिवर्तन, व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटियां, प्रौद्योगिकी में परिवर्तन, घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन और घरेलू उद्योग की उत्पादकता शामिल हैं।

(क) तीसरे देशों से आयात की मात्रा और कीमतें

92. अन्य देशों से उत्पाद का कोई आयात विचाराधीन नहीं है। इसलिए, अन्य देशों से आयात से घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हो सकती।

(ख) मांग में संकुचन और खपत के पैटर्न में परिवर्तन

93. क्षति की अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद की मांग में वृद्धि हुई है। इसलिए, मांग में गिरावट घरेलू उद्योग को क्षति का संभावित कारण नहीं है।

(ग) प्रौद्योगिकी में विकास

94. संबंधित उत्पाद के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है। इस प्रकार, प्रौद्योगिकी में विकास भी घरेलू को क्षति पहुंचाने वाला कारक नहीं है।

(घ) प्रतिस्पर्धा की शर्तें और व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटियां

95. ऐसी कोई व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटी नहीं है, जो घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा सकती है क्योंकि कच्ची सामग्री तथा संबद्ध आयात देश में स्वतंत्र रूप से आयात किए जा सकते हैं।

(ङ) घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन

96. इस क्षति विश्लेषण के उद्देश्य से केवल घरेलू उद्योग के घरेलू निष्पादन पर विचार किया गया है। इसलिए, निर्यात बाजार में निष्पादन से वर्तमान क्षति विश्लेषण किसी भी तरह से प्रभावित नहीं हुआ है।

(च) अन्य उत्पादों का निष्पादन

97. घरेलू उद्योग ने समान वस्तु के लिए क्षति के आंकड़े प्रदान किए हैं और इसे प्राधिकारी द्वारा क्षति विश्लेषण के उद्देश्य से अपनाया गया है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और बेचे जाने वाले अन्य उत्पादों के निष्पादन पर विचार नहीं किया गया है। इसलिए, उत्पादित और बेचे जाने वाले अन्य उत्पादों का निष्पादन घरेलू उद्योग को क्षति का संभावित कारण नहीं है।

98. इस प्रकार यह नोट किया जाता है कि अन्य कारक यह नहीं दर्शाते हैं कि इन अन्य कारकों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती है।

ज.5 क्षति मार्जिन का निर्धारण

99. प्राधिकारी ने यथासंशोधित, अनुबंध-III के साथ पठित नियमावली में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए क्षतिरहित कीमत निर्धारित की है। जांच की अवधि के लिए उत्पादन लागत से संबंधित सत्यापित सूचना/आंकड़ों को अपनाकर विचाराधीन उत्पाद की क्षतिरहित कीमत निर्धारित की गई है। क्षति मार्जिन की गणना के लिए संबद्ध देशों से पहुंच कीमत की तुलना के लिए क्षतिरहित कीमत पर विचार किया गया है। यही व्यवहार यूटिलिटियों के साथ किया गया है। क्षति की अवधि में उत्पादन क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि उत्पादन की लागत पर कोई असाधारण या गैर-आवर्ती व्यय नहीं लगाया गया था। विचाराधीन उत्पाद के लिए नियोजित औसत पूंजी (अर्थात्, औसत निवल अचल परिसंपत्ति एवं औसत कार्यशील पूंजी) पर उचित आय (कर-पूर्व @ 22%) को नियमावली के अनुबंध-III में निर्धारित क्षतिरहित कीमत निकालने के लिए अनुमति दी गई थी।

100. पहुंच कीमत और ऊपर निर्धारित क्षतिरहित कीमत के आधार पर, प्राधिकारी द्वारा निर्धारित क्षति का अंतर नीचे दी गई तालिका में दिया गया है।

उत्पादक/निर्यातक का नाम	क्षतिरहित कीमत (रु./एमटी)	पहुंच मूल्य (रु./एमटी)	क्षति मार्जिन (रु./एमटी)	क्षति मार्जिन %	क्षति मार्जिन % रेंज
यानचेंग सिटी डोंगगैंग फार्मास्युटिकल डेवलपमेंट कं, लिमिटेड	***	***	***	***	50-60
लिनहाई हुआनान	***	***	***	***	60-70

केमिकल कं, लिमिटेड					
झेजियांग तियान्यू फार्मास्युटिकल कं, लिमिटेड	***	***	***	***	50-60
अन्य सभी	***	***	***	***	80-90

झ. कारणात्मक संपर्क की जांच

101. प्राधिकारी ने यह जांच की है कि क्या पाटन के प्रभावों के माध्यम से चीन जन.गण. से पाटित आयात, घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहे हैं, और निम्नलिखित नोट करते हैं।

- संबद्ध देश से पाटित आयात जांच की अवधि में अपने उच्चतम स्तर *** एमटी तक पहुंच गये, जिसने कुल भारतीय मांग के 64% पर कब्जा कर लिया, और घरेलू उद्योग क्षति की जांच अवधि के दौरान नकारात्मक नकद लाभ और नकारात्मक आरओसीई के साथ हानियों में रहा।
- जांच की अवधि में पाटित आयातों का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत से कम था, जिससे घरेलू उद्योग को लागत से कम बेचने और जांच की अवधि में हानियां उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा।
- घरेलू उद्योग ने आयात कीमतों से मिलान करने के लिए अपने ग्राहकों से पत्रों को रिकॉर्ड में रखा है और वे उदाहरण दिए हैं, जिनमें कीमत कम होने तक ऑर्डर रोक कर रखे गये थे।
- घरेलू उद्योग का प्रति-इकाई घाटा तब बढ़ गया है जब इसकी बिक्री लागत और पाटित आयातों के पहुंच मूल्य के बीच का अंतर बढ़ गया था, और जब अंतर कम हो गया था तो वह घट गया है, जो यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग की लाभप्रदता उस कीमत से नियंत्रित होती है जिस पर पाटित आयात भारतीय बाजार में आते हैं।
- पाटित आयात ने घरेलू उद्योग की कीमतों को उसकी उत्पादन लागत से नीचे ले गये हैं।
- भारतीय मांग में वृद्धि के बावजूद, चीन जन.गण. से आयात का हिस्सा जांच की अवधि में 64% पर प्रभावी रहा है, जबकि घरेलू उद्योग का हिस्सा केवल 20% था, जो दर्शाता है कि घरेलू उद्योग बाजार हिस्से में वृद्धि के अनुरूप मांग बाजार वृद्धि करने में अक्षम रहा है।

102. उपर्युक्त को और उपर्युक्त पैरा में गैर-आरोपण विश्लेषण को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि चीन जन.गण. से पाटित आयातों और घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति के बीच कारणात्मक संपर्क है।

त्र. भारतीय उद्योग के हित और अन्य मुद्दे

त्र.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

103. गोपनीयता के संबंध में वर्तमान जांच के दौरान अन्य अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोध और प्राधिकारी द्वारा संगत माने गए अनुरोध इस प्रकार हैं:

- पाटनरोधी शुल्क लगाना पाटन या क्षति के अस्तित्व का एक यांत्रिक परिणाम नहीं है; बल्कि, यह पाटनरोधी नियमावली के नियम 17 (3) के तहत जनहित के व्यापक मूल्यांकन के अध्यक्षीन है। सार्वजनिक हित व्यापार उपचार कार्यों के लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षण है और यह सुनिश्चित करता है कि शुल्क घरेलू उपभोक्ताओं, निचले स्तर के उद्योगों या व्यापक आर्थिक लक्ष्यों को अनुचित रूप से हानि न पहुंचाएं। चीन जन.गण. से ब्रोमो ओटीबीएन के आयात से संबंधित वर्तमान मामले में, पाटनरोधी शुल्क लगाना स्पष्ट रूप से सार्वजनिक हित के लिए हानिकारक होगा।

- ii. ब्रोमो ओटीवीएन एक महत्वपूर्ण मध्यवर्ती रसायन है जिसका उपयोग दवाओं के "सरतान" वर्ग से संबंधित कई सक्रिय औषधीय अवयवों (एपीआई) के संश्लेषण में किया जाता है। ये एपीआई व्यापक रूप से निर्धारित एंटीहाइपरटेंसिव दवाओं जैसे कि वालसार्टन, टेलमिसार्टन, इरबेसार्टन और लोसार्टन के निर्माण के लिए आवश्यक हैं, जिनका उपयोग मधुमेह के रोगियों में उच्च रक्तचाप, हृदय की विफलता और गुर्दे की बीमारी के इलाज के लिए किया जाता है। इन दवाओं को आवश्यक दवाओं की सूची में सूचीबद्ध किया गया है, और उनकी सस्ती उपलब्धता भारत में महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता का विषय है। प्रमुख मध्यवर्ती (ब्रोमो ओटीवीएन) पर शुल्क लगाने से भारतीय एपीआई निर्माताओं के लिए इनपुट लागत सीधे बढ़ेगी, जिससे इन महत्वपूर्ण दवाओं की उत्पादन लागत में वृद्धि होगी।
- iii. भारतीय दवा उद्योग, विशेष रूप से एपीआई निर्माताओं के पास ब्रोमो ओटीवीएन के लिए सीमित घरेलू सोर्सिंग विकल्प हैं। क्षमता की कमी, लागत कारकों और आपूर्ति की विश्वसनीयता के कारण याचिकाकर्ता, नियोजन केमिकल्स लिमिटेड या किसी अन्य भारतीय उत्पादक द्वारा पूरी मांग को पूरा नहीं किया जा सकता है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, याचिकाकर्ता की घरेलू बिक्री मांग वृद्धि की बराबरी करने में असमर्थ थी, और बाजार की जरूरतों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा आयात के माध्यम से पूरा किया गया है। शुल्क के माध्यम से इन आयातों को अवरुद्ध करने या बोझ डालने से अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्र में आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान पैदा होगा।
- iv. घरेलू उद्योग (80-90% पाटन मार्जिन और 70-80% क्षति मार्जिन) द्वारा दावा किए गए उच्च पाटनरोधी शुल्क को लागू करने से यह आवश्यक कच्चा माल निषेधात्मक रूप से महंगा हो जाएगा। इससे महत्वपूर्ण दवाओं की उत्पादन लागत बढ़ जाएगी, जो वांछनीय नहीं है।
- v. यह भी उजागर करना महत्वपूर्ण है कि अंतिम दवा उत्पादों के लिए घरेलू उत्पादन क्षमता की कोई कमी नहीं है। इसके विपरीत, ब्रोमो ओटीवीएन के आयात में वृद्धि ने भारत में एपीआई के अधिक कुशल और लागत प्रभावी उत्पादन को सक्षम बनाया है। संरक्षणवादी व्यापार उपायों के माध्यम से इस आपूर्ति श्रृंखला में किसी भी व्यवधान से केवल एक घरेलू आपूर्तिकर्ता को लाभ होगा, जबकि दर्जनों निचले स्तर के प्रयोक्ताओं और लाखों रोगियों को नुकसान होगा और यह सार्वजनिक हित के विरुद्ध होगा।
- vi. यदि घरेलू उद्योग के पास बढ़ती घरेलू मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता नहीं है, तो आयात केवल एक विकल्प नहीं है, बल्कि निचले स्तर के दवा उद्योग के लिए आपूर्ति घाटे को रोकने के लिए एक आवश्यकता है।

त्र.2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

104. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- i. बाजार से उपलब्ध सूचना के अनुसार, अंतिम प्रयोक्ताओं पर पाटनरोधी शुल्कों का नगण्य प्रभाव पड़ेगा। विचाराधीन उत्पाद का प्रयोग मुख्य रूप से फार्मास्युटिकल एपीआई के निर्माण और अन्य पायराजोलिन और संबंधित व्युत्पन्नों के संश्लेषण में किया जाता है। इस तरह के उत्पादों की कीमत 8,000 रुपये प्रति किलोग्राम से लेकर 14,000 रुपये प्रति किलोग्राम तक है। यह नोट करना व्यावहारिक है कि अंतिम कीमत संबद्ध सामानों की कीमत पर निर्भर नहीं है। यह इस तथ्य से सिद्ध है कि क्षति की अवधि में संबद्ध सामानों की कीमतें घटकर आधी हो गई हैं, तथापि, आवेदक के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार निचले स्तर के उत्पादों की बिक्री कीमतों में ऐसी कोई गिरावट नहीं आई है।
- ii. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया गया यह अनुरोध कि शुल्क लगाना जनहित में नहीं होगा, गलत है क्योंकि यह गलत आधार पर आधारित है।

- iii. शुल्क लगाना न केवल देश में संबद्ध सामानों के उत्पादकों के बने रहने के लिए मौलिक होगा बल्कि इससे सामान्य जनहित का काम भी होगा।
- iv. जांच की अवधि से पूर्व, निम्नलिखित उद्योग आवेदक के अलावा, भारत में संबद्ध सामानों का उत्पादन कर रहे थे:
- क) सौरव केमिकल्स
ख) एस. वी. लैब्स
ग) ईथर इंडस्ट्रीज लिमिटेड
घ) विजयश्री ऑर्गेनिक्स
ड.) एलिमेंट केमलिक
- v. तथापि, सौरव केमिकल्स जैसे प्रमुख उत्पादकों सहित उपरोक्त सभी विनिर्माताओं ने या तो उत्पादन में गंभीर कटौती की है या संबद्ध सामानों का उत्पादन पूरी तरह से बंद कर दिया है। यह गंभीर स्थिति सीधे तौर पर घरेलू उत्पादन लागत से काफी नीचे पहुंच मूल्य पर कीमत वाले पाटित आयातों से उत्पन्न होती है, जिससे निरंतर प्रचालन आर्थिक रूप से अस्थिर हो जाते हैं। कुछ शेष उत्पादक केवल प्रमुख ग्राहकों को बनाए रखने के लिए बने रहते हैं, बाजार की उपस्थिति बनाए रखने के लिए एक हताश बोली में गंभीर हानियां उठाते हैं।
- vi. यह अनुरोध किया जाता है कि पाटनरोधी शुल्कों की अनुपस्थिति में, घरेलू उत्पादकों के पास पूरी तरह से दुकान बंद करने, घरेलू क्षमता को समाप्त करने और निचल स्तर के प्रयोक्ताओं को पूरी तरह से संबद्ध देश से आयातों पर निर्भर रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा।
- vi. यह भी अनुरोध किया जाता है कि संबद्ध सामान मुख्य रूप से केवल संबद्ध देश और भारत में उत्पादित किए जाते हैं। घरेलू उद्योगों के संरक्षण की आवश्यकता जहां वैश्विक आपूर्ति अत्यधिक केंद्रित है और जहां पहुंच से इनकार करने से तत्काल और विषम राष्ट्रीय लागतें लागू होंगी, भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण (2025-26) में उपयुक्त रूप से उजागर किए गए संगत उद्धरण नीचे दिए गए हैं:
- "16.33। इस स्तर [टियर I] में सामान, घटक और प्रौद्योगिकियां शामिल हैं जहां पहुंच से इनकार करने से तत्काल और असमान राष्ट्रीय लागतें लागू होंगी, और जहां वैश्विक आपूर्ति अत्यधिक केंद्रित है। विशिष्ट उदाहरणों में रक्षा-महत्वपूर्ण प्रणालियाँ, मुख्य बुनियादी ढांचा निवेश, ऊर्जा सुरक्षा घटक, सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक वस्तुएं और मूलभूत औद्योगिक प्रौद्योगिकियां शामिल हैं।*
- 16.34. टियर I मदों के लिए, उद्देश्य तनाव में उपलब्धता सुनिश्चित करना है, न कि अल्पकालिक दक्षता। घरेलू उत्पादन उचित हो सकता है, भले ही यह शुरू में महंगा हो... "*
- viii. यह नोट करना भी व्यावहारिक है कि संबद्ध सामानों के किसी भी प्रयोक्ता ने शुल्क लगाने के लिए वर्तमान आवेदन-पत्र का विरोध नहीं किया है। संबद्ध सामानों प्रयोक्ताओं द्वारा विरोध का अभाव भी स्पष्ट रूप से यह दर्शाता है कि प्रयोक्ता इस उद्योग की विकट स्थिति और शुल्क लगाने की आवश्यकता से भी अवगत हैं।

ब.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

105. प्राधिकारी नोट करते हैं कि व्यापार उपचारात्मक उपायों का प्राथमिक उद्देश्य अनुचित व्यापार परिपाटियों द्वारा घरेलू उद्योग को होने वाले क्षतिकारक प्रभावों का मुकाबला करना और भारतीय बाजार में खुली और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बहाल करना है, जो देश के सामान्य हित में है। व्यापार उपचारात्मक उपायों का उद्देश्य संबद्ध देश से आयात को सीमित करना नहीं है। इसके विपरीत, प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि उपायों के सकारात्मक

प्रभाव घरेलू उद्योग के और बिगड़ने को रोकते हैं, जिससे संबद्ध सामानों के उपभोक्ताओं को प्रतिस्पर्धी और विविधकृत आपूर्ति बनी रहती है।

106. प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों से विचार आमंत्रित करते हुए जांच शुरुआत अधिसूचना जारी की। प्राधिकारी ने प्रयोक्ताओं/उपभोक्ताओं को उनके प्रचालनों के संबंध में उपायों के किसी भी संभावित प्रभाव सहित वर्तमान जांच के बारे में संगत सूचना प्रदान करने के लिए एक प्रश्नावली भी निर्धारित की। विभिन्न देशों के विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पाद की परस्पर परिवर्तनीयता, उपभोक्ताओं पर उपायों के प्रभाव आदि के संबंध में अन्य बातों के साथ-साथ सूचना मांगी गई थी। प्राधिकारी ने एक आर्थिक हित प्रश्नावली निर्धारित की थी जिसे इस जांच के लिए सभी हितबद्ध पक्षकारों को भेजा गया था। केवल घरेलू उद्योग और प्रतिभागी निर्यातक ने आर्थिक हित प्रश्नावली का उत्तर दिया है। किसी भी प्रयोक्ता और आयातक ने वर्तमान जांच में भाग नहीं लिया।
107. प्राधिकारी यह मानते हैं कि अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने आवश्यक दवाओं की लागत में वृद्धि के बारे में चिंता व्यक्त करते हुए, प्रस्तावित उपाय से उत्पन्न होने वाली वृद्धिशील लागत का कोई भी अनुमान, किसी भी मात्रात्मक सामग्री को रिकॉर्ड पर नहीं रखा है। घरेलू उद्योग ने भी प्रभाव की मात्रा निर्धारित नहीं की है, यह दर्ज करते हुए कि "अंतिम उपयोग वाले उत्पादों पर शुल्क के प्रभाव की सटीक मात्रा निर्धारित करना बेहद मुश्किल है"। संबद्ध सामानों के प्रयोक्ता जो इस तरह के प्रभाव की मात्रा निर्धारित करने के लिए सबसे अच्छी स्थिति में हैं, उन्होंने जांच में भाग नहीं लिया है और न तो उपाय का विरोध किया है और न ही किसी भी चिंता को रिकॉर्ड में रखा है। तथापि, प्राधिकारी ने अंतिम उत्पादों में से एक अर्थात् उपलब्ध सूचना के आधार पर उपभोक्ताओं/रोगियों के लिए लोसार्टन 50 मिलीग्राम की गोलियों पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव की मात्रा निर्धारित की है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

विवरण	विवरण	टिप्पणियां
1 किलोग्राम लोसार्टन पोटेशियम के लिए ब्रोमो-ओटीबीएन की आवश्यकता।	1.15 किग्रा.	एसआईओएन मानदंडों के अनुसार
अपेक्षित पाटनरोधी शुल्क (पाटन मार्जिन)	डॉ.5,688/- एमटी	सहयोगी उत्पादकों का औसत पाटन मार्जिन
1 किलो लोसार्टन लागत (रु.) का प्रभाव	621.41	विनिमय दर 95 रु. प्रति डॉलर
1 टैबलेट 50 एमजी पर प्रभाव (रु.)	0.03	50 एमजी की सामान्य खुराक
मासिक लागत पर प्रभाव (रु.)	0.93	30 टैबलेट के लिए
लोसार्टन 50एमजी 30 टैबलेट की एमआरपी लगभग (रु.)	150	
एमआरपी के प्रतिशत के रूप में रोगियों पर प्रभाव	0.62%	

108. यह देखा जाता है कि उपभोक्ताओं पर पाटनरोधी शुल्कों का प्रभाव नगण्य है। प्राधिकारी घरेलू उद्योग के इस अनुरोध को भी नोट करते हैं कि संबद्ध सामानों का उपयोग करके निर्मित निचले स्तर के उत्पाद भारत सरकार के कीमत नियंत्रण उपायों के अध्वधीन हैं। प्राधिकारी द्वारा सिफारिश किए हुए किसी भी उपाय को किसी भी स्थिति में कमतर शुल्क नियम को लागू करके जांचा जाएगा ताकि घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए आवश्यक से अधिक न हो। पूर्वोक्त को ध्यान में रखते हुए, और निचले स्तर के प्रयोक्ता या अंतिम उपभोक्ताओं पर वास्तविक प्रतिकूल प्रभाव दर्शाने वाले किसी भी मात्रात्मक साक्ष्य के अभाव में, प्राधिकारी का यह मत है कि वर्तमान जांच के तथ्यों पर पाटनरोधी उपाय लागू करना व्यापक सार्वजनिक हित के अनुरूप है, जिसमें एक

आवश्यक दवा मध्यवर्ती के लिए एक व्यवहार्य घरेलू विनिर्माण आधार बनाए रखने का हित भी शामिल है, जहां वैश्विक आपूर्ति कुछ देशों में अत्यधिक केंद्रित है।

109. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध सामानों की घरेलू मांग और उपलब्ध स्वदेशी उत्पादन क्षमता के बीच एक अंतर मौजूद है। तथापि, प्राधिकारी यह स्पष्ट करते हैं कि मांग-आपूर्ति अंतराल की मौजूदगी, अपने आप में, पाटनरोधी उपाय के लिए मामले को विस्थापित नहीं करता है। वर्तमान जांच का विषय यह नहीं है कि क्या संबद्ध सामानों का आयात होना चाहिए या नहीं, बल्कि यह है कि इस तरह के आयात किस कीमत पर होते हैं। प्राधिकारी की जांच ने यह सिद्ध किया है कि संबद्ध देश से आयात घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत से कम कीमतों पर भारतीय बाजार में आए हैं, इस तरह के आयात ने घरेलू कीमतों का न्यूनीकरण और ह्रास किया है और यह कि घरेलू उद्योग को तदनुसार अलाभकारी कीमतों पर संबद्ध सामानों की बिक्री करने के लिए और उत्पादन और बिक्री की मात्रा में वृद्धि के बावजूद निरंतर हानियां उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। आपूर्ति अंतराल को उचित कीमतों पर आयात के माध्यम से पूरा किया जा सकता है, जब क्षतिकारक पाटन ठीक किया जाए।
110. प्राधिकारी का मानना है कि अन्य भारतीय उत्पादकों द्वारा उत्पादन में कटौती या रोक लगाने के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किया गया अनुरोध रिकॉर्ड में उपलब्ध समर्थक साक्ष्य के साथ प्रमाणित नहीं किया गया है। तदनुसार, प्राधिकारी इस अनुरोध पर जांच परिणाम दर्ज करने की स्थिति में नहीं है। इस तथ्य पर विचार करते हुए कि संबद्ध सामानों के आयात घरेलू उद्योग की लागत से काफी कम पर हो रहे हैं, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की स्थिति संबद्ध देश से आयातों के कारण सुभेद्य है। घरेलू उद्योग को जांच की अवधि सहित क्षति की अवधि में हानियां हो रही थीं।

ट. प्रकटन पश्चात टिप्पणियां

ट.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

111. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटन विवरण के संबंध में निम्नलिखित टिप्पणियां प्रस्तुत की गई हैं:
- प्राधिकारी द्वारा डोंगगांग के लिए प्रकटन की गई निर्यात कीमत और पहुंच मूल्य की अंतिम जांच परिणाम में पुष्टि की जानी चाहिए। इन निर्धारणों में किसी भी बदलाव की स्थिति में, प्रतिवादी, प्राधिकारी से एक संशोधित प्रकटन विवरण जारी करने और उस पर टिप्पणी करने का अवसर प्रदान करने का अनुरोध करता है।
 - चीन जनवादी गणराज्य को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में माना जाना जारी रखना कानूनी आधार के बिना है। चीन के एक्सेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क) का प्रावधान, जो प्रतिनिधि देश पद्धति के उपयोग की अनुमति देता है, 11 दिसंबर 2016 को समाप्त हो गया है। समाप्ति के पश्चात, भारत सहित विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों के लिए यह आवश्यक है कि वे चीन के उत्पादकों की घरेलू कीमतों और लागतों या सत्यापित निर्यातक आकड़ों का उपयोग करके डब्ल्यूटीओ पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 2 के अनुसार सामान्य मूल्य का निर्धारण करें। निर्यातक आकड़ों की जांच किए बिना अनुबंध-1 के पैरा 7 को यांत्रिक रूप से लागू करना भारत के डब्ल्यूटीओ दायित्वों के असंगत होगा। प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे प्रतिवादी निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत वास्तविक लागत और कीमत संबंधी जानकारी की जांच करें और उसी आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण करें।
 - लिन्हाई हुआनान केमिकल क. लि. ने वर्तमान जांच में पूर्ण सहयोग दिया है और पूरी जानकारी प्रदान की है। तथापि, प्राधिकारी ने सहयोगी हिस्से के लिए सत्यापित निर्यात कीमत को उन असंबंधित गैर-सहयोगी व्यापारियों के माध्यम से निर्यात की गई मात्रा के लिए उपलब्ध-तथ्यों वाली निर्यात कीमत के साथ जोड़कर भारत और निर्यात कीमत का निर्धारण किया है, जिन पर उत्पादक/निर्यातक का कोई नियंत्रण नहीं है। पाटनरोधी नियमावली व्यक्तिगत पाटन मार्जिन के निर्धारण के लिए एक अनिवार्य पूर्व-शर्त के रूप में निर्यात श्रृंखला में प्रत्येक व्यापारी की भागीदारी को निर्धारित नहीं करती है। उपलब्ध-तथ्यों के

अनुप्रयोग ने प्रकटन किए गए पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन दोनों को कृत्रिम रूप से बढ़ा दिया है। प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे केवल सहयोगी कंपनियों द्वारा प्रस्तुत सत्यापित जानकारी के आधार पर ही निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण करें।

- iv. चीन जनवादी गणराज्य से होने वाले कथित पाटित आयातों और घरेलू उद्योग द्वारा दावा किए गए वित्तीय नुकसान के बीच कोई प्रमाणित कारणात्मक संबंध नहीं है। घरेलू उद्योग को 2021-22 में भारी घाटा हो रहा था, जो एक ऐसी अवधि थी जब आयात की मात्रा अपने सबसे निचले स्तर पर थी। इसके विपरीत, जांच की अवधि में, जब आयात की मात्रा अपने उच्चतम स्तर पर थी, घरेलू उद्योग का प्रति-इकाई नुकसान आधार वर्ष की तुलना में 40% से अधिक कम हो गया। आयातों के पहुंच मूल्य में गिरावट की दर, घरेलू उद्योग की बिक्री लागत में गिरावट की दर से कम है। यह सिद्ध करता है कि आयात घरेलू उद्योग पर कीमत संबंधी दबाव नहीं डाल रहे हैं।
- v. प्राधिकारी ने पाया है कि जांच की अवधि के दौरान चीन जनवादी गणराज्य से होने वाले आयातों से कीमत कटौती ऋणात्मक है, जो यह सिद्ध करता है कि आयातों का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से अधिक था। ऐसी परिस्थितियों में, यह नहीं कहा जा सकता कि आयातों ने घरेलू कीमतों में ह्रास या न्यूनीकरण किया है या घरेलू उद्योग को अपनी कीमतें बढ़ाने से रोका है। इन परिस्थितियों में कीमत संबंधी क्षति का निष्कर्ष रिकॉर्ड पर मौजूद तथ्यों से असंगत है।
- vi. प्राधिकारी द्वारा जांच किए गए आर्थिक मापदंड वास्तविक क्षति की पुष्टि नहीं करते हैं। रिकॉर्ड पर मौजूद आकड़े जांच की अवधि के दौरान प्रमुख मापदंडों में सुधार दिखाता है, जिसमें उत्पादन, बिक्री, क्षमता उपयोग, उत्पादकता, रोजगार, मजदूरी और बाजार हिस्सेदारी शामिल हैं। लाभप्रदता संकेतक जैसे कि कर-पूर्व लाभ, नकद लाभ, और नियोजित पूंजी पर आय ने भी पिछले वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान सुधार दर्शाया है। जब अधिकांश आर्थिक मापदंड सुधार दर्शाते हैं, तो वास्तविक क्षति का निष्कर्ष न्यायसंगत नहीं है।
- vii. क्षतिरहित कीमत के निर्धारण के लिए औसत नियोजित पूंजी पर एक समान 22% कर-पूर्व आय को अपना अत्यधिक है और पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-III के तहत "उचित आय" की अपेक्षा के असंगत है। नियोजित पूंजी में एक ऋण घटक शामिल होता है जिस पर पहले से ही व्याज लागत लगती है। संपूर्ण पूंजी आधार पर एक समान 22% आय लागू करने के परिणामस्वरूप इकट्टी पर कृत्रिम रूप से बढ़ी हुई आय प्राप्त होती है, जो क्षतिरहित कीमत को बढ़ा देता है और क्षति मार्जिन निर्धारण को विकृत करता है।
- viii. चल रहे रूस-यूक्रेन युद्ध के परिणामस्वरूप वैश्विक व्यापार और आपूर्ति श्रृंखलाओं में काफी व्यवधान उत्पन्न हुए हैं, जिससे कच्चे माल की उपलब्धता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, ऊर्जा और संभार तंत्र लागत में वृद्धि हुई है, और अंतर्राष्ट्रीय परिवहन में अनिश्चितताएं पैदा हुई हैं। इन घटनाक्रमों का ब्रोमो ओटीबीएन सहित रासायनिक मध्यवर्ती वस्तुओं के उत्पादन, कीमत निर्धारण और आपूर्ति पर सीधा प्रभाव पड़ा है, और यह एक प्रासंगिक गैर-आरोपण कारक है जिसकी जांच प्राधिकारी द्वारा क्षति, कारणात्मक संबंध और जनहित का आकलन करते समय की जानी चाहिए।
- ix. घरेलू उद्योग को हुई क्षति, यदि कोई हो, चीन जनवादी गणराज्य से होने वाले कथित पाटित आयातों के अलावा अन्य कारकों के कारण है। घरेलू उद्योग की वर्ष 2024-25 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट आपूर्ति श्रृंखला की बाधाओं, भू-राजनीतिक तनावों, व्यापार नीति की अनिश्चितताओं, बदलती टैरिफ दरों और निरंतर मालसूची समाप्त करने की पहचान प्राथमिक चुनौतियों के रूप में करती है। ये कारक कथित पाटन से पूरी तरह से असंबंधित हैं और इन्हें किसी भी क्षति का मुख्य कारण माना जाना चाहिए।

- x. ब्रोमो ओटीबीएन के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाना जनहित के विपरीत होगा। घरेलू उद्योग ने पूरी घरेलू मांग को विश्वसनीय रूप से पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता प्रदर्शित नहीं की है। शुल्क लगाने से भारतीय दवा निर्माताओं के लिए इनपुट लागत बढ़ जाएगी, उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, और सीधे सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़े क्षेत्र में आपूर्ति-शृंखला के जोखिम उत्पन्न होंगे।

ट.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

112. घरेलू उद्योग द्वारा प्रकटन विवरण के संबंध में निम्नलिखित टिप्पणियां की गई हैं:

- i. घरेलू उद्योग प्रकटन विवरण में प्राधिकारी द्वारा व्यक्त किए गए विचारों से सहमति व्यक्त करता है और प्राधिकारी से अनुरोध करता है कि अंतिम जांच परिणाम में इन विचारों को इसी प्रकार रखा जाए।
- ii. जहां तक प्रकटन विवरण के पैरा 27 और 28 में सीसीसीएमएचपीआईईई को एक पात्र हितबद्ध पक्ष माने जाने की पात्रता के संबंध में प्राधिकारी की टिप्पणी का प्रश्न है, यह मुद्दा एक कानूनी मुद्दा है न कि तथ्यों पर कोई विवाद है। यह सिद्ध होता है कि किसी कानूनी कार्य की वैधता से जुड़े मुद्दों पर किसी भी चरण में प्रश्न उठाया जा सकता है और इसे समय-बाधित नहीं माना जा सकता है। जब तक कि हितबद्ध पक्षकार या सीसीसीएमएचपीआईईई अपनी टिप्पणियों के माध्यम से जांच में उक्त पक्ष की स्थिति को सिद्ध नहीं कर देते, तब तक सीसीसीएमएचपीआईईई को एक पात्र हितबद्ध पक्षकार के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।
- iii. जहां तक प्रकटन विवरण में निर्धारित प्रयोक्ताओं पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव की गणना का संबंध है, इस प्रभाव की गणना अंतिम उपभोक्ताओं (मरीजों) पर पड़ने वाले प्रभाव के आधार पर की गई है। संबद्ध वस्तुओं के डाउनस्ट्रीम प्रयोक्ताओं पर प्रभाव और भी अधिक मामूली होगा और उनके द्वारा इसे आसानी से अवशोषित किया जा सकता है। यद्यपि डाउनस्ट्रीम प्रयोक्ताओं पर प्रभाव मामूली होगा, वही संबद्ध वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों को महत्वपूर्ण राहत प्रदान करेगा, जिससे पीड़ित घरेलू उद्योग को अनिवार्य रूप से पुनर्जीवित किया जा सकेगा।
- iv. जहां तक मांग-आपूर्ति के अंतर की उपस्थिति के संबंध में प्राधिकारी की टिप्पणी का संबंध है, वास्तव में भारत में संबद्ध वस्तुओं के लिए कोई मांग-आपूर्ति का अंतर नहीं है। अन्य दो मौजूदा उत्पादकों की क्षमताएं घरेलू उद्योग के लगभग समान हैं। इसके अलावा, अन्य निर्माता जिन्होंने उत्पादन बंद कर दिया है और ब्रोमिनेशन-आधारित दवाओं के निर्माता जैसे कि आरती इंडस्ट्रीज, कम कीमत वाले पाटित आयातों के न होने की स्थिति में, आसानी से संबद्ध वस्तुओं का निर्माण कर सकते थे।
- v. जहां तक प्राधिकारी की इस टिप्पणी का संबंध है कि घरेलू उद्योग ने अन्य भारतीय उत्पादकों द्वारा उत्पादन में कटौती या उसे बंद करने के संबंध में अपने अनुरोध की पुष्टि नहीं की है, प्रत्येक उत्पादक के उत्पादन से जुड़े विवरण गोपनीय हैं और घरेलू उद्योग के पास उपलब्ध नहीं थे। तथापि, यह अनुरोध लिखित अभ्यावेदनों में किया गया था जिसे सभी हितबद्ध पक्षकारों को परिचालित किया गया था, और किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने इस पर विवाद नहीं किया है। घरेलू उद्योग यह भी अनुरोध करता है कि संबद्ध वस्तुओं के एक उत्पादक, अर्थात् सौरव केमिकल्स ने प्राधिकारी के समक्ष एक अनुरोध प्रस्तुत किया है। यद्यपि प्रक्रियात्मक मुद्दों के कारण उक्त अनुरोध को रिकॉर्ड में नहीं लिया गया है, फिर भी उसमें निहित आकड़ों/जानकारी का उपयोग घरेलू उद्योग के अनुरोध को सत्यापित करने के लिए किया जा सकता है।
- vi. घरेलू उद्योग प्राधिकारी से पाटनरोधी शुल्क को एक निश्चित आधार पर लगाने की सिफारिश करने का अनुरोध करता है। क्षति जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं की कीमतों में महत्वपूर्ण उतार-चढ़ाव यह दर्शाता है कि संदर्भ कीमत-आधारित शुल्क संबद्ध वस्तुओं के आयात के विरुद्ध प्रभावी नहीं हो सकता है।
- vii. घरेलू उद्योग प्राधिकारी से अनुरोध करता है कि चीन के निर्यातकों द्वारा किए जा रहे पाटन के कारण घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचने के संबंध में अपने निष्कर्षों को इसी प्रकार रखे, और घरेलू उद्योग को पाटित और क्षतिकारी आयातों से बचाने के लिए जल्द से जल्द पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करे।

ट.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

113. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रकटन-पश्चात अनुरोधों की जांच की है। यह देखा गया है कि इनमें से अधिकांश अनुरोध उन तर्कों और दावों की पुनरावृत्ति हैं जिनकी पहले ही जांच की जा चुकी है और इन अंतिम जांच परिणाम के संगत पैराग्राफों में आवश्यक सीमा तक उनका समाधान किया जा चुका है। संक्षिप्तता के लिए, प्राधिकारी ने इस प्रकटन-पश्चात जांच में ऐसे अनुरोधों के उत्तरों को दोहराने का परिहार किया है। तथापि, प्रकटन-पश्चात टिप्पणियों में पहली बार उठाए गए नए अनुरोधों, और साथ ही पहले संबोधित किए जा चुके लेकिन आगे जांच के लिए आवश्यक समझे गए अनुरोधों को नीचे संबोधित किया गया है।
114. लिन्हाई ग्रुप के इस अनुरोध के संबंध में कि चीन जनवादी गणराज्य को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में मानना कानूनी आधार के बिना है और चीन के एक्सेसन प्रोटोकॉल का अनुच्छेद 15(क), जो प्रतिनिधि देश पद्धति के उपयोग की अनुमति देता है, 11 दिसंबर 2016 को समाप्त हो गया है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यह दावा लागू कानूनी स्थिति द्वारा समर्थित नहीं है। प्राधिकारी द्वारा सामान्य मूल्य का निर्धारण पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के साथ पठित चीन के एक्सेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क)(i) पर आधारित है, जो वर्तमान जांच में कानूनी रूप से लागू पद्धति है। किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा रिकॉर्ड पर ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जो सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए पहली या दूसरी पद्धति को लागू करने का औचित्य साबित करे। प्राधिकारी को इस दावे में कोई सत्यता नहीं दिखाई देती है।
115. लिन्हाई ग्रुप के इस अनुरोध के संबंध में कि असहयोगी असंबंधित व्यापारियों के माध्यम से किए गए निर्यात के हिस्से के लिए उपलब्ध-तथ्यों को लागू करना अनुचित है और इसने पाटन मार्जिन तथा क्षति मार्जिन को कृत्रिम रूप से बढ़ा दिया है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि असहयोगी भाग के लिए उपलब्ध-तथ्यों को लागू करना पाटनरोधी नियमावली के प्रावधानों के अनुसार है। लिन्हाई हुआनान की निर्यात कीमत सहयोगी हिस्से के लिए सत्यापित आकड़ों को असहयोगी हिस्से के लिए उपलब्ध-तथ्यों के आकड़ों के साथ जोड़कर एक भारित औसत के रूप में निर्धारित करती है, जो प्राधिकारी की स्थापित प्रथा के अनुरूप है। प्राधिकारी को इस अनुरोध में कोई तथ्य नहीं दिखाई देता है।
116. इस दावे के संबंध में कि घरेलू उद्योग के मात्रात्मक मापदंड पर्याप्त सुधार दर्शाते हैं और यह वास्तविक क्षति के निष्कर्ष को खारिज करता है, प्राधिकारी यह दोहराते हैं कि पाटनरोधी नियमावली के तहत क्षति का निर्धारण करने के लिए सभी प्रासंगिक आर्थिक कारकों की निष्पक्ष जांच आवश्यक है। घरेलू उद्योग जांच की अवधि सहित संपूर्ण क्षति जांच अवधि के दौरान लगातार घाटे में रहा है, पाटित आयातों के कीमत ह्रास और कीमत न्यूनीकरण प्रभाव के कारण अपनी उत्पादन लागत के अनुरूप कीमत प्राप्त करने में असमर्थ रहा है, और अपनी उत्पादन क्षमता के अनुरूप बाजार हिस्सेदारी हासिल करने में असमर्थ रहा है। जांच की अवधि में कुछ मात्रात्मक मापदंडों में सुधार, समग्र मूल्यांकन में, वास्तविक क्षति संबंधी निष्कर्ष को निष्प्रभावी नहीं करता है।
117. इस अनुरोध के संबंध में कि कथित पाटित आयातों और घरेलू उद्योग के वित्तीय निष्पादन के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि कारणात्मक संबंध विश्लेषण उस कीमत के बीच के संबंध की जांच करता है जिस पर पाटित आयात बाजार में प्रवेश करते हैं और घरेलू उद्योग की कीमत निर्धारण तथा लाभप्रदता की जांच करता है, न कि केवल आयातों की मात्रा के उतार-चढ़ाव की। चीन जनवादी गणराज्य से होने वाले पाटित आयातों का पहुंच मूल्य संपूर्ण क्षति जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से काफी कम रहा है, जिससे उसे लागत से कम पर बेचने और लगातार घाटा उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। पहुंच मूल्य बनाम उत्पादन लागत के अंतर और घरेलू उद्योग के प्रति-इकाई नुकसान के बीच सीधे संबंध को इन अंतिम जांच परिणाम के संगत पैराग्राफों में सिद्ध किया गया है।
118. इस अनुरोध के संबंध में कि क्षति, यदि कोई हो, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान, भू-राजनीतिक तनाव, कच्चे माल की कीमतों में सुधार, और रूस-यूक्रेन संघर्ष सहित अन्य कारकों के कारण हुई है, प्राधिकारी ने इन अंतिम जांच

परिणाम के संगत पैराग्राफों में एक गैर-आरोपण विश्लेषण किया है और पाटित आयातों के अलावा उन सभी कारकों की जांच की है जो क्षति का कारण बन सकते थे। क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के कच्चे माल की कीमतें और आयातों का पहुंच मूल्य एक ही दिशा में बढ़े हैं। तथापि, आयातों का पहुंच मूल्य संपूर्ण अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत से काफी कम रहा है। दावा किए गए अन्य कारक यह निष्कर्ष निकालने का कोई आधार प्रदान नहीं करते हैं कि घरेलू उद्योग को हुई क्षति पाटित आयातों के कारण नहीं हुई है।

119. लिन्हाई ग्रुप के इस अनुरोध के संबंध में कि क्षतिरहित कीमत की गणना के लिए अपनाया गया 22% का आरओसीई अत्यधिक है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि औसत नियोजित पूंजी पर 22% की कर-पूर्व आय यथा-संशोधित पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-III के अधीन एक स्थापित प्रथा है, जिसे सभी जांचों में समान रूप से लागू किया जाता है। प्राधिकारी को इस अनुरोध में कोई आधार नहीं दिखता है।
120. इस दलील के संबंध में कि यदि किसी उपाय की सिफारिश की जाती है, तो वह संदर्भ कीमत के रूप में होनी चाहिए, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने क्षति जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं की कीमतों में देखे गए महत्वपूर्ण उतार-चढ़ाव को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से एक नियत आधार पर शुल्क की सिफारिश करने का अनुरोध किया है। प्राधिकारी ने अपनी सिफारिश पर पहुंचने के लिए उपाय के प्रारूप से संबंधित सभी संगत अनुरोधों पर विचार किया है।
121. जनहित से जुड़े अनुरोधों के संबंध में, प्राधिकारी इन अंतिम जांच परिणाम के संगत पैराग्राफों में दर्ज अपने निष्कर्षों को दोहराते हैं। डाउनस्ट्रीम भेषज प्रयोक्ताओं और अंतिम उपभोक्ताओं पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव की गणना की गई है और इसे नगण्य पाया गया है। वर्तमान जांच में किसी भी उपयोगकर्ता या आयातक ने भाग नहीं लिया है और डाउनस्ट्रीम प्रयोक्ताओं पर पड़ने वाले किसी भी महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव का कोई मात्रात्मक साक्ष्य रिकॉर्ड पर नहीं रखा गया है। संबद्ध वस्तुओं का उपयोग करके निर्मित डाउनस्ट्रीम एपीआई भारत सरकार के कीमत नियंत्रण उपायों के अधीन हैं। प्राधिकारी का यह विचार बना हुआ है कि वर्तमान जांच में पाटनरोधी उपाय लागू करना व्यापक जनहित के अनुरूप है, जिसमें एक आवश्यक फार्मास्युटिकल मध्यवर्ती वस्तु के लिए एक व्यवहार्य घरेलू विनिर्माण आधार बनाए रखने का हित भी शामिल है। प्राधिकारी को जनहित के आधार पर शुल्क न लगाने की मांग करने वाले अनुरोधों में कोई योग्यता नहीं दिखती है।
122. सीसीसीएमएचपीआईई की एक हितबद्ध पक्षकार के रूप में पात्रता के संबंध में घरेलू उद्योग के अनुरोध के संबंध में, इस प्रश्न पर विचार किया गया है और इन अंतिम जांच परिणाम के संगत पैराग्राफों में इस पर ध्यान दिया गया है।
123. मांग-आपूर्ति में कोई अंतर न होने के संबंध में घरेलू उद्योग के अनुरोध के संबंध में, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के अलावा, भारत में संबद्ध वस्तुओं के अन्य उत्पादक भी मौजूद हैं। पाटनरोधी उपाय लागू करने से पाटित आयातों के कारण उत्पन्न हुई कीमत विकृति ठीक होगी और भारतीय बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा बहाल होगी। घरेलू आपूर्ति और मांग के बीच किसी भी अवशिष्ट अंतर को उचित कीमतों पर आने वाले आयातों के माध्यम से पूरा किया जाना जारी रखा जा सकता है।

ठ. निष्कर्ष

124. जैसा कि उपरोक्त निष्कर्षों में दर्ज किया गया है, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए दावों, प्रदान की गई जानकारी, और प्रस्तुत किए गए अनुरोधों तथा प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, और पाटन, क्षति, कारणात्मक संबंध तथा जनहित के उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर, प्राधिकारी निम्नलिखित निष्कर्ष निकालते हैं:
- i. विचाराधीन उत्पाद 4-(ब्रोमोमिथाइल)-2'-साइनोबाइफेनिल है, जिसे 'ब्रोमो ओटीबीएन' के रूप में भी जाना जाता है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित समान वस्तु सभी वास्तविक पहलुओं के संबंध में विचाराधीन उत्पाद के समान या सदृश है।

- ii. मेसर्स नियोजन केमिकल्स लिमिटेड पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग का निर्माण करती है, और यह आवेदन नियम 5(3) के संदर्भ में स्थिति संबंधी मानदंडों को पूरा करता है।
- iii. चीन जनवादी गणराज्य के सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन सकारात्मक है और न्यूनतम सीमा से काफी अधिक है। चीन जनवादी गणराज्य से होने वाले आयात भारतीय बाजार में अत्यधिक पाटित कीमत पर हुए हैं।
- iv. चीन जनवादी गणराज्य से संबद्ध वस्तुओं का आयात क्षति जांच अवधि के दौरान समग्र रूप में बढ़ा है, जांच की अवधि के दौरान यह अपने उच्चतम स्तर पर था, और भारतीय मांग में एक प्रमुख हिस्सेदारी रखता है।
- v. जांच की अवधि में कीमत कटौती ऋणात्मक है। घरेलू उद्योग ने रिकॉर्ड पर ऐसे साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं जो यह दर्शाते हैं कि आयातित कीमतों से मुकाबला करने के लिए ग्राहकों के दबाव के उत्तर में वह अपनी कीमतें कम करने के लिए बाध्य हुआ है। आयातों का पहुंच मूल्य संपूर्ण क्षति जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत से काफी कम रहा है, जिससे कीमत ह्रास और कीमत न्यूनीकरण की स्थिति उत्पन्न हुई है।
- vi. घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है। घरेलू उद्योग जांच की अवधि सहित संपूर्ण क्षति जांच अवधि के दौरान लगातार घाटा उठा रहा है, जिसमें नकद लाभ ऋणात्मक रहा है और नियोजित पूंजी पर आय भी ऋणात्मक रही है। चीन जनवादी गणराज्य के सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए क्षति मार्जिन सकारात्मक और काफी अधिक रहा है।
- vii. चीन जनवादी गणराज्य से होने वाले पाटित आयातों और घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति के बीच एक कारणात्मक संबंध मौजूद है। प्राधिकारी ने अन्य सभी ज्ञात कारणों की जांच की है जो क्षति का कारण बन सकते थे और यह निष्कर्ष निकाला है कि वे पाटित आयातों और क्षति के बीच के कारणात्मक संबंध को अस्वीकार नहीं करते हैं।
- viii. पाटनरोधी शुल्क लगाना व्यापक जनहित के अनुरूप है, जिसमें एक आवश्यक फार्मास्युटिकल मध्यवर्ती वस्तु के लिए एक व्यवहार्य घरेलू विनिर्माण आधार बनाए रखने का हित भी शामिल है, जहां वैश्विक आपूर्ति अत्यधिक संकेंद्रित है।

ड. सिफारिश

125. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच शुरू की गई थी और सभी हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित की गई थी तथा घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के पहलू पर सकारात्मक जानकारी प्रदान करने का पर्याप्त अवसर दिया गया था। पाटनरोधी नियमावली के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के संदर्भ में पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध की जांच शुरू करने और संचालित करने के बाद, प्राधिकारी का यह विचार है कि पाटन और क्षति की क्षतिपूर्ति के लिए शुल्क लगाना आवश्यक है। इसलिए, प्राधिकारी यह आवश्यक समझते हैं और चीन जनवादी गणराज्य से संबद्ध वस्तुओं के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं।
126. प्राधिकारी द्वारा अपनाए जाने वाले कमतर शुल्क नियम को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन दोनों में से जो भी कम हो, उसके बराबर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं, ताकि घरेलू उद्योग को हो रही क्षति को समाप्त किया जा सके। तदनुसार, प्राधिकारी चीन जनवादी गणराज्य में मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयात पर, केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से पांच (5) वर्ष की अवधि के लिए, नीचे दी गई शुल्क तालिका के कॉलम 7 में उल्लिखित राशि के बराबर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं।

शुल्क तालिका

क्र.सं.	एचएस कोड	विवरण	मूलता का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	राशि	इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	29269000, 29339990, 29332990, 29420090, और 29152990	4 (ब्रोमोमिथाइल)- 2'- सायनोबाईफिनाइल (ब्रोमो ओटीबीएन)	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई देश	यानचेंग सिटी डोंगगैंग फार्मास्युटिकल डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड	5,089	एमटी	अम.डा.
2.	-वही-	-वही-	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई देश	लिनहार्ड हुआनान केमिकल कंपनी लिमिटेड	5,500	एमटी	अम.डा.
3.	-वही-	-वही-	चीन जन. गण. सहित कोई देश	चीन जन. गण.	झेजियांग तियानयु फार्मास्युटिकल कंपनी लिमिटेड	5,440	एमटी	अम.डा.
4.	-वही-	-वही-	चीन जन. गण.	चीन जन. गण.सहित कोई देश	क्र.सं. 1 से 3 के अलावा कोई भी निर्माता	6,305	एमटी	अम.डा.
5.	-वही-	-वही-	चीन जन. गण. के अलावा कोई भी देश	चीन जन. गण.	कोई	6,305	एमटी	अम.डा.

नोट - उपर्युक्त उत्पादकों के लिए विनिर्दिष्ट अलग-अलग शुल्क दरों का अनुप्रयोग सीमा शुल्क अधिकारियों के समक्ष एक वैध वाणिज्यिक बीजक प्रस्तुत करने के अधीन होगा, जिस पर उक्त बीजक जारी करने वाले निर्माता के किसी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित और दिनांकित एक घोषणा अंकित होगी, जिसमें उस अधिकारी का नाम और पदनाम स्पष्ट रूप से उल्लिखित होगा, और जिसका प्रारूप निम्नानुसार होगा:

'मैं, अधोहस्ताक्षरी, यह प्रमाणित करता हूँ कि इस बीजक के अंतर्गत भारत को निर्यात के लिए बेची गई (विचाराधीन उत्पाद) की (मात्रा) का विनिर्माण (उत्पादक का नाम और पता) द्वारा (देश का नाम) में किया गया था। मैं यह घोषित करता/करती हूँ कि इस बीजक में प्रदान की गई जानकारी पूर्ण और सही है।' यदि ऐसा कोई बीजक प्रस्तुत नहीं किया जाता

है, तो अन्य सभी उत्पादकों पर लागू होने वाला शुल्क देय होगा। यह अपेक्षा लागू सीमा शुल्क कानून और विनियमों के तहत सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा स्वतंत्र रूप से की जाने वाली सत्यापन प्रक्रियाओं पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी।"

आगे की प्रक्रिया

127. इस अंतिम जाँच परिणाम में निर्दिष्ट प्राधिकारी के निर्धारण के विरुद्ध कोई अपील अधिनियम/नियमावली के संगत प्रावधानों के अनुसार सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष की जा सकती है।

अमिताभ कुमार , निर्दिष्ट प्राधिकरण

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

FINAL FINDINGS NOTIFICATION

New Delhi, the 24th June, 2026

Case No. AD(OI) - 20/2025

Subject: Anti-dumping duty investigation concerning imports of "4- (Bromomethyl)-2'-cyanobiphenyl" also known as "Bromo OTBN" originating in or exported from China PR.

F. No. 6/23/2025-DGTR.— Having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the "Act"), and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the "Anti-Dumping Rules" or the "Rules");

A. BACKGROUND

1. M/s Neogen Chemicals Limited (hereinafter also referred to as the "Petitioner" or "Applicant") has filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the "Authority") in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter also referred to as "AD Rules, 1995" or the "AD Rules" or the "Rules") for imposition of anti-dumping duty on imports of "4- (Bromomethyl)-2'-cyanobiphenyl" also known as "Bromo OTBN" (hereinafter also referred to as the "subject goods" or "product under consideration" or "PUC") from China PR (hereinafter also referred to as the "subject country").
2. Whereas, the Authority, on the basis of sufficient *prima facie* evidence submitted by the applicant, issued a Notification No.6/23/2025-DGTR dated 30th June, 2025, published in the Gazette of India, initiating the subject investigation in accordance with Rule 5 of the AD Rules to determine existence, degree and effect of the alleged dumping of the subject goods, originating in or exported from China PR, and to recommend the amount of anti-dumping duty, which, if levied, would be adequate to remove the alleged injury to the domestic industry.

B. PROCEDURE

3. The procedure described herein below has been followed by the Authority with regard to the subject investigation:
 - i. The Designated Authority, under the AD Rules, received a written application from the Applicant on behalf of the domestic industry, alleging dumping of subject goods, originating in or exported from China PR.
 - ii. The Authority notified the Embassy of China PR in India about the receipt of the anti-dumping application before proceeding to initiate the investigation in accordance with sub-rule (5) of Rule 5 supra.

- iii. The Authority issued a public notice dated 30th June 2025 published in the Gazette of India Extraordinary, initiating the anti-dumping investigation concerning imports of the subject goods from the subject country.
- iv. The Authority sent a copy of the initiation notification to the Embassy of China PR in India, known producers/exporters from China PR and the domestic industry as per the addresses made available by the applicant and requested them to make their views known in writing within the time limit prescribed by the Authority in accordance with the Rule 6(4).
- v. The Authority sent exporter's questionnaires to elicit relevant information to the following known producers/exporters in China PR, (whose details were made available by the applicant) and gave them opportunity to make their views known in writing in accordance with the Rule 6(2) of the AD Rules.
 - a) Yancheng City Donggang
 - b) Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co Limited
 - c) Cidic Co. Limited
 - d) Zhejiang Tianyu Pharmaceutical Co. Ltd.
 - e) Sinolite Industrial Co. Limited
 - f) Jiangsu Gtig Huatai Co. Limited
 - g) Luna Chemicals Co. Limited
- vi. The Authority also issued an economic interest questionnaire (hereinafter referred to as 'EIQ') to the interested parties seeking inputs on the economic impact of the proposed duties.
- vii. In response to the initiation of the subject investigation, the following producers/exporters from the subject country have responded by filing questionnaire response:
 - a) Nantong Huayu Chemical Technology Co., Ltd.
 - b) Linhai Huanan Chemical Co., Ltd.
 - c) Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co., Ltd.
 - d) Zhejiang Tianyu Pharmaceutical Co., Ltd.
 - e) Yancheng City DongGang Pharmaceutical Development Co., Ltd.
- viii. The Authority forwarded a copy of the Initiation Notification to the following known importers/users/user associations (whose names and addresses were made available to the Authority by the applicant) of subject goods in India and advised them to make their views known in writing within the time limit prescribed by the Authority in accordance with the Rule 6(4):
 - a) Vasudha Pharma Chem Ltd
 - b) CTX Lifesciences Pvt Ltd
 - c) Sun Pharmaceutical Industries Ltd
 - d) KP Manish Global Ingredients Pvt Ltd
 - e) Laurus Labs Ltd
 - f) Macleods Pharmaceuticals Ltd
 - g) Gensynth Laboratories Pvt Ltd
 - h) Verdant Life Sciences Pvt Ltd
 - i) Glenmark Life Sciences Ltd
 - j) Cadila Healthcare Ltd
 - k) BLD Pharmatech (India) Pvt Ltd
 - l) B K D Health Care
 - m) Granules India Ltd
 - n) Konar Organics Ltd
 - o) Synergy Remedies Private Limited

- p) Jubilant Generics Ltd
- q) Mylan Laboratories Limited
- ix. None of the importers/users have filed their Questionnaire/legal submission in the present investigation.
- x. China Chamber of Commerce for Import & Export of Medicines & Health Products (CCCMHPIE) made legal submissions.
- xi. The Authority *vide* para 7 of the initiation notification dated 30th June 2025 invited comments on the scope of the product under consideration and product control number (PCN) methodology from the stakeholders within 30 days of initiation. The Authority notified the final scope of PUC and PCN methodology *vide* its letter dated 25th August 2025.
- xii. The period of investigation (“POI”) for the purpose of present investigation is from January 2024 – December 2024 (12 Months). The period of injury covers the periods from April 2021 to March 2022, April 2022 to March 2023, April 2023 to March 2024 and the POI.
- xiii. Further information was sought from the applicant and other interested parties to the extent deemed necessary. Verification of the data provided by the domestic industry and other interested parties was conducted to the extent considered necessary for the purpose of the investigation.
- xiv. The non-injurious price (hereinafter referred to as the “NIP”) has been determined based on the cost of production and reasonable return on capital employed for the subject goods in India, based on the information furnished by the domestic industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure III to the AD Rules, 1995 so as to ascertain whether anti-dumping duties lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry.
- xv. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claims. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.
- xvi. The Authority made available non-confidential version of the evidence presented by various interested parties. A list of all interested parties was uploaded on the DGTR website, along with the request to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all the other interested parties.
- xvii. Request was made to the DG Systems to provide the transaction-wise details of imports of the subject goods for the past three years, and the period of investigation, which was received by the Authority. The Authority has relied upon the DG systems data for computation of the volume of imports and its analysis after due examination of the transactions.
- xviii. The Authority held an oral hearing on 3rd February, 2026 to provide an opportunity to the interested parties to present relevant information orally in accordance with Rule 6(6) of the AD Rules. The interested parties who presented their views orally at the time of oral hearing were asked to file written submissions of the views expressed orally. The interested parties were provided opportunity to offer rejoinder submissions to the views expressed by other interested parties. The interested parties were requested to submit their written submissions by 10th February 2026 and rejoinder submissions by 17th February 2026. The submissions made therein have been duly considered and addressed appropriately.
- xix. The Authority, during the course of the investigation, satisfied itself as to the accuracy of the information supplied by the applicant and the interested parties, which forms the basis of these final findings, to the extent possible and considered relevant and necessary.
- xx. The Authority has considered all the arguments raised and information provided by all the interested parties at this stage, to the extent the same are supported with evidence and considered relevant to the present investigation.
- xxi. A disclosure statement dated 9th June 2026 was issued by the Authority, in accordance with Rule 16 of the Rules disclosing the essential facts under consideration in the matter relating to the present anti-dumping investigation. The Authority has examined all the post-disclosure comments made by the interested parties in these final findings to the extent relevant. Any submission which was merely a reproduction of the previous submission, and which had been adequately examined by the Authority has not been repeated for the sake of brevity.

- xxii. Wherever an interested party has refused access to or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has recorded its observations on the basis of the facts available.
- xxiii. ***in these final findings represents information furnished by an interested party on a confidential basis, and so considered by the Authority under the AD Rules.
- xxiv. The exchange rate adopted by the Authority for the subject investigation is 1 US\$ = Rs 84.58.

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

C.1. Submissions made by the other interested parties

4. None of the interested parties have submitted any comments on the product under consideration.

C.2. Submissions by the Domestic Industry

5. Following submissions have been made by the domestic industry with regard to the scope of the product under consideration and like article:

- i) The product under consideration in the present application is “4-(Bromomethyl)-2'-cyanobiphenyl” which is also known as “Bromo OTBN”. Bromo OTBN is a cream / off white colored powder used in the manufacturing of certain pharmaceutical API's, mainly Valsartan, Irbesartan & Telmisartan. It acts as intermediate in the synthesis of pharmaceutical drugs of sartan class such as Losartan, azilsartan ester and telmisartan. It is also used in the synthesis of other pyrazolines and related derivatives.
- ii) The chemical structure of the subject goods consists of a central biphenyl core with substituents on each benzene ring. The cyano group (-CN) is located on the 2' position of one benzene ring, while the bromomethyl group (-CH₂Br) is situated on the 4 positions of the other benzene ring. This arrangement gives the molecule its unique properties and reactivity.
- iii) The subject goods are prepared by brominating 2-Cyano-4'- methyl biphenyl (OTBN) in suitable solvent in the presence of catalyst at suitable temperature. Further bromination is completed by addition of Hydrogen Peroxide (H₂O₂) into the reaction mass. Work up involves removal of bromine traces by Sodium metabisulfite (SMBS) followed by neutralization process using sodium bicarbonate solution. The resulting solid material is obtained by distilling the organic layer; which on further crystallisation with methanol gives pure product.
- iv) The subject goods are classified under Chapter 29 of the Customs Tariff Act, 1975. The subject goods are imported under different codes from company to company and country to country, and majority of imports are happening under the headings 29269000, 29339990, 29332990, 29420090 and 29152990. It is submitted that the customs classification is indicative only and in no way, it is binding upon the product scope.
- v) There is no difference in the subject goods produced by the domestic industry and that imported from the subject country. The subject goods produced by the domestic industry and the subject goods imported from subject country are comparable in terms of characteristics such as physical and chemical characteristics, manufacturing process and technology, functions and uses, product specifications, distribution and market & tariff classification of the goods.

C.3. Examination by the Authority

6. The initiation notification defined the product under consideration as follows:

“The product under consideration in the present case is “4-(Bromomethyl)-2'- cyanobiphenyl” (hereinafter also referred to as “Product under Consideration” or “PUC”). As per the information contained in the Application filed by the domestic industry, the PUC is also known as “Bromo OTBN”. Bromo OTBN is a cream / off white colored powder used in the manufacturing of certain pharmaceutical API's, mainly Valsartan, Irbesartan & Telmisartan.”

7. The subject goods act as intermediate in the synthesis of pharmaceutical drugs of sartan class such as Losartan, azilsartan ester and telmisartan. It is also used in the synthesis of other pyrazolines and related derivatives. In addition, recently reported studies have indicated the role of subject goods in the determination of potential genotoxic impurities in telmisartan using ESI-MS/MS technique and other solvents using thermodynamic studies.
8. The chemical structure of the subject goods consists of a central biphenyl core with substituents on each benzene ring. The cyano group (-CN) is located on the 2' position of one benzene ring, while the bromomethyl group (-CH₂Br) is situated on the 4 positions of the other benzene ring. This arrangement gives the molecule its unique properties and reactivity.

9. The subject goods are classified under Chapter 29 of the Customs Tariff Act, 1975. The petitioner has submitted that the subject goods are being imported under different HS codes and majority of the imports are happening under the headings 29269000, 29339990, 29332990, 29420090, 29152990. However, it is noted that in anti-dumping investigation the customs classification is indicative only and in no way, it is binding upon the product scope. The interested parties, through para 7 of the notice of initiation, were advised to furnish their comments/suggestions on the product scope and PCN methodology within 30 days from the date of initiation of the investigation. No other interested party has submitted any comment on the scope of the PUC or PCN methodology.
10. Accordingly, the scope of the PUC remains the same as defined in the initiation notification. Further, no interested party proposed any PCN methodology. In the absence of any comment on PCN methodology, no PCN methodology is being adopted for the present investigation.
11. With regard to like article, Rule 2(d) of the Anti-Dumping Rules provides as under:
- "like article" means an article which is identical or alike in all respects to the article under investigation for being dumped in India or in the absence of such article, another article which although not alike in all respects, has characteristics closely resembling those of the articles under investigation;*
12. After considering the information on record, the Authority holds that there is no material difference in product under consideration exported from subject country and the product produced by the Indian industry. Product under consideration produced by the domestic industry is comparable to the imported subject product in terms of physical characteristics, production technology & manufacturing process, functions & uses, product specifications, distribution & marketing. The two are technically and commercially substitutable. Accordingly, the Authority concludes that the product produced by the domestic industry are 'like article' to the product under consideration imported from the subject country in terms of Rule 2(d) of the Rules.

D. SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY & STANDING

D.1. Submissions made by the other interested parties

13. None of the other interested parties have submitted any comments on the standing of the Domestic Industry.

D.2. Submissions by the Domestic Industry

14. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to the domestic industry and standing:
- i. The application for the imposition of anti-dumping duty has been filed by M/s Neogen Chemicals Ltd. As per the information available with the applicant, there are two more producers of the subject goods in the country, namely, SV Labs and Saurav Chemicals. However, the applicant accounts for majority of the Indian production of the subject goods (above 50%).
 - ii. The applicant has neither imported the PUC nor is related to any producer/exporter of the product under consideration in China PR or any importer of the subject goods in India.
 - iii. The production of the Applicant constitutes "a major proportion" of total Indian production in terms of the Rules. Thus, the applicant qualifies the test of Rule 2(b) as well as the standing requirements of Rule 5.

D.3. Examination by the Authority

15. Rule 2 (b) of the AD rules defines domestic industry as under:

"(b) "domestic industry" means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term 'domestic industry' may be construed as referring to the rest of the producers"

16. The application in the present case has been filed by M/s. Neogen Chemicals Ltd. As per the applicant, there are two more producers of the subject goods in the country, namely, SV Labs and Saurav Chemicals.
17. Saurav Chemicals (now SCL Lifesciences) sent an email dated 30.01.2026 stating that they support the application filed by the domestic industry. However, it is noted that neither the information in prescribed format was filed nor the party registered and participated in the investigation.
18. As per the information on record, the applicant holds major share in the total domestic production regardless of the support extended by the other domestic producer and constitutes "a major proportion" of total Indian production in terms of the AD Rules. The following table elaborates on the share held by the applicant and that of other producers:

Production	MT	% Share
Applicant	***	***
Other Producer:	***	***
S V Labs	***	***
Saurav Chemicals	***	***
Total Indian Production	***	100

19. The applicant has submitted that it has neither imported the PUC nor is related to any producer/exporter of the product under consideration in China PR or any importer of the subject goods in India. In view of the above and after due examination, the Authority notes that the applicant constitutes eligible domestic industry in terms of Rule 2(b), and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules supra.

E. ISSUES RELATING TO CONFIDENTIALITY

E.1. Submissions made by the other interested parties

20. The various submissions made by the other interested parties during the course of the present investigation with regard to confidentiality and considered relevant by the Authority are as follows:

- i. The petition suffers from excessive confidentiality. Further, the petition provides no information with respect to volume.
- ii. Domestic Industry has also not provided sufficient details of their costing.

E.2. Submissions by the Domestic Industry

21. The submissions made by domestic industry are as follows:

- i. Responding exporters have failed to fulfill their obligations under the Indian law by not providing the meaningful summary of the response to exporters' questionnaire. They have claimed excessive confidentiality without any proper justification. Further, non-confidential version of the questionnaire response has not been given for all the information contained in the confidential version without assigning proper reasons.
- ii. It was obligatory for the exporters to give proper statement of reasons as to why confidentiality was claimed and why summarization was not possible for certain information.
- iii. The exporters have not only failed to provide the meaningful response but they have also failed to give any reasons for claiming such excessive confidentiality. The appendices enclosed with the responses contain no meaningful non-confidential response and, in some cases, the same are either totally blank or are not enclosed with the response.
- iv. The law further states that if the Authority finds that a request for confidentiality is not warranted and if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, the Authority may disregard such information. Further, the questionnaire responses by the responding exporters are grossly deficient and do not respond to a number of questions raised therein.

E.3. Examination by the Authority

22. The Authority made available non-confidential version of the information provided by various interested parties to all interested parties.

23. The Authority made available the non-confidential version of the information provided by the various parties to other interested parties as per Rule 6(7). With regard to confidentiality of information submitted by the interested parties, Rule 7 of the AD Rules provided as follows:

“Confidential Information:

(1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7) of rule 6, sub-rule (2) of rule 12, sub-rule (4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any Other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such Information shall be disclosed to any other Party without specific authorization of the party providing such information.

(2) The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such

information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarization is not possible.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the Information public or to authorize its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information."

24. The information provided by the interested parties on a confidential basis was examined with regards to sufficiency of such claims. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to the other interested parties. Wherever possible, the parties providing information on a confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on a confidential basis. The Authority also notes that all interested parties have claimed their business-related sensitive information as confidential.

F. MISCELLANEOUS ISSUES

F.1. Submissions made by the other interested parties

25. The submissions made by the other interested parties are as follows:

- i. It has been noticed that the petitioner has sourced the import data from the secondary sources. It is submitted that the data sourced from the secondary sources is not authentic and reliable. The Authority should have called for DGCI&S data for the examination of imports in the present investigation at the time of initiation. In the past, the Authority has always relied upon the data sourced from DGCI&S and not the secondary sources.
- ii. The petition filed by the domestic industry contains material inconsistencies and contradictory information regarding crucial data points such as the import volume and CIF price for the financial year 2021-22, which is the base year of the injury period.
- iii. The DGTR has consistently adopted 22% Return on Capital Employed (ROCE) for determining the Non-Injurious Price (NIP), which we submit is excessive, outdated, and inconsistent with the principles laid out under the Anti-Dumping Rules. As per Para 4 of Annexure-III to the Rules, a "reasonable return" is to be allowed on capital employed, not a fixed or inflated one. The current method does not account for prevailing interest and tax rates and unjustifiably increases the NIP, thereby overstating injury and granting undue protection to the domestic industry.

F.2. Submissions by the Domestic Industry

26. The submissions made by the domestic industry are as follows:

- i. China Chamber of Commerce for Import & Export of Medicines & Health Products (CCCMHPIE) cannot be considered as an interested party in terms of Rule 2(c) of the AD Rules.
- ii. There is no dispute that CCCMHPIE is certainly not falling under the category of a producer, exporter or an importer. The association can therefore claim the status of a business Association under Rule 2(c)(i). It may be seen from the above that only that association can be considered as "interested party", where the majority of the members of which are producers, exporters or importers of "such an article". Therefore, an association can be permitted to participate as an interested party in the investigation only if it is proved to the satisfaction of the Authority that the majority of the members of such association are either importers or producers of subject goods. It is pertinent to note that the majority test is to be applied in the context of total membership of the respective association.
- iii. The said association has not even made any averment, let alone evidence, to prove that they qualify as an interested party in terms of the Rule cited above. They have not even bothered to submit complete lists of all their members so as to enable the Hon'ble Authority to ascertain their status as an interested party despite the fact that the responding association as well as their legal representative is well aware of the requirement contained in the Anti-Dumping Rules.
- iv. The submissions made by the interested parties challenging the reliability of the import data relied upon by the applicant are misplaced and constitute unnecessary verbosity. It is important to clarify that as per established practice and repeated clarifications by the Authority, applicants in anti-dumping investigations are permitted to provide import data from any source for the purpose of filing their applications. However, the data that the Authority uses for initiation and further proceedings is duly sourced from government databases such as the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S), which is the official and reliable repository of import statistics. This ensures the integrity and credibility of the import

data on which the investigations are based. Thus, objections focusing merely on the source of applicant-provided data ignore this procedural safeguard and should be dismissed.

- v. As regards the contention that the return on capital employed used for the purpose of computing NIP is inflated, it is submitted that such submission is not based upon any cogent reasoning or submission. The 22% return allowed while computing NIP is historically consistent return which has been found to be adequate/reasonable by the Authority as well as the Hon'ble CESTAT time and again.

F.3. Examination by the Authority

27. The Authority has examined the submission of the domestic industry, raised in its rejoinder dated 17th February, 2026, that CCCMHPIE does not satisfy the conditions prescribed in Rule 2(c)(i) of the Rules for being treated as an interested party. The Authority notes that CCCMHPIE has described itself, in its preliminary submission dated 2nd September, 2025 and in subsequent written submissions, as a national trade association in China established in May 1989, functioning under the Ministry of Commerce of the People's Republic of China, with a membership of over 2,400 companies including manufacturers, trading companies and research and development facilities in the healthcare sector.
28. The Authority published the list of interested parties on 6th August, 2025, in which CCCMHPIE was specifically included, and the domestic industry did not raise any objection to such inclusion at that stage. The Authority further observes that the domestic industry, by its communications dated 10th September, 2025 and 17th November, 2025, expressly acknowledged receipt of the submissions of CCCMHPIE, and engaged with such submissions on merits throughout the investigation, including at the oral hearing held on 3rd February, 2026 and in its written submissions dated 10th February, 2026, without at any point raising any challenge to CCCMHPIE's eligibility to participate. The objection has been raised for the first time in the rejoinder submissions, which are not, in the normal course, circulated for further reply, with the result that CCCMHPIE has had no procedural opportunity to respond. The domestic industry had already engaged with CCCMHPIE's submissions on merits without objecting to it before making rejoinder submissions, and the domestic industry's prolonged silence on this issue can be understood as acceptance of CCCMHPIE's participation throughout that period.
29. The Authority also observes that the contentions advanced by CCCMHPIE in the present investigation are substantially the same as those advanced by the cooperating producers and exporters from China PR who have filed questionnaire responses, and would have to be considered on merits in any event. Having regard to the foregoing, the Authority does not entertain the belated challenge to CCCMHPIE's eligibility, and has considered the submissions of CCCMHPIE on merits.
30. As regards the arguments of the interested parties regarding the import data relied by the applicant, the Authority notes that at the time of initiation, the applicant is required to prima-facie satisfy the Authority regarding dumping, injury and causal link. For such purpose, the applicant procures data from secondary sources/market intelligence. However, for the purpose of initiation and the present final findings, the Authority has relied upon the official import data from DG System.
31. As regards the issues raised by the interested parties regarding the computation of NIP for the domestic industry, the Authority has determined NIP for the domestic industry on the basis of principles laid down in AD Rules read with Annexure III and in accordance with the consistent practice of the Authority.

G. NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DUMPING MARGIN

G.1. Views of the other interested parties

32. The following submissions have been made by the other interested parties during the course of the present investigation and considered relevant by the Authority:
 - i. The continued treatment of China PR as a non-market economy (NME) under anti-dumping investigations is without legal basis post-11th December 2016, the date on which Article 15(a)(ii) of China's WTO Accession Protocol expired. As per this Protocol, WTO members were permitted to use surrogate country methodology for a maximum of 15 years. That period has lapsed, and such methodology is now inconsistent with WTO law.
 - ii. The Authority should take into account the actual consumption norms of the cooperating Chinese producer/exporter for determining the constructed normal value for cooperating Chinese producer/exporter. There is no legal justification or economic rationale for substituting actual consumption norm of Chinese producer/exporter with the consumption norm of domestic industry, which may be inefficient.
 - iii. The cooperating Chinese producers/exporters have fully cooperated with the Authority in this investigation and have submitted a complete questionnaire response in the prescribed format and within the timeline prescribed by the Authority. In accordance with Section 9A(6A) of the Customs Tariff Act, 1975, an

individual rate of duty must be determined based on the records maintained and information provided by cooperating producers/exporters.

G.2. Submissions by the Domestic Industry

33. The submissions made by the domestic industry are as follows:

- i. None of the exporters have filed the additional questionnaire for claiming the market economy status. Any reliable and verified information relating to the third country exports is also not there on record. Thus, the normal value of the exporters should be computed on the basis of the cost-plus methodology.
- ii. The data on record shows a significantly positive dumping margin. Thus, the Authority is requested to kindly impose the anti-dumping duties to protect the domestic industry.
- iii. As regards the submission that China PR should be granted market economy status, it is submitted that China PR has been considered as a non-market economy country by various authority's world over including DGTR. Para 8 of Annexure I contain a presumption against such country that it is operating on Non-market Economy basis, subject to the rebuttal of the same by the producers/exporters of the said country. Since none of the Chinese producers have filed the requested information in prescribed format which is required for the assessment of market economy situation, in terms of the presumption under para 8 of Annexure-I, China PR has to be treated as a non- market economy country and accordingly the normal value is required to be determined in terms of Para 7 of Annexure I of the Rules.
- iv. As regards the request of the Chinese producers to take into account their actual consumption norms for the purpose of constructing the normal value, it is submitted that such request is not consistent with the practice followed by the Authority.

G.3. Examination by the Authority

G.3.1. Normal Value

34. Under Section 9A (1)(c), normal value in relation to an article means:

- i. *The comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article, when destined for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6), or*
- ii. *When there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either-*
 - a. *comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*
 - b. *the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6);*

Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely trans-shipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.

35. Article 15 of China's Accession Protocol in WTO provides as follows:

" Article VI of the GATT 1994, the Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 ("Anti-Dumping Agreement") and the SCM Agreement shall apply in proceedings involving imports of Chinese origin into a WTO Member consistent with the following:

(a) In determining price comparability under Article VI of the GATT 1994 and the Anti-Dumping Agreement, the importing WTO Member shall use either Chinese prices or costs for the industry under investigation or a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China based on the following rules:

- (i) *If the producers under investigation can clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of that product, the importing WTO Member shall use Chinese prices or costs for the industry under investigation in determining price comparability;*

- (ii) *The importing WTO Member may use a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China if the producers under investigation cannot clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to manufacture, production and sale of that product.*
- (iii) *In proceedings under Parts II, III and V of the SCM Agreement, when addressing subsidies described in Articles 14(a), 14(b), 14(c) and 14(d), relevant provisions of the SCM Agreement shall apply; however, if there are special difficulties in that application, the importing WTO Member may then use methodologies for identifying and measuring the subsidy benefit which take into account the possibility that prevailing terms and conditions in China may not always be available as appropriate benchmarks. In applying such methodologies, where practicable, the importing WTO Member should adjust such prevailing terms and conditions before considering the use of terms and conditions prevailing outside China.*
- (iv) *The importing WTO Member shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (a) to the Committee on Anti-Dumping Practices and shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (b) to the Committee on Subsidies and Countervailing Measures.*
- (v) *Once China has established, under the national law of the importing WTO Member, that it is a market economy, the provisions of subparagraph (a) shall be terminated provided that the importing Member's national law contains market economy criteria as of the date of accession. In any event, the provisions of subparagraph (a)(ii) shall expire 15 years after the date of accession. In addition, should China establish, pursuant to the national law of the importing WTO Member, that market economy conditions prevail in a particular industry or sector, the non-market economy provisions of subparagraph (a) shall no longer apply to that industry or sector."*
36. The Authority notes that while the provisions of Article 15 (a)(ii) of China PR's Accession Protocol have expired with effect from 11th December 2016. However, the provision under Article 2.2.1.1 of the Anti-Dumping Agreement read with obligation under 15(a)(i) of the Accession Protocol require criterion stipulated in Para 8 of the Annexure I of Anti-Dumping Rules to be satisfied through the information/data to be provided in the supplementary questionnaire for claiming market economy status.
37. At the stage of initiation, the Authority constructed the normal value for China PR based on best estimates of the cost of production of the domestic industry after duly adjusting the selling, general and administrative expenses and profits. Upon initiation, the Authority advised the producers/ exporters in China PR to respond to the notice of initiation and provide information relevant to determination of their market economy status. The Authority sent copies of the supplementary questionnaire to all the known producers/ exporters for rebutting presumption of non-market economy in accordance with criteria laid down in Para 8(3) of Annexure-I to the Rules and furnish relevant detailed information.
38. The Authority notes the following provisions under Para 7 and Para 8 of Annexure-I to the Rules with regard to the determination of normal value for producers in China PR
- "7. In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in a market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India, or where it is not possible, on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duty adjusted, if necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate market economy third country shall be selected by the designated authority in a reasonable manner [keeping in view the level of development of the country concerned and the product in question] and due account shall be taken of any reliable information made available at the time of the selection. Account shall also be taken within time limits; there appropriate, of the investigation if any made in a similar matter in respect of any other market economy third country. The parties to the investigation shall be informed without unreasonable delay of the aforesaid selection of the market economy third country and shall be given a reasonable period of time to offer their comments.*
- "8. (1) The term "non-market economy country" means any country which the designated authority determines as not operating on market principles of cost or pricing structures, so that sales of merchandise in such country do not respect the fair value of the merchandise, in accordance with the criteria specified in subparagraph (3).*
- (2) There shall be a presumption that any country that has been determined to be, or has been treated as, a non-market economy country for purposes of an antidumping investigation by the designated authority or by the competent authority of any WTO member country during the three-year period preceding the investigation is a non-market economy country. Provided, however, that the non-market*

economy country or the concerned firms from such country may rebut such a presumption by providing information and evidence to the designated authority that establishes that such country is not a non-market economy country on the basis of the criteria specified in sub-paragraph (3)

(3) The designated authority shall consider in each case the following criteria as to whether: (a) the decisions of the concerned firms in such country regarding prices, costs and inputs, including raw materials, cost of technology and labour, output, sales and investment, are made in response to market signals reflecting supply and demand and without significant State interference in this regard, and whether costs of major inputs substantially reflect market values: (b) the production costs and financial situation of such firms are subject to significant distortions carried over from the former non-market economy system, in particular in relation to depreciation of assets, other write-offs, barter trade and payment via compensation of debts: (c) such firms are subject to bankruptcy and property laws which guarantee legal certainty and stability for the operation of the firms, and (d) the exchange rate conversions are carried out at the market rate. Provided, however, that where it is shown by sufficient evidence in writing on the basis of the criteria specified in this paragraph that market conditions prevail for one or more such firms subject to anti-dumping investigations, the designated authority may apply the principles set out in paragraphs 1 to 6 instead of the principles set out in paragraph 7 and in this paragraph.

(4) Notwithstanding, anything contained in sub-paragraph (2), the designated authority may treat such country as market economy country which, on the basis of the latest detailed evaluation of relevant criteria, which includes the criteria specified in sub paragraph (3), has been, by publication of such evaluation in a public document, treated or determined to be treated as a market economy country) for the purposes of anti-dumping investigations, by a country which is a Member of the World Trade Organization.

39. At the stage of initiation, the Authority proceeded with the presumption of treating China PR as a non-market economy country. Upon initiation, the Authority advised the producers / exporters in China PR to respond to the notice of initiation and provide information on whether their data/information could be adopted for normal value determination. The Authority sent copies of the market economy treatment / supplementary questionnaire to all the known producers/ exporters in China PR to provide relevant information in this regard.
40. Paragraph 7 stipulates multiple plausible methods for calculating the normal value for producers in non-market economy, including (a) on the basis of price or constructed value in a market economy third country; (b) price from such a third country to other country, including India; and (c) on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted, if necessary, to include a reasonable profit margin. The Authority notes that the normal value is required to be determined having regard to various sequential alternatives provided under paragraph 7.
41. At the stage of filing the application, the domestic industry had submitted that the normal value for China PR should be constructed based on price actually payable in India, including reasonable profits for the like article being produced in India.
42. No information/evidence has been provided by the interested parties for the consideration of the normal value on the basis of the first and second methods. Therefore, the Authority has decided to construct the normal value based on the third method, i.e., on any other reasonable basis. Under this, the normal value can be determined based on price actually paid or payable in India. For this purpose, the Authority has considered the optimized cost of production of the domestic industry, with a reasonable addition of selling, general and administrative expenses and profits. The normal value so determined is provided in the dumping margin table below.

G.3.2. Export price

43. Following producers and exporters from China PR have participated and filed questionnaire response:
- Lin Hai Huanan Chemical Co., Ltd, Producer Exporter
 - Nantong Huayu Chemical Technology Co, Ltd, Exporter
 - Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co., Ltd, Exporter
 - Zhejiang Tianyu Pharmaceutical Co., Ltd, Producer Exporter
 - Yancheng City Donggang Pharmaceutical Development Co., Ltd, Producer Exporter

Yancheng City Donggang Pharmaceutical Development Co., Ltd. (“DongGang”)

44. Yancheng City DongGang Pharmaceutical Development Co., Ltd. (“DongGang”) is a producer/exporter of subject goods in China PR. DongGang has provided relevant information in the prescribed exporter questionnaire format.
45. It is noted that during the POI, DongGang has exported *** MT of subject goods to unrelated customers in India directly. DongGang has claimed adjustments on account of ocean freight, ocean insurance, inland freight, port and handling expenses, credit cost and bank charges which have been allowed by the Authority. The ex-factory export price as determined for DongGang is given in the dumping margin table below.

Zhejiang Tianyu Pharmaceutical Co., Ltd. (“Tianyu”)

46. Zhejiang Tianyu Pharmaceutical Co., Ltd., China PR is a producer/exporter of subject goods in China PR and has provided relevant information in the prescribed exporter questionnaire.
47. During the POI, Zhejiang Tianyu Pharmaceutical Co., Ltd., China PR, has sold *** MT of subject goods to India directly to unrelated buyers in India. The producer/exporter has claimed adjustments on accounts of ocean freight, insurance, inland transportation, port and other related expenses, credit cost and bank charges which have been allowed by the authority.

M/s Linhai Huanan Chemical Co., Ltd., China PR

48. During the POI, Linhai Huanan Chemical Co., Ltd., China PR, has sold *** MT of subject goods to India indirectly through two related exports/traders namely, Nantong Huayu Chemical Technology Co., Ltd., and Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co., Ltd., on ex-work basis.
49. Linhai Huanan Chemical Co., Ltd., China PR, has sold *** MT to Nantong Huayu Chemical Technology Co., Ltd., and rest of the quantity *** MT has been sold to Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co., Ltd.
50. The *** MT of subject goods which has been sold to Nantong Huayu Chemical Technology Co., Ltd., by Linhai Huanan Chemical Co., Ltd., China PR, has been further resold to Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co., Ltd., by Nantong Huayu Chemical Technology Co., Ltd.
51. It is further noted that out of the ***MT, of subject goods exported to India Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co., Ltd., who is the ultimate exporter/trader of subject goods has sold ***MT of subject goods directly to unrelated buyers in India and rest of ***MT has been sold to India indirectly through four unrelated non-participated exporters/traders namely, Hangzhou Dawn Ray Pharmaceutical Co Ltd., Hangzhou Starshine Pharmaceutical Co Ltd., Zhejiang Top Hankook Biopharm Co Ltd., and Zhejiang Ueasy Business Service Co Ltd. The producer/exporter has not claimed any adjustments to ex-work prices.
52. The weighted average ex-factory export price for M/s Linhai Huanan Chemical Co., Ltd. for the POI has accordingly been determined by combining the verified export price for the cooperating portion of ***MT with the facts-available export price for the non-cooperating portion of ***MT, as set out in the dumping margin table below.

G.3.3. Export price for non-cooperative exporters

53. For all other producers/ exporters from China PR, export price has been determined based on facts available taking into account the data examined for the co-operating producer/exporters and the same is mentioned in the dumping margin table below.

G.3.4. Determination of Dumping Margin

54. The dumping margin is provided as under:

Producer's/ exporter's name	CNV (USD/MT)	NEP (USD/MT)	DM (USD/MT)	DM %	DM range %
Yancheng City DongGang Pharmaceutical Development Co., Ltd	***	***	***	***	55-65
Linhai Huanan Chemical Co., Ltd.	***	***	***	***	60-70
Zhejiang Tianyu Pharmaceutical Co., Ltd.	***	***	***	***	60-70

All others	***	***	***	***	80-90
------------	-----	-----	-----	-----	-------

H. METHODOLOGY FOR INJURY ASSESSMENT AND EXAMINATION OF INJURY AND CAUSAL LINK

H.1. Submissions made by the other interested parties

55. The following are the injury related submissions made by the other interested parties during the course of the present investigation and considered relevant by the Authority.

- i. A thorough analysis of the data submitted by the Applicant reveals a consistent and substantial year-on-year improvement across all key volume-related parameters throughout the injury investigation period.
- ii. The consistent and substantial improvements across all volume-based parameters such as production, capacity utilization, domestic sales, market share, employment, wages, and productivity paint a clear picture of a thriving domestic industry. These indicators collectively demonstrate that the domestic industry is not suffering material injury.
- iii. The decline in landed price of imports is commensurate with the decline in cost of sales of the domestic industry. In fact, the rate of decline in landed price is lower than the rate of decline in cost of sales of the domestic industry. This means that imports are not exerting price pressure on the domestic industry and is not causing price suppression and depression.
- iv. The domestic industry has primarily claimed injury due to losses. However, an analysis of the data shows a clear disconnect between the trend of imports and the profitability of the domestic industry.
- v. If imports were the cause of injury, the losses should have increased in the POI, not decreased. This disconnect demonstrates that the financial performance of the Applicant is not principally governed by the volume or price of imports, suggesting the root cause of losses lies in other factors.
- vi. The Applicants' own statements in its annual report identify supply chain disruptions, geopolitical tensions, and raw material price corrections as the primary challenges. These challenges affected the company as a whole and not only the PUC. However, it also means that these challenges also affected the performance of domestic industry for PUC and that these factors are entirely unrelated to the alleged dumping and must be considered as the principal causes of any injury.
- vii. The petitioner has reported financial losses; however, a closer examination of key financial indicators during the POI reveals a significant trend of stabilization and recovery. The indexed data provided by the petitioner clearly demonstrates a consistent improvement in its financial performance, which directly contradicts the assertion of material injury caused by dumped imports.
- viii. The alleged increase in imports from China PR is not a result of dumping, but a direct consequence of the growth in domestic demand. The total demand for the subject goods in India has shown a consistent upward trend, with the index increasing from 100 in 2022–23 to 163 in the POI (Jan 2024 – Dec 2024), indicating a 63% increase.
- ix. During the POI, the price undercutting is negative, indicating that imports from China PR were priced higher than the domestic selling price. In the previous years as well, price undercutting has remained minimal and inconsistent. This shows that there is no price effect causing injury to the domestic industry.
- x. The increase in inventory levels during the POI appears to be a strategic business decision rather than evidence of injury caused by imports from China PR. This is substantiated by the sharp increase in production (indexed at 210), which naturally necessitates higher inventory stocking to ensure supply continuity. Additionally, domestic sales have also grown significantly (indexed at 168), indicating steady movement of goods and continued market demand.
- xi. The financial losses claimed by the petitioner are not attributable to imports from China PR but are instead the result of its own commercial decisions and internal inefficiencies. The indexed financial data, as submitted in the non-confidential version of the updated petition, reveals that key cost components such as depreciation and interest expenses have risen significantly during the POI.
- xii. The consistent growth in production, capacity utilization and domestic sales demonstrates that the domestic industry is operating efficiently and is not adversely impacted by the subject imports.
- xiii. There is no demonstrable causal link between the dumped imports from China PR and the financial stress faced by the petitioner. The losses incurred are largely due to internal factors such as high costs, investment inefficiencies, and strategic business choices rather than external dumping.

- xiv. Despite no increase in installed capacity, the petitioner's capital employed has increased sharply, indicating poor asset utilization and potentially inefficient investment decisions. The indexed depreciation and interest costs have also risen disproportionately, further exacerbating the financial burden and reflecting internal financial mismanagement rather than external competitive pressure.

H.2. Submissions by the Domestic Industry

56. The following are the injury related submissions made by the domestic industry during the course of the present investigation and considered relevant by the Authority:

- i. The submission of the interested parties regarding lack of injury is fundamentally flawed and fails to consider the totality of the evidence demonstrating injury to the domestic industry. While it is true that some injury aspects have shown improvement, the injury analysis under Indian anti-dumping laws and WTO Agreement is not limited to just few parameters but, rather, an overall assessment is to be carried out considering the impact of dumped imports, price effect, market share erosion, and adverse effects on the domestic industry's economic parameters. The mere improvement in certain parameters does not negate the material injury caused by dumped imports, nor does it absolve the risk of further injury.
- ii. From the data already on record, it can be concluded that the domestic industry has been severely affected with respect to both volume as well as price parameters. There is significant price suppression / price depression by the subject imports and the price underselling is also positive and significant.
- iii. The economic parameters of the domestic industry have also been adversely affected vis-à-vis capacity utilization, profitability, ROCE, cash flow, market share etc.
- iv. Due to continuous price pressure exerted by imports, the domestic industry is forced to sell the subject goods below cost.
- v. The domestic industry is continuously pressurised by its customers to reduce its prices by matching the import prices and there have been multiple instances where its customers have put already placed orders on hold demanding the domestic industry to match the import prices. In this regard, the domestic industry has submitted few such email conversations with its customers where the customers have asked them to match the imports prices and, in some instances, put the orders on hold, pending price reduction.
- vi. While the production and sales of the domestic industry have increased in the POI, the market share of the domestic industry has declined. On the contrary, the market share of China PR has increased substantially accounting for over two third of the total demand in India.
- vii. There has been a parabolic increase in imports from China PR, which is in excess of and higher than the increase in demand. On the other hand, the increase in sales of the domestic industry is purely because of increase in demand. It is further submitted that the increase in sales of the domestic industry is comparatively lower than the increase in demand and increase in imports.
- viii. While certain interested parties argued during the hearing that there is no correlation between the increase in imports and the losses faced by the domestic industry, it is submitted that such submissions are meaningless without taking into consideration the underlying cost during such period of imports.
- ix. There exists a direct correlation between the capacity utilization of the domestic industry and the resultant impact on profitability and the ROCE. The capacity utilization of the domestic industry improved during 2022-23 as compared to the base year leading to improvement in profitability and ROCE of the domestic industry. However, there was a significant decline in the capacity utilization in 2023-24 leading to significant decline in profitability and ROCE. The domestic industry was again able to significantly improve its capacity utilization in the POI which led to improvement in profitability and ROCE in the POI. Clearly, there exists a direct correlation between the capacity utilization of the domestic with profitability and the ROCE of the domestic industry. Similar trend is visible when the effect of delta between CIF prices of imports and cost of the domestic industry is seen on the PBT and ROCE of the domestic industry. The domestic industry's PBT and ROCE rise in tandem when the gap between its costs and import prices widens. Conversely, both metrics decline as that gap narrows. This clearly establishes direct correlation between the import prices and the profitability of the domestic industry.
- x. None of the interested parties has provided any evidence on record as to how the domestic industry has suffered injury due to factors other than dumping from the subject country. Only bare unsubstantiated statements have been made. Therefore, the submissions of the interested parties are required to be ignored.

H.3. Examination by the Authority

57. Rule 11 of the Rules read with Annexure II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, “...taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on the domestic producers of such articles...”. In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, inventory, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure II of the Rules.
58. The injury analysis made by the Authority hereunder addresses the various submissions made by the interested parties during the course of the present investigation and considered relevant by the Authority.

H.3.1. Volume Effect of Dumped Imports

a. Assessment of demand/consumption

59. The Authority has determined demand or apparent consumption of the product in India as the sum of domestic sales of the domestic industry, estimated sales of other producers and imports of subject goods from all sources.

Particulars	UOM	2021-22	2022-23	2023-24	POI
Sales of the domestic industry	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	132	75	168
Sales of other producers	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	135	60	116
Imports from subject country	MT	***	***	***	***
Imports from other countries	MT	0	0	0	0
Total demand	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	106	96	125

60. It is seen that the demand for the subject goods increased over the injury investigation period and was the highest in the POI. The sales of domestic industry and other producers increased in 2022-23, thereafter fell in 2023-24 and increased in POI.
61. The imports have also increased over the injury investigation period and were highest in the POI. Regarding the submission of the interested parties that the increase in imports is on account of increase in demand, the Authority notes that although the increase in imports in POI from the base year is less than the increase in demand, significant production capacities of the domestic industry are unutilised.

b. Imports in absolute and relative terms

62. The information on volume of imports in absolute terms and relative terms over the injury period and in the period of investigation is as below.

Particulars	UOM	2021-22	2022-23	2023-24	POI
Subject country imports	MT	456	426	501	538
Other imports	MT	0	0	0	0
Total imports	MT	456	426	501	538
Subject countries import in relation to					
Indian production	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	65	168	73
Demand	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	88	115	94

Total Imports	%	100	100	100	100
Trend		100	100	100	100

63. The Authority notes that:

- a. The subject imports in relation to Indian production first fell in 2022-23, thereafter increased in 2023-24 and finally declined in the POI.
- b. The subject imports in relation to demand/consumption has also shown the similar pattern.

H.3.2. Price effect of dumped imports

64. In terms of Annexure II (ii) of the Rules, with regard to the effect of the dumped imports on prices, the Authority is required to consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.

65. Accordingly, the impact on the prices of the domestic industry on account of dumped imports of the subject goods from the subject country has been examined with reference to price undercutting and price suppression/depression, if any. For the purpose of this analysis the cost of sales and the net sales realization (NSR) of the domestic industry have been compared with the landed price of the subject imports from the subject country.

a. Price undercutting

66. Price undercutting has been determined by comparing the net sales realization of the domestic industry with the landed price of the imports for the period of investigation. The table below shows the price undercutting from the subject country.

Particulars	UOM	Value
Landed price	Rs./MT	***
Net Sales Realisation	Rs/MT	***
Price Undercutting	Rs/MT	***
Price Undercutting	%	***
Price Undercutting	% Range	Negative

67. It is seen that the landed price of subject imports in the POI is marginally above the selling price of domestic industry resulting in negative price undercutting.

68. The domestic industry has claimed that they are continuously pressurised by their customers to reduce prices by matching the import prices and there have been multiple instances where their customers have put already placed orders on hold demanding the domestic industry to match the import prices. In this regard, the domestic industry has submitted sample copies of email conversations with their customers as evidence where the customers have asked them to match the imports prices and, in some instances, put the orders on hold, pending price reduction.

b. Price suppression / depression

69. In order to determine whether the dumped imports are depressing the domestic prices or whether the effect of such imports is to suppress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred in normal course, the changes in the costs and prices over the injury period, are compared as below.

Particulars	UOM	2021-22	2022-23	2023-24	POI
Landed value	₹/MT	14,69,288	17,59,638	10,15,382	8,01,233
Trend	Index	100	120	69	55
Cost of sales	₹/MT	***	***	***	***

Trend	Index	100	85	83	49
Selling price	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Index	100	100	64	47

70. It is seen that the imports from the subject country continue to be below the cost of production of the domestic industry. The low-priced imports have forced the domestic industry to sell the subject goods below their cost of sales. The dumped imports are depressing and suppressing the prices of the domestic industry.

71. As regards the submission of the interested parties that the decline in landed price of imports is commensurate with the decline in cost of sales and that reduction in import price is reflecting the decline in cost of sales of the product and not dumping, the Authority notes that while there has been decline in the cost of production, the landed value of imports is continuously significantly below the cost of production of the domestic industry.

H.3.3. Impact on economic parameters of the domestic industry.

72. The various injury parameters relating to the domestic industry are discussed herein below.

a. Capacity, production, capacity utilization and domestic sales.

73. Information on capacity, production, capacity utilization and domestic sales over injury period is as follows:

Particulars	UOM	2021-22	2022-23	2023-24	POI
Installed capacity	MT	***	***	***	***
Trend	Index	100	100	100	100
Production	MT	***	***	***	***
Trend	Index	100	143	72	210
Capacity utilization	%	***	***	***	***
Trend	Index	100	139	71	207
Domestic sales	MT	***	***	***	***
Trend	Index	100	132	75	168

74. The Authority notes that: -

- a. The capacity of the domestic industry has remained same over the injury investigation period. However, the domestic industry has significant unutilized capacities.
- b. The production, capacity utilization and sales of the domestic industry increased in 2022-23, thereafter declined in year 2023-24 and increased in POI.

b. Market share

75. Information on market share of imports and the Indian industry over the period was as follows:

Market share of	UOM	2021-22	2022-23	2023-24	POI
Domestic industry	%	***	***	***	***
Trend	Index	100	124	78	134
Other producers	%	***	***	***	***
Trend	Index	100	127	62	92
Imports from subject country	%	***	***	***	***
Trend	Index	100	88	114	94
Other countries imports	%	0	0	0	0
Trend	Index	0	0	0	0

76. The Authority notes that: -

- a. The market share of the domestic industry increased in 2022-23, but declined thereafter in 2023-24, and again increased in the POI. Overall, the market share of the domestic industry increased during the injury period.

- b. The market share of imports from China PR firstly declined in 2022-23, thereafter increased in 2023-24 and finally declined during the POI. Overall, the market share of the imports from China PR marginally declined during the injury period.
- c. The imports from the subject country command majority of the market share in the Indian market.
- d. Regarding improved volume parameters during the POI, the Authority notes that the imports from the subject country command the majority of the market share despite significant unutilised capacities with the domestic industry. Further, the market share of other Indian producers has also declined.

c. Profitability, cash profits and return on investment

77. Information on profitability, return on investment and cash profits is as follows:

Particulars	UOM	2021-22	2022-23	2023-24	POI
Profit/(Loss)	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Index	-100	-43	-140	-57
Profit/(Loss)	₹ lakhs	***	***	***	***
Trend	Index	-100	-56	-106	-97
Cash Profit	₹/ MT	***	***	***	***
Trend	Index	-100	-36	-142	-52
Cash Profit	₹ lakhs	***	***	***	***
Trend	Index	-100	-47	-108	-83
ROCE	%	***	***	***	***
Trend	Index	-100	-31	-95	-32

78. It is seen that the per unit losses of the domestic industry increased in 2023-24 and thereafter declined during the POI. PBIT, cash profit and ROCE has also seen a similar trend. The domestic industry is continuously in losses over the entire injury investigation period.
79. Regarding improved financial performance of the domestic industry, it has been noted that the profitability of the domestic industry has increased whenever their capacity utilisation has increased and has declined with decline in capacity utilisation. Thus, the high quantum of imports lead to underutilisation of capacities of the domestic industry which, in turn, leads to losses to the domestic industry.
80. Regarding the submission of other interested parties that despite no increase in installed capacity, the petitioner's capital employed has increased sharply, indicating poor asset utilization and potentially inefficient investment decisions, the Authority notes that the domestic industry uses common plant for manufacturing the subject goods and other products not covered in the present investigation. The increase in production and capacity utilisation of subject goods led to increase in apportionment of higher capital employed, depreciation and interest cost towards the subject goods.

d. Inventories

81. Information on inventories is as follows:

Particulars	UOM	2021-22	2022-23	2023-24	POI
Opening inventory	MT	***	***	***	***
Closing inventory	MT	***	***	***	***
Average inventory	MT	***	***	***	***

Trend	Index	100	2350	3809	7864
-------	-------	-----	------	------	------

82. It is seen that the average inventory of the domestic industry has increased significantly over the injury period.

e. Employment, wages and productivity

83. Information on employment, wages and productivity over the injury period is as under:

Particulars	UOM	2021-22	2022-23	2023-24	POI
No of employees	MT	***	***	***	***
Trend	Index	100	125	142	140
Salary & Wages	₹ Lacs	***	***	***	***
Trend	Index	100	170	107	337
Productivity per day	MT/Days	***	***	***	***
Trend	Index	100	144	74	211
Productivity per employee	MT/Emp	***	***	***	***
Trend	Index	100	114	51	150

84. The number of employees increased during the injury period. The wages paid to them have also increased. The productivity per day and per employee has increased.

f. Growth.

85. The information on growth is provided below: -

Growth	UOM	2022-23	2023-24	POI
Capacity	%	0%	0%	0%
Production	%	43%	-50%	193%
Domestic sales	%	32%	-43%	124%
Profit/(Loss) (Rs/MT)	%	57%	-229%	59%
Cash Profit (Rs/MT)	%	64%	-291%	63%
ROCE	%	69%	-207%	74%

86. The Authority notes that although the domestic industry has recorded positive growth in the period of investigation in terms of all price parameters like profitability, cash profits and ROCE etc., they are still incurring losses. The Authority also notes that the domestic industry has recorded positive growth in volume parameters like production, sales and capacity utilization etc.

g. Magnitude of dumping

87. The magnitude of dumping is an indicator of the extent to which the imports are being dumped into India. The investigation has shown that the dumping margin is positive and significant in the period of investigation.

h. Ability to raise capital investment

88. It is noted that the profitability and return on capital employed by the domestic industry has remained negative during the period of investigation. The domestic industry was in losses during the period of investigation and the injury investigation period. It has impacted the ability to raise capital investment.

i. Factors affecting domestic prices

89. Examination of import price shows that the import price from the subject country is materially below the cost of sales of the domestic industry. As imports from the subject country entered the domestic market at such prices, the domestic industry has been unable to align its prices in line with the increase in the cost of sales.

j. Observation on injury

90. The examination of the imports of the product under consideration and performance of domestic industry shows that:

- a. Exporters from the subject country are exporting the subject goods to India at dumped prices. The dumping margin determined is positive and significantly high.
- b. The imports from the subject country have increased significantly in absolute terms.
- c. The price undercutting is negative. The authority notes the submission of the domestic industry that it was forced to reduce its prices in view of growing imports in the country and in the light of pressure from its customers to match import prices.
- d. Imports from the subject country have suppressed & depressed the prices of the domestic industry.
- e. The domestic industry is suffering significant losses.
- f. The domestic industry has not been able to get substantial returns. In fact, the ROCE has been negative.
- g. The imports from the subject country have not allowed the domestic industry to perform well and, thus, have caused continuous losses to the domestic industry.

H.4. NON-ATTRIBUTION ANALYSIS (OTHER FACTORS)

91. The Authority examined whether other factors listed under the anti-dumping Rules could have caused injury to the domestic industry. The Authority examined known factors other than the dumped imports and ascertain whether these at the same time have been injuring the domestic industry, so that the injury caused by other, if any, is not attributable to the dumped imports. Factors which are relevant in this respect include, *inter alia*, the volume of subject goods not sold at dumped prices, contraction in demand or changes in the pattern of consumption, trade restrictive practices, changes in technology, the export performance of the domestic industry and the productivity of the domestic industry

(a) Volume and prices of imports from third countries

92. There are no imports of the product under consideration from other countries. Therefore, imports from other countries could not have caused any injury to the domestic industry.

(b) Contraction of demand and changes in the pattern of consumption

93. There has been a rise in demand of the product under consideration over the injury period. Therefore, decline in demand is not a possible reason of injury to the Domestic Industry.

(c) Developments in technology

94. Technology for production of the product concerned has not undergone any significant change. Thus, development in technology is also not a factor causing injury to the domestic injury.

(d) Conditions of competition and trade restrictive practices

95. There is no trade restrictive practice, which could have contributed to the injury to the Domestic Industry as the raw materials as well as the subject goods are freely importable in the country.

(e) Export performance of the domestic industry

96. Only domestic performance of the domestic industry has been considered for this injury analysis purpose. Therefore, performance in the export market has not affected the present injury analysis in any manner whatsoever.

(f) Performance of other products

97. The domestic industry has provided the injury data for the like article and the same has been adopted by the Authority for the purpose of injury analysis. Performance of other products produced and sold by the domestic industry has not been considered. Therefore, the performance of other products produced and sold is not a possible cause of the injury to the domestic industry.

98. It is thus noted that other factors do not show that the domestic industry could have suffered injury due to these other factors.

H.5. DETERMINATION OF INJURY MARGIN

99. The Authority has determined Non-Injurious Price for the domestic industry on the basis of principles laid down in the Rules read with Annexure III, as amended. The non-injurious price of the product under consideration has been determined by adopting the information/data relating to the cost of production for the period of investigation. The non-injurious price has been considered for comparing the landed price from the subject country for calculating injury margin. For determining the non-injurious price, the best utilization of the raw materials by the domestic industry over the injury period has been considered. The same treatment has been carried out with the utilities. The best utilization of production capacity over the injury period has been considered. It is ensured that no extraordinary or non-recurring expenses were charged to the cost of production. A reasonable return (pre-tax @ 22%) on average capital employed (i.e. average net fixed assets plus average working capital) for the product under consideration was allowed as pre-tax profit to arrive at the non-injurious price as prescribed in Annexure III of the Rules.

100. Based on the landed price and the NIP determined as above, the injury margin as determined by the Authority is provided in the table below.

Producer's/ exporter's name	NIP (Rs./ MT)	Landed Value (Rs/MT)	Injury margin (Rs./ MT)	Injury margin %	Injury margin % range
Yancheng City Donggang Pharmaceutical Development Co., Ltd.	***	***	***	***	50-60
Linhai Huanan Chemical Co., Ltd.	***	***	***	***	60-70
Zhejiang Tianyu Pharmaceutical Co., Ltd.	***	***	***	***	50-60
All others	***	***	***	***	80-90

I. EXAMINATION OF CAUSAL LINK

101. The Authority has examined whether the dumped imports from China PR are, through the effects of dumping, causing injury to the domestic industry, and notes the following.

- i. Dumped imports from the subject country reached their highest level of ***MT in the POI, capturing 64% of total Indian demand, and the domestic industry remained in losses, with negative cash profits and negative ROCE, throughout the injury investigation period.
- ii. The landed value of dumped imports in the POI was materially below the cost of sales of the domestic industry, compelling the domestic industry to sell below cost and incur losses in the POI.
- iii. The domestic industry has placed on record communications from its customers requiring it to match import prices, and instances in which orders were put on hold pending price reduction.
- iv. The per-unit losses of the domestic industry have widened when the gap between its cost of sales and the landed value of dumped imports has widened, and have reduced when the gap has narrowed, indicating that the profitability of the domestic industry is governed by the price at which dumped imports enter the Indian market.
- v. The dumped imports have suppressed the domestic industry's prices below its cost of production.
- vi. Notwithstanding the increase in Indian demand, the share of imports from China PR remained dominant at 64% in the POI, while the domestic industry held only 20%, indicating that the domestic industry has been unable to translate growth in demand into a corresponding growth in market share.

102. Having regard to the foregoing, and the non-attribution analysis at paragraph above, the Authority concludes that there is a causal link between the dumped imports from China PR and the material injury suffered by the domestic industry.

J. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST AND OTHER ISSUES

J.1. Submissions made by the other interested parties

103. The various submissions made by the other interested parties during the course of the present investigation with regard to confidentiality and considered relevant by the Authority are as follows:

- i. The imposition of anti-dumping duties is not a mechanical consequence of the existence of dumping or injury; rather, it is subject to a comprehensive assessment of the public interest under Rule 17(3) of AD Rules. Public interest forms a crucial test for trade remedy actions and ensures that duties do not unduly harm domestic consumers, downstream industries, or broader economic goals. In the present case concerning imports of Bromo OTBN from China PR, the imposition of anti-dumping duties would be clearly detrimental to public interest.
- ii. Bromo OTBN is a critical intermediate chemical used in the synthesis of several Active Pharmaceutical Ingredients (APIs) belonging to the “sartan” class of drugs. These APIs are essential for manufacturing widely prescribed antihypertensive medicines such as Valsartan, Telmisartan, Irbesartan, and Losartan, which are used to treat high blood pressure, heart failure, and kidney disease in diabetic patients. These drugs are listed in essential medicine lists, and their affordable availability is a matter of significant public health concern in India. The imposition of duties on the key intermediate (Bromo OTBN) would directly raise input costs for Indian API manufacturers, thereby increasing the production cost of these critical drugs.
- iii. The Indian pharmaceutical industry, particularly API manufacturers, has limited domestic sourcing options for Bromo OTBN. The entire demand cannot be met by the petitioner, Neogen Chemicals Ltd. or any other Indian producers due to capacity constraints, cost factors, and reliability of supply. As per the available data, domestic sales by the petitioner were unable to match demand growth, and a significant portion of market needs has been met through imports. Blocking or burdening these imports through duties would lead to supply chain disruptions in a highly sensitive sector
- iv. Imposing a high anti-dumping duty, as claimed by the domestic industry (80-90% dumping margin and 70-80% injury margin), would make this essential raw material prohibitively expensive. This would escalate the production costs of vital medicines, which is not desirable
- v. It is also important to highlight that there is no reported shortage of domestic production capacity for the final pharmaceutical products in question. On the contrary, the increase in imports of Bromo OTBN has enabled more efficient and cost-effective production of APIs in India. Any disruption in this supply chain by way of protectionist trade measures would only benefit one domestic supplier, while harming dozens of downstream users and lakhs of patients and would be against the public interest.
- vi. If the domestic industry does not possess sufficient capacity to meet the growing domestic demand, imports are not just a choice but a necessity to prevent a supply deficit for the downstream pharmaceutical industry.

J.2. Submissions by the Domestic Industry

104. The submissions made by domestic industry are as follows:

- i. As per the available information from the market, there will be insignificant impact of the anti-dumping duties on the end-users. The PUC is mainly used in manufacturing pharmaceutical APIs and synthesis of other pyrazolines and related derivatives. Such products range from Rs 8,000 per KG to Rs 14,000 per KG. It is pertinent to note that the end-price is not dependent upon the price of the subject goods. This is evident from the fact that the prices of the subject goods have reduced to half in the injury period, however, as per the information available with the applicant no such decline has occurred in the selling prices of the downstream products.
- ii. The submission made by the interested parties that the imposition of duties shall not be in public interest, is incorrect as the same is based upon incorrect premise.
- iii. The imposition of the duties shall not only be fundamental for the survival of the producers of the subject goods in the country, the same would also serve the general public interest.
- iv. Before the POI, the following industries were producing the subject goods in India, apart from the applicant:
 - a) Saurav Chemicals
 - b) SV Labs
 - c) Aether Industries Ltd.
 - d) Vijayasri Organics

e) Element Chemlink

- v. However, all the above manufacturers, including major producers such as Saurav Chemicals, have either severely curtailed the production or have stopped producing the subject goods altogether. This drastic situation stems directly from dumped imports priced at landed values significantly below domestic production costs, rendering continued operations economically unsustainable. The few remaining producers persist only to retain key customers, absorbing severe losses in a desperate bid to maintain market presence.
- vi. It is submitted that absent anti-dumping duties, the domestic producers will have no choice but to shut shop entirely, wiping out domestic capacity and making the downstream users entirely dependent on imports from the subject country.
- vii. It is further submitted that the subject goods are primarily only produced in the subject country and India. The need for protection of domestic industries where global supply is highly concentrated and where denial of access would impose immediate and asymmetric national costs was aptly highlighted in the Economic Survey of India (2025-26). The relevant excerpts are provided hereinbelow:
- “16.33. This tier [Tier I] includes goods, components, and technologies where denial of access would impose immediate and asymmetric national costs, and where global supply is highly concentrated. Typical examples include defence-critical systems, core infrastructure inputs, energy security components, public health essentials, and foundational industrial technologies.*
- 16.34. For Tier I items, the objective is assured availability under stress, not short-term efficiency. Domestic production may be justified, even if it is initially costly....”*
- viii. It is also pertinent to note that none of the users of the subject goods have opposed the present application for imposition of duties. The lack of opposition by the users of the subject goods also clearly indicates that the users are also aware of the dire state of the industry and the need for imposition of duties.

J.3. Examination by the Authority

105. The Authority notes that the primary objective of trade remedial measures is to counteract the injurious effects caused to the domestic industry by unfair trade practices and restore open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. Trade remedial measures do not intend to limit imports from the subject country. On the contrary, the Authority concludes that the positive effects of measures prevent further deteriorations of the domestic industry, maintaining a competitive and diversified supply to the consumers of the subject goods.
106. The Authority issued initiation notification inviting views from all the interested parties. The Authority also prescribed a questionnaire for the users/ consumers to provide relevant information about the present investigation including any possible effects of the measures on their operations. Information was sought on, inter-alia, interchangeability of the product supplied by various suppliers from different countries, impact of measures on the consumers, etc. The Authority had prescribed an economic interest questionnaire which was sent to all interested parties to this investigation. Only the domestic industry and participating exporter has responded to the economic interest questionnaire. No user or importer participated in the present investigation.
107. The Authority observes that the other interested parties, while raising concerns about cost escalation in essential medicines, have not placed on record any quantitative material, any estimate of the incremental cost that would arise from the proposed measure. The domestic industry has also not quantified the impact, recording that *"it is extremely difficult to exactly quantify the impact of duty on end-use products"*. The users of the subject goods who are best placed to quantify such impact, have not participated in the investigation and have neither opposed the measure nor placed any concerns on record. However, the Authority has quantified the impact of anti-dumping duties on one of the final products i.e. Losartan 50 mg tablets for the consumers / patients based on available information, as detailed below:

Particulars	Particulars	Remarks
Requirement of Bromo-OTBN for 1 Kg. of Losartan Potassium	1.15 kg.	As per SION Norms
Expected ADD (Dumping margin)	\$ 5,688 /- MT	Average Dumping margin of cooperative producers

Impact of 1 Kg. of Losartan Cost (Rs.)	621.41	Exchange rate Rs. 95 per USD
Impact on 1 tablet 50mg (Rs.)	0.03	Normal dosage of 50mg.
Impact on monthly cost (Rs.)	0.93	for 30 tablets
Approx. MRP of Losartan 50mg 30 Tablets (Rs.)	150	
Impact on patients as % of MRP	0.62%	

108. It is seen that the impact of anti-dumping duties on consumers is insignificant. The Authority further notes the submission of the domestic industry that the downstream products manufactured using the subject goods are subject to price control measures of the Government of India. Any measure recommended by the Authority would in any event be calibrated by application of the lesser duty rule so as not to exceed what is necessary to remove the injury caused to the domestic industry. In view of the foregoing, and in the absence of any quantified evidence demonstrating a material adverse impact on downstream users or end-consumers, the Authority is of the view that the imposition of an anti-dumping measure, on the facts of the present investigation, is consistent with the wider public interest, including the interest of maintaining a viable domestic manufacturing base for an essential pharmaceutical intermediate where global supply is highly concentrated in a few countries.
109. The Authority notes that there exists a gap between the domestic demand for the subject goods and the available indigenous production capacity. The Authority clarifies, however, that the existence of a demand-supply gap does not, in itself, displace the case for an anti-dumping measure. The subject of the present investigation is not whether imports of the subject goods should occur, but the price at which such imports occur. The Authority's examination has established that imports from the subject country have entered the Indian market at prices materially below the cost of production of the domestic industry, that such imports have suppressed and depressed domestic prices, and that the domestic industry has accordingly been forced to sell the subject goods at non-remunerative prices and absorb continuous losses notwithstanding increase in production and sales volumes. The supply gap can continue to be met through imports at fair prices, while injurious dumping is corrected.
110. The Authority observes that the submission made by the domestic industry regarding curtailment or stoppage of production by other Indian producers has not been substantiated with supporting evidence on record. The Authority is, accordingly, not in a position to record a finding on this submission. Considering the fact that the imports of the subject goods are happening much below the cost of the domestic industry, the Authority notes that the condition of the domestic industry is vulnerable due to imports from subject country. The domestic industry was suffering losses in the period of injury including period of investigation.

K. POST DISCLOSURE COMMENTS

K.1 Submissions by other interested parties

111. The following comments on the Disclosure Statement have been filed by other interested parties.
- i. The export price and landed value as disclosed by the Authority for DongGang should be confirmed in the final findings. In the event of any change in these determinations, the respondent requests the Authority to issue a revised Disclosure Statement and grant an opportunity to comment thereon.
 - ii. The continued treatment of China PR as a non-market economy is without legal basis. The provision of Article 15(a) of China's Accession Protocol permitting the use of surrogate country methodology expired on 11th December 2016. Post expiry, WTO Members, including India, are required to determine normal value in accordance with Article 2 of the WTO Anti-Dumping Agreement using domestic prices and costs of Chinese producers or verified exporter data. A mechanical application of Para 7 of Annexure I without examining exporter data would be inconsistent with India's WTO obligations. The Authority is requested to examine the actual cost and price information submitted by the responding exporters and determine normal value on that basis.
 - iii. Linhai Huanan Chemical Co., Ltd. has fully cooperated in the present investigation and has provided complete information. However, the Authority has determined the weighted average export price by combining verified export price for the cooperating portion with facts-available export price for the volume exported through unrelated non-cooperating traders over whom the producer/exporter exercises no control. The Anti-Dumping Rules do not prescribe participation of every trader in the export chain as a mandatory pre-condition for determination of an individual dumping margin. The application of facts available has artificially inflated both the dumping margin and the injury margin

- disclosed. The Authority is requested to determine the export price and dumping margin solely on the basis of verified information submitted by the cooperating entities.
- iv. There is no demonstrable causal link between the alleged dumped imports from China PR and the financial losses claimed by the domestic industry. The domestic industry was incurring significant losses in 2021-22, a period when import volumes were at their lowest. Conversely, in the POI, when import volumes were at their highest, the per-unit losses of the domestic industry reduced by more than 40% compared to the base year. The rate of decline in the landed price of imports is lower than the rate of decline in the cost of sales of the domestic industry. This establishes that imports are not exerting price pressure on the domestic industry.
 - v. The Authority has found that price undercutting from imports from China PR is negative during the POI, establishing that the landed price of imports was higher than the selling price of the domestic industry. In such circumstances, imports cannot be said to have suppressed or depressed domestic prices or prevented the domestic industry from increasing its prices. A finding of price injury in these circumstances is inconsistent with the facts on record.
 - vi. The economic parameters examined by the Authority do not establish material injury. The data on record shows improvement in key parameters during the POI, including production, sales, capacity utilization, productivity, employment, wages, and market share. Profitability indicators such as Profit Before Tax, Cash Profit, and Return on Capital Employed have also shown improvement during the POI compared to the previous year. When most economic parameters show improvement, a finding of material injury is not justified.
 - vii. The adoption of a uniform 22% pre-tax return on average capital employed for determination of the Non-Injurious Price is excessive and inconsistent with the requirement of "reasonable return" under Annexure III of the Anti-Dumping Rules. Capital employed includes a debt component that already attracts interest cost. Applying a uniform 22% return on the entire capital base results in an artificially inflated return on equity, which inflates the Non-Injurious Price and distorts the injury margin determination.
 - viii. The ongoing Russia-Ukraine conflict has resulted in significant disruptions across global trade and supply chains, adversely impacting availability of raw materials, increasing energy and logistics costs, and creating uncertainties in international transportation. These developments have had a direct bearing on the production, pricing, and supply of chemical intermediates including Bromo OTBN, and constitute a relevant non-attribution factor that must be examined by the Authority while assessing injury, causal link, and public interest.
 - ix. The injury suffered by the domestic industry, if any, is attributable to factors other than the alleged dumped imports from China PR. The domestic industry's own Annual Report for 2024-25 identifies supply chain constraints, geopolitical tensions, trade policy uncertainties, changing tariff rates, and persistent inventory de-stocking as the primary challenges. These factors are entirely unrelated to the alleged dumping and must be considered as the principal causes of any injury suffered.
 - x. Imposition of anti-dumping duties on imports of Bromo OTBN would be contrary to public interest. The domestic industry has not demonstrated sufficient capacity to reliably meet the entire domestic demand. Imposition of duties would increase input costs for Indian pharmaceutical manufacturers, adversely affect their competitiveness, and create supply-chain risks in a sector directly linked to public health.

K.2 Submissions by the Domestic Industry

112. The following comments on the Disclosure Statement have been filed by the domestic industry.

- i. The domestic industry concurs with the views expressed by the Authority in the Disclosure Statement and requests the Authority to uphold such views in the final findings.
- ii. As regards the observation of the Authority in paras 27 and 28 of the Disclosure Statement regarding the eligibility of CCCMHPIE to be treated as an eligible interested party, the issue is a legal issue and not a dispute on facts. It is settled that issues relating to the validity of a legal act can be questioned at any stage and cannot be treated as time barred. Unless the interested parties or CCCMHPIE can establish the standing of the said party in the investigation through their comments, CCCMHPIE should not be treated as an eligible interested party.
- iii. As regards the computation of the impact of anti-dumping duties on users as set out in the Disclosure Statement, the impact has been computed based on the impact on final consumers (patients). The impact on downstream users of the subject goods would be even more minuscule and can be easily absorbed by them. While the impact on downstream users shall be minuscule, the same

shall provide significant relief to the domestic producers of the subject goods, essentially reviving the ailing domestic industry.

- iv. As regards the observation of the Authority regarding the existence of a demand-supply gap, there is in fact no demand-supply gap for the subject goods in India. The two other existing producers have almost similar capacities as the domestic industry. Further, other manufacturers who have stopped production and producers of bromination-based drugs such as Aarti Industries could easily manufacture the subject goods, but for the low-priced dumped imports.
- v. As regards the observation of the Authority that the domestic industry has not substantiated its submission regarding curtailment or stoppage of production by other Indian producers, the production-related details of every producer are confidential and were not in the possession of the domestic industry. However, the submission was made in written submissions duly circulated to all interested parties, and no interested party has disputed it. The domestic industry also submits that a producer of the subject goods, namely Saurav Chemicals, has made a submission before the Authority. While such submission has not been taken on record due to procedural issues, the data/information contained therein may be used to validate the domestic industry's submission.
- vi. The domestic industry requests the Authority to recommend imposition of anti-dumping duties on a fixed basis. Significant fluctuation in the prices of the subject goods over the injury investigation period indicates that a reference price-based duty may not be effective against the imports of the subject goods.
- vii. The domestic industry requests the Authority to uphold its findings with respect to dumping by the Chinese exporters causing injury to the domestic industry, and to recommend the imposition of anti-dumping duties at the earliest to protect the domestic industry from dumped and injurious imports from China PR.

K.3 Examination by the Authority

113. The Authority has examined the post-disclosure submissions made by the interested parties. It is observed that the majority of these submissions are reiterations of arguments and contentions that have already been examined and addressed to the extent deemed necessary in the relevant paragraphs of these final findings. For the sake of brevity, the Authority has refrained from repeating responses to such submissions in this post-disclosure examination. However, new submissions raised for the first time in post-disclosure comments, as well as those previously addressed but deemed necessary to examine further, are addressed hereunder.
114. With regard to the submission of Linhai Group that the treatment of China PR as a non-market economy is without legal basis and that Article 15(a) of China's Accession Protocol permitting use of surrogate country methodology expired on 11th December 2016, the Authority notes that this contention is not supported by the legal position as applicable. The Authority's determination of normal value is based on Article 15(a)(i) of China's Accession Protocol read with Para 7 of Annexure I to the Anti-Dumping Rules, which constitutes the legally applicable methodology in the present investigation. No evidence has been placed on record by any interested party to warrant application of the first or second methods for determination of normal value. The Authority finds no merit in this contention.
115. With regard to the submission of Linhai Group that the application of facts available for the portion of exports made through non-participating unrelated traders is unwarranted and has artificially inflated the dumping margin and injury margin, the Authority notes that the application of facts available for the non-cooperating portion is in accordance with the provisions of the Anti-Dumping Rules. Linhai Huanan's export price has been determined as a weighted average combining verified data for the cooperating portion with facts-available data for the non-cooperating portion, consistent with the Authority's established practice. The Authority finds no merit in this submission.
116. With regard to the contention that volume parameters of the domestic industry show substantial improvement and that this negates a finding of material injury, the Authority reiterates that an injury determination under the Anti-Dumping Rules requires an objective examination of all relevant economic factors. The domestic industry has remained continuously in losses throughout the injury investigation period including the POI, has been unable to realize prices commensurate with its cost of production due to the price-suppressing and price-depressing effect of dumped imports, and has been unable to access market share consistent with its production capacity. Improvement in certain volume parameters in the POI does not, in the overall assessment, negate the finding of material injury.
117. With regard to the submission that there is no causal link between the alleged dumped imports and the financial performance of the domestic industry, the Authority notes that causal link analysis examines the relationship between the price at which dumped imports enter the market and the pricing and profitability of the domestic industry, not merely the volume trajectory of imports. The landed value of dumped imports from China PR has

throughout the injury investigation period remained materially below the cost of sales of the domestic industry, compelling it to sell below cost and incur continuous losses. The direct correlation between the gap in landed value versus cost of production and the per-unit losses of the domestic industry has been established in the relevant paragraphs of these final findings.

118. With regard to the submission that the injury, if any, is attributable to other factors including supply chain disruptions, geopolitical tensions, raw material price corrections, and the Russia-Ukraine conflict, the Authority has conducted a non-attribution analysis in the relevant paragraphs of these final findings and has examined all factors other than dumped imports that could have caused injury. The raw material prices of the domestic industry and the landed price of imports have moved in the same direction over the injury period. However, the landed value of imports has throughout the period remained materially below the cost of production of the domestic industry. The claimed other factors do not provide any basis for concluding that injury caused to the domestic industry is not attributable to the dumped imports.
119. With regard to the submission of Linhai Group that the ROCE of 22% adopted for computation of the Non-Injurious Price is excessive, the Authority notes that a pre-tax return of 22% on average capital employed is the practice under Annexure III of the Anti-Dumping Rules, as amended, applied consistently across investigations. The Authority finds no merit in this submission.
120. With regard to the contention that if any measure is recommended, it should be in the form of a reference price, the Authority notes that the domestic industry has specifically requested recommendation of duties on a fixed basis in view of significant price fluctuations of the subject goods observed during the injury investigation period. The Authority has considered all relevant submissions on the form of measure in arriving at its recommendation.
121. With regard to the submissions regarding public interest, the Authority reiterates its findings recorded in the relevant paragraphs of these final findings. The impact of anti-dumping duties on downstream pharmaceutical users and end-consumers has been quantified and found to be insignificant. No user or importer has participated in the present investigation and no quantified evidence of material adverse impact on downstream users has been placed on record. The downstream APIs manufactured using the subject goods are subject to price control measures of the Government of India. The Authority remains of the view that the imposition of an anti-dumping measure in the present investigation is consistent with the wider public interest, including the interest of maintaining a viable domestic manufacturing base for an essential pharmaceutical intermediate. The Authority finds no merit in the submissions seeking non-imposition of duty on public interest grounds.
122. With regard to the submission of the domestic industry regarding the eligibility of CCCMHPIE as an interested party, this question has been considered and addressed in the relevant paragraphs of these final findings.
123. With regard to the submission of the domestic industry that there is no demand-supply gap, the Authority notes that apart from the domestic industry, there are other Indian producers of the subject goods as well. The imposition of an anti-dumping measure will correct the price distortion caused by dumped imports and restore fair competition in the Indian market. Any residual gap between domestic supply and demand can continue to be met through imports entering at fair prices.

L. CONCLUSION

124. Having regard to the contentions raised, information provided, and submissions made by the interested parties and facts available before the Authority, as recorded in the above findings, and on the basis of the above analysis of dumping, injury, causal link, and public interest, the Authority concludes as follows:
 - i. The product under consideration is 4-(Bromomethyl)-2'-cyanobiphenyl, also known as Bromo OTBN. The like article produced by the domestic industry is like or similar to the product under consideration in all material respects.
 - ii. M/s Neogen Chemicals Limited constitutes the domestic industry within the meaning of Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules, and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3).
 - iii. The dumping margin for cooperating producers/exporters from China PR is positive and significantly above the de minimis threshold. Imports from China PR have entered the Indian market at significantly dumped prices.
 - iv. The imports of the subject goods from China PR have increased in absolute terms over the injury investigation period, were at their highest level during the POI, and command a dominant share of Indian demand.
 - v. The price undercutting is negative in the POI. The domestic industry has placed on record evidence indicating that it has been compelled to reduce its prices in response to customer pressure to match import prices. The landed value of imports has throughout the injury investigation period remained

materially below the cost of production of the domestic industry, causing price suppression and depression.

- vi. The domestic industry has suffered material injury. The domestic industry has been continuously incurring losses, with negative cash profits and negative return on capital employed, throughout the injury investigation period including the POI. The injury margin for cooperating producers/exporters from China PR is positive and significant.
- vii. There is a causal link between the dumped imports from China PR and the material injury suffered by the domestic industry. The Authority has examined all other known factors that may have caused injury and concluded that they do not negate the causal link between the dumped imports and the injury.
- viii. The imposition of anti-dumping duty is consistent with the wider public interest, including the interest of maintaining a viable domestic manufacturing base for an essential pharmaceutical intermediate where global supply is highly concentrated.

M. RECOMMENDATION

125. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the domestic industry, exporters, importers, and other interested parties to provide positive information on the aspect of dumping, injury, and causal link. Having initiated and conducted the investigation into dumping, injury, and causal link in terms of the provisions laid down under the Anti-Dumping Rules, the Authority is of the view that imposition of duty is required to offset dumping and injury. Therefore, the Authority considers it necessary and recommends the imposition of anti-dumping duty on imports of the subject goods from China PR.

126. Having regard to the lesser duty rule followed by the Authority, the Authority recommends the imposition of an anti-dumping duty equal to the lesser of the margin of dumping and the margin of injury, so as to remove the injury to the domestic industry. Accordingly, the Authority recommends imposition of anti-dumping duty on imports of the subject goods, originating in or exported from China PR, for a period of five (5) years from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government, equal to the amount mentioned in Col. 7 of the duty table below.

Duty Table

S No.	HS Code	Description	Country of Origin	Country of Export	Producer	Amount	Unit	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	29269000, 29339990, 29332990, 29420090, and 29152990	4 (Bromomethyl)- 2'-cyanobiphenyl (Bromo OTBN)	China PR	Any country including China PR	Yancheng City DongGang Pharmaceutical Development Co., Ltd	5,089	MT	USD
2.	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Linhai Huanan Chemical Co., Ltd.	5,500	MT	USD
3.	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Zhejiang Tianyu Pharmaceutical Co., Ltd.	5,440	MT	USD

4.	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Any producer other than S No. 1 to 3	6,305	MT	USD
5.	-do-	-do-	Any country other than China PR	China PR	Any	6,305	MT	USD

Note - The application of the individual duty rates specified for the producers mentioned in the above shall be conditional upon presentation to customs authorities of a valid commercial invoice, on which shall appear a declaration dated and signed by an official of the entity issuing such invoice, identified by his/her name and function, drafted as follows:

“I, the undersigned, certify that the (volume) of (product concerned) sold for export to India covered by this invoice was manufactured by (producer name and address) in the (name of country). I declare that the information provided in this invoice is complete and correct.’ If no such invoice is presented, the duty applicable to all other producers shall apply. This requirement is without prejudice to the verification procedures independently undertaken by the Customs authorities under the applicable customs law and regulations.”

A N. FURTHER PROCEDURE

127. An appeal against the determination of the Designated Authority in these final findings shall lie before the Custom, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Act/Rules.

AMITABH KUMAR, Designated Authority